बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 304

अवैध पलायन पर नजर रखे सरकार

अमेरिका का एक सैन्य विमान वहां अवैध रूप से रहने वाले 100 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को लेकर बुधवार को अमृतसर पहुंचा। इससे अवैध आव्रजन पर अमेरिका का रुख एकदम स्पष्ट हो गया। खबर हैं कि इनमें से कई लोगों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी थीं। अवैध रूप से रहने वाले भारतीयों को इस तरह भेजकर अमेरिकी सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान के दौरान डॉनल्ड ट्रंप ने अवैध रूप से रहने वालों को वापस भेजने का वादा किया था और वह अब वादा पूरा कर रहे हैं। इस काम के लिए सेना के विमान का इस्तेमाल शायद यह दिखाने के लिए हुआ है कि वह कितने गंभीर हैं और हथकड़ी में लोगों को देखकर अमेरिका में उनके समर्थक जरूर खुश हुए होंगे। विकासशील एवं पिछड़े देशों से लोगों का अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचना नई बात नहीं है और अमेरिका ऐसे लोगों को उनके देश भेजता भी रहा है मगर इसके लिए सैन्य विमान का इस्तेमाल एकदम नई बात है। आम वाणिज्यिक विमानों के मुकाबले सैन्य विमान उड़ाना खर्चीला होता है और उनका इस्तेमाल कर अमेरिका दिखाना चाहता है कि अवैध आव्रजन रोकने के लिए वह कितना गंभीर है।

अमेरिका में 18,000 से अवैध भारतीय पहचाने जा चुके हैं और उन्हें जल्द ही वापस भेजा जाएगा। लेकिन इन हालात में दो बातों पर तत्काल ध्यान जाना चाहिए। पहली, अमेरिका से आया विमान दिल्ली की जगह अमृतसर में क्यों उतरने दिया गया। अगर दिल्ली में केंद्र सरकार की एजेंसियां वहां से भेजे गए लोगों के बयान दर्ज करतीं तो बेहतर होता। दूसरी, इन लोगों को बिना देर किए स्वीकार कर भारत ने सही कदम उठाया है मगर विमान में इन लोगों के साथ जो सलूक किया गया उस पर भारत को अमेरिकी सरकार के सामने आपत्ति जरूर दर्ज करानी चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को संसद में बताया कि अमेरिका ने इस पूरे मामले में सामान्य नियमों और प्रक्रिया का ही पालन किया है। किंतु भारत ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत कर रहा है ताकि आगे वहां से लौटाए जाने वाले भारतीयों के साथ अनुचित व्यवहार नहीं हो। चूंकि वहां अवैध तरीके से रह रहे लोगों को भारत भेजने का सिलसिला लंबे समय तक चलेगा, इसलिए भारत सरकार को इसे सहजता से पूरा करने के लिए अमेरिका के साथ बात करनी चाहिए। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार को भी विमान आदि भेजकर मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इससे यह संदेश भी जाएगा कि किसी देश में अवैध तरीके से घुसने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भारत सरकार दूसरे देशों से भी अपने ऐसे नागरिकों को वापस लाने के लिए वहां की सरकारों के साथ सहयोग कर सकती है।

इसके साथ ही अवैध पलायन पर भी पर्याप्त ध्यान दिए जाने की जरूरत है। भारत से बड़ी संख्या में लोग विदेश जा रहे हैं। भारत जैसे बड़े एवं विकासशील देश में कुछ नागरिक बेहतर जीवन जीने के लिए विकसित देश में बसना चाहते हों तो गलत नहीं है। बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भी पढ़ने के लिए अमेरिका जैसे विकसित देश में जाते हैं और बाद में बेहतर अवसर मिलने पर वहीं रह जाते हैं। उदाहरण के लिए सिलिकन वैली में भारतीयों की भारी तादाद है, जो अच्छी तरह रह रहे हैं। मगर अमेरिका इस समय भारत से गए जिन लोगों को वापस भेज रहा है वे इन लोगों की श्रेणियों में नहीं आते हैं। ये लोग तो अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचने की ख्वाहिश में अपनी जान जोखिम में डालने से भी नहीं हिचकते। बताया जा रहा है कि कई लोग भारत के संपन्न राज्यों से हैं और अमेरिका पहुंचने के लिए उन्होंने बिचौलियों को मुंहमांगी रकम भी दी होगी। ऐसा जोखिम उठाने की इकलौती वजह देश में अवसरों की कमी हो सकती है। लिहाजा भारत को तेज आर्थिक विकास के लिए आर्थिक अवसर तैयार करने पर जोर देना चाहिए। सरकार को ऐसे लोगों एवं तंत्रों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो भारतीय नागरिकों को दूसरे देशों में अवैध तरीके से घुसने में मदद करते हैं। ऐसे लोग न केवल भारतीय नागरिकों की जान जोखिम में डालते हैं बल्कि दूसरे देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध भी खराब करते हैं।

किरण सिन्हा

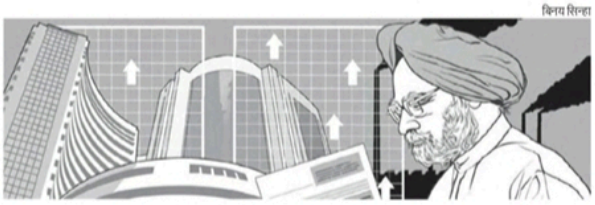

भारत के वित्तीय बाजार के शिल्पकार मनमोहन

मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए कई सुधार किए, जिनमें भारत के प्रतिभूति बाजारों का कायाकल्प सबसे अहम है। बता रहे हैं के पी कृष्णन

दिवंगत डॉ. मनमोहन सिंह को भारत में बुनियादी बदलाव करने वाले योगदान के लिए सराहा जाता है। उन्होंने संसाधनों को असली अर्थव्यवस्था में लाने में आधुनिक प्रतिभूति बाजार अहम भूमिका समझ ली थी, जिसके बाद उन्होंने इस बाजार का खाका तैयार किया और इसकी नींव डाली। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) का गठन इसका सबसे अहम और मुश्किल हिस्सा था, लेकिन उनका योगदान यहीं तक सीमित नहीं था। वास्तव में उन्हें आधुनिक बाजार के लिए जरूरी संस्थाओं, कानूनों एवं मददगार माहौल के साथ पूरा तंत्र तैयार करने का श्रेय जाता है। अमेरिका के साथ बाद में हुए परमाणु समझौते की तरह यह भी मामूली सुधार नहीं था बल्कि बुनियादी और निर्णायक बदलाव लाने वाला था।

अगर तकनीकी कंपनियों सहित कई भारतीय कंपनियां इस साल आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) का रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं तो यह 1990 में हुई शुरुआत का नतीजा है। उस वक्त भारतीय उद्योग अधिक संपत्तियों वाली इंजीनियरिंग कंपनियों से हटकर अधिक मुनाफे और कम संपत्तियों वाले सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र की ओर कदम बढ़ा रहा था, जिसमें मानव प्रतिभा का ज्यादा इस्तेमाल होता था। यह क्षेत्र कर्ज के बजाय जोखिम वाली पूंजी पर ज्यादा निर्भर था। क्लीर वित्त मंत्री डॉ सिंह ने हर्षद मेहता घोटाले के नतीजों का चतुराई से इस्तेमाल किया और संसद से प्रतिभूति बाजार नियामक के गठन की मंजूरी हासिल कर ली, जिसके पास अधिकार थे और जो सरकार से अलग रहकर काम करता था।

सेबी को कानून ने बाध्यकारी कायदे बनाने का अधिकार दिया। साथ ही इस काम के लिए सरकार की मंजूरी के बगैर ही माहिर लोगों को नियुक्त करने तथा जरूरी नीतियां बनाने का अधिकार भी दिया गया। सेबी को इसके लिए वित्तीय संसाधनों की जरूरत थी। इसके लिए सेबी को सरकार से कर्ज दिलाया गया और स्वायत्तता के साथ काम करने के लिए अपने अधीन आने वाली इकाइयों से शुल्क वसूलने तथा संसाधन तैयार करने का अधिकार भी दिया गया। यह सब कानून में स्पष्ट रूप से लिखा गया, जबकि इससे पहले सभी सरकारी संस्थाओं को सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती थी और उसके अनुदान पर निर्भर रहना पड़ता था।

इस तरह देश का पहला आधुनिक नियामक बना, जो भारत सरकार के विभागों से एकदम अलग था और जिसे अपने क्षेत्र के कायदे बनाने की ताकत कानून से मिली थी। 1992 के सेबी अधिनियम में यह सब नहीं था मगर यह जरूर बता दिया गया था कि किस दिशा में जाना है। डॉ सिंह ने 1995 में आधुनिक नियामक की सभी खासियत इस अधिनियम में जुड़वा दीं। मगर उन्होंने पहले से मौजूद नियामक पूंजी निर्गम नियंत्रक में सुधार की कोशिश नहीं की बल्कि पुराने झंझटों से मुक्त नया नियामक बना दिया।

इसके साथ ही डॉ सिंह और उनकी टीम ये संस्थाएं और बुनियादी ढांचा भी तैयार करने लगी, जो सेबी के नियामकीय दायरे में आने थे। पहला अहम हिस्सा स्टॉक एक्सचेंज थे। उस समय बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का जोर था, जिसे ब्रोकर चलाते थे और उन सुधारों के खिलाफ थे, जो उनके माकूल नहीं थे। बीएसई में सुधार की शुरुआती कोशिश के बाद उनकी टीम नया आधुनिक एक्सचेंज बनाने लगी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की शुरुआत आईडीबीआई ने स्टार्टअप की तरह की और स्पष्ट नियम बनाया गया कि इसमें ट्रेडिंग करने वाले स्वामित्व ढांचे में नहीं आ सकते। बेहतर कंपनी प्रशासन पक्का करने के लिए इसे लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत कराया गया। स्वामित्व का ढांचा भी आर्थिक प्रोत्साहन को ध्यान में रखकर बनाया गया ताकि जल्दी मुनाफा कमाने की हड़बड़ी न हो। इस तरह एनएसई पहला स्वतंत्र और कॉरपोरेट एक्सचेंज बन गया।

आपको 1990 के दशक के शुरुआती और बीच के साल तो याद होंगे, जब दूरसंचार और आईटी में एक तरह से क्रांति हो रही थी। उस क्रांति ने वित्तीय बाजारों समेत सभी बाजारों का मिजाज पूरी तरह बदल दिया। लगातार बढ़ रहे दूरसंचार बुनियादी ढांचे और आईटी के चतुराई भरे इस्तेमाल से एनएसई पूरे भारत का एक्सचेंज बन गया और क्षेत्रीय एक्सचेंजों (जिनमें ज्यादातर बहुत खराब तरीके से चलाए जा रहे थे) की कोई तुक ही नहीं रह गई। लेकिन इसके लिए जरूरी था कि कागजी शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक शेयरों में तब्दील किया जाए और पैसा भी ऑनलाइन भेजा जा सके। शेयरों को कागज से इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए कानून में परिवर्तन जरूरी था और पैसे को ऑनलाइन भेजने के लिए बैंकों का कंप्यूटरीकरण पहली शर्त थी।

इसके बाद डिपॉजिटरीज अधिनियम 1996 बनाया गया और हितों का टकराव रोकने के लिए आधुनिक एक्सचेंज जैसे ढांचे वाली डिपॉजिटरी बनाई गई। इसमें भी सेबी की ही तर्ज पर काम हुआ और पहले से मौजूद सरकारी उपक्रम में सुधार करने के बजाय नई बेहतर और आधुनिक डिपॉजिटरी बनाना सही माना गया। महमोहन सिंह के पास प्रतिभाओं को परखने वाली नजर थी, जिसकी मदद से उन्होंने राष्ट्र निर्माण की ख्वाहिश रखने वाले दूरदर्शी लोग जुटा लिए। ये लोग आईडीबीआई से आए थे। नई संस्थाएं बनाने के लिए डॉ सिंह ने इन लोगों के साथ उद्यमियों की तरह शानदार नई पहलें कीं और जोखिम भी लिए।

इसी के साथ सी रंगराजन के नेतृत्व में भारतीय रिजर्व बैंक भी धीरे-धीरे सरकारी बैंकों में कंप्यूटरीकरण की रफ्तार बढ़ा रहा था। जब राजनीतिक माहौल अनुकूल हुआ तब रिजर्व बैंक ने कई नए निजी बैंकों को लाइसेंस दे दिया, जो शुरू से ही तकनीक का जमकर इस्तेमाल कर रहे थे।

नियामक आ गया, बुनियादी ढांचा बन गया और संस्थाएं खड़ी हो गईं तब नीति निर्माताओं का ध्यान बाजार के भागीदारों की संख्या बढ़ाने तथा विविधता लाने पर गया, जो बाजारों के विकास के लिए जरूरी था। कानून में संशोधनों के जरिये विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय शेयर बाजारों में रकम लगाने की इजाजत दे दी गई। यह अहम कदम था क्योंकि उस समय भारत में ऐसे बड़े संस्थागत निवेशक नहीं थे, जिन्हें संपत्तियों के बजाय केवल कारोबारी योजनाएं तथा प्रतिभाएं दिखाने वाली कंपनियों के शेयरों को समझने और उनमें निवेश करने का अनुभव हो।

डॉ सिंह ने जो बुनियाद रखी उसी के बल पर भारत शेयर बाजारों की प्रगति मापने वाले आकार, गहराई, कायदे और दूसरे पैमानों पर इतना आगे पहुंच सका। छोटे-मोटे सुधार तो 1977 में ही शुरू हो चुके थे। 1991 में बड़ा बदलाव यह रहा कि विदेशियों पर शक करने की पुरानी आदत छोड़कर भारत ने दुनिया के लिए दरवाजे खोल दिए और वित्त से जुड़ी पुरानी शंकाएं किनारे रखकर उसी को भारतीय अर्थव्यवस्था की नई ऊंचाई का जरिया बना लिया गया।

अब इस प्रगति के बेपटरी होने का खतरा खड़ा हो गया है और देश के राजनीतिक नेतृत्व समेत हम सभी को साथ मिलकर खड़ा होना पड़ेगा ताकि हम एक बार फिर वैश्वीकरण और वित्त के अनुकूल रुख अपनाएं तथा वित्तीय व्यवस्था के लिए संस्थाएं बनाने पर ध्यान दें।

(लेखक आईसीपीपी में मानद सीनियर फेलो हैं और प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं)

मीडिया के सबसे बड़े दुश्मन नहीं हैं ईलॉन मस्क

इरीडियम 1990 के दशक की एक सैटेलाइट फोन कंपनी थी जो पृथ्वी की कक्षा में कम ऊंचाई पर चक्कर लगाने वाले दर्जनों उपग्रहों से जोड़ना चाहती थी। उसके ग्राहक तो बहुत कम बने मगर उसके विज्ञापन की एक पंक्ति लाखों लोगों को पसंद आई: 'भूगोल इतिहास है।' 1990 के दशक के आखिर में दफ्तर में मेरे एक साथी ने इरीडियम का यह विज्ञापन निकाला और इसमें से 'भूगोल' शब्द काट दिया। उसके ऊपर 'प्रिंट मीडिया' लिखकर उसने हमारे दफ्तर में चिपका दिया।

यह देखकर मैं बहुत घबरा गया। मेरा वह साथी बेहद तेजतर्रार रिपोर्टर था और उसकी लिखी खबरें पहले पृष्ठ पर छपती रहती थीं। उसके पास हर तरह के नीले रंग की कमीज थीं। दफ्तर में जब हम डेस्कटॉप के चौड़े कीबोर्ड पर काम करते थे उन दिनों वह लैपटॉप का इस्तेमाल करता था। लेकिन क्या उसे वाकई कोई खबर थी? प्रिंट मीडिया आज भी है, लेकिन इरीडियम इतिहास बन गई है। इस दौरान हमने यानी प्रिंट मीडिया ने टेलीविजन और इंटरनेट से जंग लड़ी, जिसका असर भी हुआ। सभी प्रिंट मीडिया कंपनियों ने इंटरनेट को अपना लिया है और वे हजारों वीडियो भी बना रही हैं। ज्यादातर की कमाई अब भी प्रिंट मीडिया से ही होती है मगर तकरीबन सारा नया निवेश डिजिटल मीडिया में ही हो रहा है चाहे उनसे कमाई कितनी भी कम क्यों न हो। असल में मीडिया में पेवॉल (यानी तय शुल्क अदा कर खबर या अखबार पढ़ना) का चलन अभी ज्यादा कामयाब नहीं हुआ है और डिजिटल पर विज्ञापन की कीमत प्रिंट जितनी नहीं है।

अब हम ईलॉन मस्क के खिलाफ हो गए हैं। मस्क की कुछ खूबियां हैं। वह मामूली शब्दों को भी मारक और अपमानजनक बना सकते हैं। जब वह 'लेगसी मीडिया' यानी 'घिसे-पिटे मीडिया' का नाम लेते हैं तो दुखती रग छिड़ जाती है। वह चौतरफा हमला करने से भी पीछे नहीं रहते, जैसा उन्होंने अपने दुलारे साइबरट्रक में विस्फोट के बाद मीडिया में आई खबरों पर किया था। लेकिन जब वह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के यूजर्स से कहते हैं कि यूजर्स ही मीडिया हैं तब सोचना पड़ता है कि यह बात वह वाकई गंभीरता से तो नहीं कह रहे। सोशल मीडिया ने हर किसी को मंच तो दिया है मगर कुछ लोग उसे भोंपू समझ बैठे हैं। हर किसी की राय होती है, जिसे जाहिर करने के लिए वह बेकरार रहता है। लेकिन कहते हैं कि हर किसी की राय तो हो सकती है मगर उसे सही साबित करने के लिए कुछ नहीं हो सकता। हर किसी के पास तथ्यों को जांचने के लिए फैक्ट-चेकिंग की सुविधा भी नहीं हो सकती। मेटा के मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक पर किसी अन्य कंपनी द्वारा चलाई जाने वाली फैक्ट-चेकिंग की सुविधा डॉनल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही एकाएक खत्म कर दी, जबकि फेसबुक उस समय गलत जानकारी देने के गंभीर आरोपों से जूझ रहा था।

अनदेखी

सुवीन सिन्हा

एक बार मैं किसी बड़े मंत्री के पास बैठा उन्हें साक्षात्कार के लिए मना रहा था। उन्होंने पूछा, 'सोशल मीडिया पर मेरे इतने (संख्या में कई शून्य लगे थे) फॉलोअर हैं। मैं अपनी बात सीधे पोस्ट कर सकता हूं और वह बिल्कुल वैसी ही आएगी, जैसी मैं चाहता हूं। फिर मैं आपको साक्षात्कार क्यों दूं?'

मैंने उनसे कहा कि इसीलिए तो साक्षात्कार देना चाहिए क्योंकि वह उनका लिखा हुआ नहीं होगा। कोई सवाल पूछेगा, चर्चा को एक रूप देगा, ऐसी दिशा में ले जाएगा, जहां उन लोगों को सही जानकारी मिलेगी, जो मंत्री से सीधे बात नहीं कर सकते। हॉलीवुड की उम्दा फिल्म 'अ फ्यू गुड मेन' में बेहतरीन काम करने वाले जैक निकलसन के संवाद 'यू वॉन्ट मी ऑन दैट वॉल, यू नीड मी ऑन दैट वॉल' की तर्ज पर मैंने कहा, 'आपको जरिया चाहिए और आप मुझे जरिया बनाना चाहते हैं।' मंत्री को बहुत तजुर्बा था और वह साक्षात्कार के लिए राजी होने से पहले मुझे आजमा रहे थे। सार्वजनिक चर्चा में सीधे अपने श्रोताओं से बात की जा सकती है मगर कभी-कभी इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, जैसा पिछले दिनों नए जमाने के एक उद्यमी को भुगतना पड़ा। उन्होंने एक्स पर ऐसे शख्स से पंगा ले लिया, जो चुटकुलों और लतीफों से रोजी-रोटी कमाता है यानी जिसके पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन समाचार कंपनियों को आगे की राह अब भी तलाशनी है।

इंटरनेट को अपनाने के साथ ही समाचार वेबसाइट ज्यादा से ज्यादा लोगों (ट्रैफिक) को खींचने की होड़ में लग गईं। वेबसाइट पर ज्यादा लोगों का आना अच्छा है। हममें से कई लोग उम्मीद करते हैं कि नई फिल्म देखने के लिए पहले हफ्ते में ही उमड़ी भीड़ की सुर्खी देखकर वेबसाइट पर आने वाले सरकार के खर्च की खबर भी पढ़कर जाएंगे। लेकिन वेबसाइट ज्यादा पाठक बटोरने के चक्कर में अखबारों से अलग दिखने लगी हैं। बेहतर पत्रकारिता से आई खबरों के मुकाबले हमेशा ही फिल्मों, क्रिकेट और सेलेब्रिटी की खबरें ज्यादा पढ़ी जाती हैं। पहले जब मैं अक्सर दिल्ली और पटना के बीच ट्रेन से सफर करता था तो इंडिया टुडे के मुकाबले स्टारडस्ट कई गुना ज्यादा बिकती थी।

लेकिन अच्छी खबरों के बारे में भी कुछ कहना चाहिए, जिसे एक खास जमात के पाठक और विज्ञापनदाता हमेशा पसंद करते रहे हैं। मुझे लगता है कि स्टारडस्ट के मुकाबले इंडिया टुडे में विज्ञापन छपवाना ज्यादा सम्मान की बात थी। अगर पत्रकारिता आधुनिक तरीकों को ज्यादा अपनाए तो मदद मिलेगी।

मैंने सुना है कि जब पहली बार कंप्यूटर आए तो कई पत्रकारों को उनसे हिचक थी और उन्हें लगता था कि टाइपराइटर पर बढ़िया लिखना ही असली हुनर है। अब कंप्यूटर का इस्तेमाल आम है। पांच साल बाद शायद आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी उतनी ही आम बात हो जाएगी। हो सकता है कि यकीन करना मुश्किल हो लेकिन डिजिटल और प्रिंट के बीच दीवार अखबारों के दफ्तरों में ही खिंच जाती है। कई साल से दोनों को साथ लाने की कोशिश हो रही हैं मगर नतीजे मिले-जुले ही हैं। कई रिपोर्टर ऐसी खबरें ऑनलाइन नहीं डालते, जो केवल उनके पास होती हैं। उन्हें डर रहता है कि अखबार छपते-छपते वही खबर कोई और भी छाप देगा। यहां तक कि कोई हल्की खबर देखकर हम लोग भी कहते हैं, 'इसको डिजिटल पर डाल दो।' मानो वेबसाइट किसी दूसरे ब्रांड और दूसरी कंपनी की है और इसके पाठक भी कोई और हैं।

अगर हम नई तकनीकों को अपना साथी मानने लगें, जो कहानी कहने का हमारा हुनर और तराश सकती हैं और पाठकों के सामने उस खबर को जीवंत बनाने के लिए हम केवल शब्दों के सहारे न रहें तो हम अपने पाठकों को ही नहीं बल्कि दर्शकों को भी बेहतर सामग्री दे सकते हैं। आपको नमूना चाहिए तो न्यूयॉर्क टाइम्स में कई साल पहले छपी खबर 'स्नो फॉल: द एक्लांच ऐट टनल क्रीक' देख सकते हैं। गूगल पर जाइए और देखिए कि नई तकनीक का इस्तेमाल कर खबर को बेहतरीन कैसे बनाया जा सकता है।

अच्छी पत्रकारिता का अपना रसूख और मकसद है। फिल्मों, क्रिकेट और सेलेब्रिटी की खबरें पढ़ने-देखने के लिए हमें विकल्पों की कमी नहीं चाहिए? किसी को तो जरिया या पुल बनना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी।

आपका पक्ष

अमेरिका से प्रवासियों को भारत भेजा जाना

अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय प्रवासियों को वापस भेजने का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। पिछले दिनों अमेरिका ने भारतीय प्रवासियों को हथकड़ी लगाकर अमेरिकी सेना के विमान से भारत भेजा है। जब भारत सरकार प्रवासियों को वापस लाने के लिए तैयार है अमेरिकी सरकार द्वारा ऐसा कदम उठाना उचित नहीं है। इस घटना पर भारत सरकार द्वारा अमेरिकी सरकार को सख्त चेतावनी देनी चाहिए। भारत सरकार ने इस घटना पर अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वे इस मामले की जांच करेंगे। अमेरिकी राजदूत को तलब करके इस घटना पर सख्त आपत्ति जताई जानी चाहिए। अमेरिका को प्रवासियों को सम्मान पूर्वक भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस घटना से सवाल उठता है कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता होगा। बहरहाल भारत सरकार को अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि वहां अवैध रूप से रह रहे भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं हो।

सुभाष बुझावन वाला, रतलाम

अमेरिका से अमृतसर भेजे गए गुजरात के अप्रवासी गुरुवार को अहमदाबाद हवाई अड्डा पहुंचे

ट्रंप की नीतियों से मिला-जुला असर होगा

ट्रंप जिद्दी प्रवृत्ति के हैं और वह अपने देश के हित में कदम उठा रहे हैं। भारत के अमेरिका से अच्छे संबंध हैं। अगर ट्रंप ने जैसे कि टैरिफ का ऐलान किया है और वे भारत पर भी कुछ प्रतिशत लागू करते हैं तो यह हमारी अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर डाल सकता है। ट्रंप और मोदी की नीति एक ही है जैसा कि शपथ से पूर्व ट्रंप कह चुके हैं कि वे विश्वशांति के पक्षधर हैं और दुनिया में चल रहे युद्ध व मतभेद को किसी तरह खत्म करना चाहते हैं। अतः हमारे देश पर यूं तो ट्रंप की नीतियों का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। फिर भी हम इसे मिला-जुला असर भी कह सकते हैं क्योंकि हम भी दुनिया के एक हिस्से हैं तब दुनिया के देशों के प्रभाव से अछूते नहीं रह सकते।

शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

जानलेवा बीमारी कैंसर से बचाव जरूरी

देश में जानलेवा बीमारी कैंसर के आंकड़े भयावह स्थिति पैदा कर डराते नजर आ रहे हैं। विगत 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस पर जारी आंकड़ों के मुताबिक देश दुनिया में कैंसर के मामले में मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर भोपाल है तथा पहले नंबर पर अहमदाबाद है। कैंसर का मुख्य कारण तंबाकू है तथा युवा वर्ग इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। हालांकि कैंसर विशेषज्ञ चिकित्सकों का मानना है की खानों का प्रदूषण भी इस जानलेवा बीमारी का एक कारण हो सकता है। अतः बच्चों को और युवावर्ग को नशे के सेवन से बचाना होगा। अत्यधिक बीड़ी सिगरेट और तंबाकू के सेवन से मुक्त कराना होगा। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का उपचार जितना पीड़ा दायक है उतना ही बहुत महंगा भी है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए तो कैंसर का इलाज उसे बरबाद देता है। नशीले पदार्थों के सेवन से परहेज और अन्य नशा का त्याग ही इसका उपचार है। युवावर्ग को नशा से बचाने के लिए कारगर रणनीति तैयार करनी चाहिए।

योगेश जोशी, बड़वाह

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

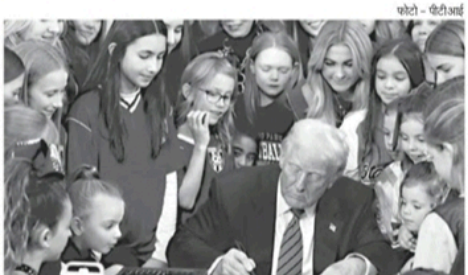

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने बुधवार को ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को लड़कियों और महिलाओं के खेलों में हिस्सा लेने से प्रतिबंधित करने वाले एक शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किए। ट्रंप ने कहा कि इस शासकीय आदेश के साथ महिलाओं के खेलों पर विवाद समाप्त हो गया है। इस अवसर पर पूर्व कॉलेजिएट तैराक रिले गेन्स सहित कई सांसद और महिला खिलाड़ी मौजूद थीं जो प्रतिबंध के समर्थन में थीं।

2000 वर्ष से भी पुराना संग्रंथ है भारत और इंडोनेशिया के बीच। इसका सबसे प्राचीन प्रमाण इंडोनेशिया के पूर्वी बोर्नियो स्थित तीसरी-चौथी शताब्दी ईस्वी के अभिलेखों में मिलता है।

डा. गौतम कुमार झा
असिस्टेंट प्रोफेसर, चीनी और दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

आजकल

भारत-इंडोनेशिया की साझा विरासत

गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबिआंतो ने कहा कि हाल ही में उन्होंने अपना डीएनए सीक्वेंसिंग टेस्ट करवाया, जिससे पता चला कि उनका डीएनए भारतीय है। सुबिआंतो के इस बयान के बाद से देश की राजनीति और विदेश नीति को लेकर एक बार फिर व्यापक बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों के लिए उनका यह कथन असहज और स्वीकार्य नहीं था। परंतु हमें यह भी समझना होगा कि भारत और इंडोनेशिया की विरासत साझा रही है

इंडोनेशिया में भी व्यापक रूप से लोकप्रिय है रामायण मंचन, जो दोनों देशों के बीच साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। फाइल

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबिआंतो द्वारा स्वयं के डीएनए का भारतीय होना बताए जाने के बाद से इस पर अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इसकी मुख्य वजह भारत की राजनीति और उसका आधुनिक इतिहास है, जिसे तथाकथित कान्वेंट शिक्षित इतिहासकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर राजनीतिक ध्रुवीकरण का साधन बना दिया गया। इसके परिणामस्वरूप भारतीय मूल्यों की पहचान धीरे-धीरे जनमानस की चेतना से धुंधली होती चली गई और वे केवल एक मध्य वर्ग मानसिकता का पर्याय बनकर रह गई।

ऐसे में जब एक मुस्लिम-बहुल राष्ट्र का राष्ट्रपति यह कहे कि उनके रक्त में भारतीय डीएनए प्रवाहित है, तो यह निश्चित रूप से एक पूर्वनिर्धारित मानसिकता के लिए असहज करने वाली बात होगी। चलिए भारतीय मूल्यों पर हम अभी विचार नहीं करेंगे। दक्षिण-पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश इंडोनेशिया अपने क्षेत्रफल, अर्थव्यवस्था और जनसंख्या के लिहाज से भारतीय ज्ञान परंपरा से गहरे रूप से प्रभावित रहा है, क्योंकि बौगोलिक दृष्टि से ये देश भारत से बहुत ही करीब है। छठी शताब्दी में यह भारतीय संस्कृति और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। भारतीय ज्ञान परंपरा ने वहां की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक धरोहर को इस हद तक प्रभावित किया कि वह आज भी अक्षुण्ण बनी हुई है और इस प्रभाव के प्रमाण इंडोनेशिया के साहित्य, कला, स्थापत्य और धार्मिक परंपराओं में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों का प्रभाव ऐसा है कि भारत भी इंडोनेशिया के मंचन प्रणाली के सामने बहुत पीछे है, क्योंकि वहां अभी भी छाया और कई अन्य प्रकार से इंडोनेशियाई राष्ट्रीय रेडियो और टीवी से हर एक सप्ताह रामायण और महाभारत का लाइव स्ट्रीमिंग होता है। जावा और बाली में तो अभी सर्वाधिक नाम संस्कृत से कहीं न कहीं जुड़ा होता है। आज भी जावा और बाली की काष्ठ कला पर अधिकांश कला भारतीय महाकाव्य को ही समर्पित होता है। रामायंड सागर निर्मित धारावाहिक रामायण हो या बीआर चोपड़ा की महाभारत, शायद ही कोई इंडोनेशियाई होगा जिसने इन्हें न देखा हो।

गौर करने वाली बात यह भी है कि 1950 के पहले गणतंत्र दिवस पर जब इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो भारत के मुख्य अतिथि थे, उन्होंने कहा था, 'हमारे पूर्वज भारत से आए हैं और हमारे रगों में भारतीय खून बहता है।' अब सवाल यह उठता है कि यदि हम भारतीय इस बक्तव्य की गहराई को न समझें तो इसमें हमारी गलती नहीं, क्योंकि हमारी मौलिक पहचान ही समय के साथ धुंधली होती चली गई है। आज इतिहास स्वयं को दोहरा रहा है। आज भी भारत और इंडोनेशिया के संबंध केवल कूटनीतिक सीमाओं तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और पहचान की गहराइयों तक जुड़े हुए हैं।

यह संबंध केवल ऐतिहासिक नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति और कूटनीति में भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। ऐसे में भारतीय विदेश नीति को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखने और रणनीतिक रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है, ताकि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और राजनयिक संबंध और अधिक मजबूत किए जा सके। यह महज आनुवंशिकी (जेनेटिक्स) का विषय नहीं, बल्कि दो महान देशों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंधों का प्रमाण भी है। यह बही रिश्ता है जो हिंद महासागर के पार बसने वाले संस्कृतियों को जोड़ता आया है, जो कभी व्यापार, हिंदू और बौद्ध प्रभाव, रामायण-महाभारत के प्रसार और सामाजिक समानताओं से समृद्ध था।

इतिहास के सुनहरे धागों से बना रिश्ता : भारत और इंडोनेशिया के संबंध केवल भौगोलिक निकटता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह एक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सभ्यतागत साझेदारी की कहानी है, जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्रसिद्ध इंडोलाजिस्ट बिलियम डेलरिंपल अपनी नवीनतम पुस्तक (द गोल्डेन रोड : हाऊ एंसिएंट इंडिया ट्रांसफार्म्ड द वर्ल्ड) में लिखते हैं कि छठी शताब्दी तक दक्षिण-पूर्व एशिया 'इंडीफीयर' का केंद्र था। भारतीय व्यापारियों का प्रभाव इतना व्यापक था कि वे स्थानीय कारीगरों को नया स्वरूप देने लगे। थाइलैंड और मलय प्रायद्वीप में तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के भारतीय शैली के आभूषणों के साँचे मिले हैं, जो इस बात का प्रमाण हैं कि मौर्य काल से ही भारतीय जौहरी इस क्षेत्र में सक्रिय थे।

भारत और इंडोनेशिया का संबंध कम से कम दो हजार वर्ष पुराना है। इसका सबसे प्राचीन प्रमाण पूर्वी बोर्नियो जो भारत से लगभग 4500 किलोमीटर दूर स्थित है, उसमें कुतेई राज्य के यूप अभिलेखों (चौथी-पांचवीं शताब्दी ईस्वी) में मिलता है। ये अभिलेख इंडोनेशिया के सबसे पुराने संस्कृत अभिलेख माने जाते हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं कि वहां वैदिक परंपराओं और अनुष्ठानों की गहरी जड़ें स्थापित थीं। इन शिलालेखों में राजा मूलवर्मन का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने वैदिक रीति-रिवाजों के अनुसार अनुष्ठान किए और ब्राह्मणों को दान दिया। यह केवल धार्मिक प्रभाव का संकेत नहीं है, बल्कि यह भारत-इंडोनेशिया के सांस्कृतिक आदान-प्रदान की एक सशक्त मिसाल है।

सांस्कृतिक सेतु का ऐतिहासिक प्रमाण : भारत और इंडोनेशिया के गहरे संबंधों की सबसे पुरानी ऐतिहासिक पुष्टि यूप अभिलेखों में मिलती है, जो न केवल संस्कृत भाषा के प्राचीनतम प्रमाणों में से एक हैं, बल्कि इंडोनेशिया में वैदिक परंपराओं और भारतीय संस्कृति की गहरी जड़ों का भी संकेत देते हैं। इंडोनेशिया में मिले ये अभिलेख संस्कृत में लिखे गए हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि चौथी-पांचवीं शताब्दी ईस्वी तक यहां संस्कृत भाषा, वैदिक ज्ञान और अनुष्ठानों का प्रभाव था। यह प्रमाणित करता है कि इस क्षेत्र में न केवल भारतीय भाषा, बल्कि भारतीय जीवनशैली भी समाहित थी।

संस्कृति, व्यापार और विचारधारा का आदान-प्रदान : भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध केवल धार्मिक प्रभाव तक सीमित नहीं थे, बल्कि इसमें व्यापार, कला और भाषा का भी योगदान था। दक्षिण और पूर्वी भारत से ब्राह्मणों, व्यापारियों और साधुओं का यहां आना-जाना लगा रहता था, जिससे वैदिक परंपराएं और भारतीय दर्शन इन क्षेत्रों में फैलता गया। इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ-साथ वैदिक और सनातनी परंपराओं का भी उत्कर्ष हुआ। यह देखना अद्भुत है कि बौद्ध और सनातन परंपराओं ने सह-अस्तित्व और सद्भाव के साथ आगे बढ़ते हुए एक नई 'शैव-बौद्ध परंपरा' को जन्म दिया, जो भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं और नहीं देखी जाती। 19वीं शताब्दी में तो एक शिलालेख यह कह रहा है कि सनातन धर्म समाज में शांति और समृद्धि स्थापित करने के लिए के लिए औषधि के सामान है।

इंडोनेशिया में भारतीय डीएनए के प्रमाण

डीएनए कोडिंग जीवों की आनुवंशिक संरचना को समझने की एक प्रक्रिया है, जिससे यह पता लगाया जाता है कि किसी व्यक्ति या समूह का आनुवंशिक इतिहास क्या है। डीएनए परीक्षण यह स्पष्ट कर सकता है कि किसी व्यक्ति का वंश किस क्षेत्र, जातीय समुदाय या ऐतिहासिक सभ्यता से जुड़ा हुआ है। डीएनए में चार प्रमुख नाइट्रोजन बेस होते हैं : एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। यह चार बेस जोड़ों (पेयर्स) में व्यवस्थित रहते हैं और आनुवंशिक जानकारी को कूटबद्ध (इनकोड) करते हैं। डीएनए विश्लेषण से यह संभव हो गया है कि हम अपने पूर्वजों की उत्पत्ति और स्थानांतरण (माइग्रेशन) का पता लगा सकें।

भारतीय संस्कृति से संबंध : भारत और इंडोनेशिया के बीच मैरिटाइम सिल्क रोड के माध्यम से व्यापार और प्रकास हुआ। संस्कृत शिलालेख (चौथी-पांचवीं शताब्दी के यूपा शिलालेख) और बाल्मीकि रामायण में इंडोनेशिया का उल्लेख मिलता है। रामायण और महाभारत के स्थानीय संस्करणों जैसे काकावीन रामायण, पुरानी सुंडानी रामायण, रामकेन और हिकायत सेरी राम में बाल्मीकि रामायण के जीवंत प्रवाह को वहां की कठपुतली, नृत्य और कई कलाकृतियों के माध्यम से देखा जा सकता है।

प्रबोवो सुबियांतो का भारतीय संस्कृति से जुड़ाव : सुबियांतो जावा के गौबॉगेन क्षेत्र से आते हैं, जो प्राचीन हिंदू-बौद्ध साम्राज्यों का केंद्र था। वे भारतीय संगीत, योग और आध्यात्मिक परंपराओं में रुचि रखते हैं। गीता का श्लोक अक्सर अपने बक्तव्यों में उद्धृत करते हैं। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी भारतीय संस्कृति से प्रभावित रही है। डीएनए परीक्षणों से यह प्रमाणित हुआ है कि भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण-पूर्व एशिया के लोगों के आनुवंशिक मार्कर समान हैं। भारत और इंडोनेशिया के लोगों में आस्ट्रोनेशियन, द्रविड़, और इंडो-आर्यन जीन के मिश्रण के प्रमाण मिले हैं। इंडोनेशियाई लोगों में क्वाई-डीएनए हापलोग्रुप ओ एवं हापलोग्रुप आर 1ए पाया जाता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में भी प्रचलित है।

ऐसे में प्रबोवो का हालिया बयान भारत और इंडोनेशिया के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में सहायक हो सकता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह समरिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। आर्थिक दृष्टि से दोनों देशों के बीच व्यापार को और विकसित किया जा सकता है। सांस्कृतिक दृष्टि से, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों (आयुर्वेद और जामू) का संयुक्त अनुसंधान किया जा सकता है। जामू का अर्थ इंडोनेशिया के पारंपरिक औषधि सिस्टम है।

ऐसे में भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को केवल अतीत की कड़ी के रूप में नहीं, बल्कि भविष्य की साझेदारी के रूप में भी देखा जाना चाहिए। दोनों देशों का साझा इतिहास और आनुवंशिकी यह दर्शाते हैं कि वे एक वैश्विक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में आगे बढ़ सकते हैं।

(डा. गौतम कुमार झा)

खरी-खरी

टैक्स ले लो सरकार

मनोज वार्ष्णेय

केंद्र सरकार ने जैसे ही बजट पेश किया और टैक्स से आम आदमी को राहत दी, वैसे ही आम आदमी का मन खट्टा हो गया। उसे महसूस हुआ कि वह ठगा गया है। वह टैक्स देना चाहता था, लेकिन सरकार ने उसे टैक्स में बड़ी राहत दे दी और कहा कि तुम टैक्स देते हुए दुखी हो गए हो, इसलिए अब तुम्हें नाम मात्र का टैक्स देना है। आम आदमी इससे पहले कुछ सोच पाता उस पर एक और बज्रपात कर दिया। उसकी तनख्वाह जल्दी बढ़ जाए, इसके लिए एक कमेटी भी बना दी।

आम आदमी ने सोचा कि जब सरकार ने टैक्स कम किया है तो कुछ तो महंगाई भी बढ़ेगी। फिर वह भी बहती गंगा में डुबकी लगा लेगा, पर यह क्या सरकार ने पैसे बचाने के लिए कई रास्ते बता दिए। आम आदमी को एक बेरोजगार मिला, वह बोला- सरकार, टैक्स ले लो पर सरकारी नौकरी दिलवा दो। ज्यादा अच्छी नहीं तो इतनी बड़ी तो हो कि गर्व से कह सके मैं टैक्सपेयर हूं। मुझे लगता है सरकार ने जानकर मोबाइल और टीवी सस्ता किया है। वह जानती है कि आम आदमी टैक्स बचाने के लिए हजारों जतन करता है, लेकिन जब वह मोबाइल और टेलीविजन से समय पाएगा तभी तो नौकरी तलाशेगा।

सरकार ने मनरेगा, आंगनबाड़ी, संविदा, पीएम एमबाई, एनआर एलएएम, प्रधान-मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और स्वरोजगार आदि नामों से सैंकड़ों योजनाएं चला रखीं हैं। हर राज्य में दूसरी योजनाएं भी बेरोजगारों का इंतजार कर रही हैं, लेकिन हमें तो सरकारी नौकरी ही चाहिए। फिर इतनी रियायतें बस नौट कमाओ, बैंक में जमा करो या मौज मस्ती कर लो भी तो दे दी है। अब दुखी होते हो तो होते रहो।

आम आदमी जानता है कि सरकार उसकी हितैषी है, वह उसे इसलिए इतनी राहत दे रही है। परंतु आम आदमी भी देशप्रेमी है और वह भी चाहता है कि सरकार को अधिक से अधिक टैक्स दे, इसलिए उसे सरकारी नौकरी चाहिए। आशा है, जैसे टैक्स राहत का भंडारा हुआ है, वैसे ही नौकरियों का भी भंडारा होगा। और सरकार एक दिन फिर से टैक्स लगाने को मजबूर होगी। तब देखेंगे आम आदमी कैसे कहेगा, सरकार टैक्स ले लो।

X पोस्ट

कांग्रेस ने अंत में पूरा माहौल बदल दिया। संदीप दीक्षित के तेवर से दिल्ली कांग्रेस रीचार्ज हो गई। कांग्रेस 7-9 प्रतिशत वोट शेयर लेती दिख रही है। उसने 6-8 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। कांग्रेस को वोट का अर्थ 'वोट खराब' करने वाली छवि से पार्टी बाहर निकली है।

शिवम प्रताप सिंह@journalistspsc

ओबामा और बाइडन की सरकारों ने भी घुसपैठियों वापस उनके देश भेजे थे, लेकिन कमर्शियल उड़ानों में। ट्रंप महंगा पड़ने के बावजूद सैन्य जहाजों का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि उनके चुनाव का मुख्य मुद्दा घुसपैठियों को निकालने के लिए कड़े कदम उठाना था।

द कानपुरिया@Cawnporiaah

घुसपैठियों को अमेरिका से खदेड़े जाने पर

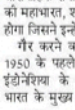

कुछ भारतीय अचंभित हैं। वे समझ ही नहीं पा रहे कि बिना पासपोर्ट, वीजा या किसी वैध दस्तावेज के घुस आए इन अवैध प्रवासियों को आखिर क्यों निर्वासित किया जा रहा है। भारत में तो ऐसे घुसपैठियों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार, सिलेंडर, मुफ्त बिजली और पानी तक दे दिया जाता है।

अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या दिल्ली चुनावों को लेकर एक्जिट पोल भरोसेमंद कहे जा सकते हैं?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या रोहित शर्मा की खराब फार्म भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय बन गई है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

भारी रसूर सीट पर दिखती है इक सीट,
दिल्ली से कम है नहीं मिल्कीपुर की हीट।
मिल्कीपुर की हीट पढ़ी थी सबकी बाहें,
क्या होगा परिणाम सभी की लगी निगाहें।
लोकसभा की जंग भले बीजेपी हारी,
चिंतित 'अखिलेश' उनकी अवढ़ी भारी!

प्रदीप सिंह
राज्य ब्यूरो प्रमुख, झारखंड

झारखंड डायरी

सधे कदमों से साध रहे राजनीतिक भविष्य

प्रत्युत्तर में झामुमो ने भावनात्मक कार्ड खेलते हुए सवाल उछाला- 'कब मिलेगा 1.36 लाख करोड़?' विधानसभा चुनाव के परिणाम से यह भी स्पष्ट है कि किसके मुद्दे ज्यादा कारगर रहे। दरअसल शानदार तरीके से सत्ता में वापसी के बाद हेमंत सोरेन ने उन मुद्दों पर और भी कड़ा एवं स्पष्ट रुख अख्तियार किया है, जो चुनाव के दौरान उनके कोर वोटरों को एकजुट करने के साथ-साथ समर्थक वर्ग का विस्तार करने में भी सहायक बने। भाजपा की प्रचार रणनीति के जवाब में झामुमो ने यह संदेश निचले स्तर पर पहुंचाने में अक्सर सफलता पाई कि केंद्र सरकार से राज्य को अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है।

इन मुद्दों को मजबूती से आगे बढ़ाने की यह बानगी है कि हेमंत सोरेन ने मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में ही यह निर्णय किया कि कोयला रायल्टी के बकाया का मसला अब अदालत में लेकर जाएंगे। इसके लिए वरिष्ठ विधि विशेषज्ञों का एक पैनल बनेगा। इसके साथ-साथ जमीन पर भी इसे लेकर लड़ाई आगे बढ़ेगी। दुमका में हेमंत सोरेन की घोषणा के यही मायने हैं कि वे अपने धारदार मुद्दों को और पैना करने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं करेंगे।

केंद्र से दो-दो हाथ करने की तैयारी के साथ-साथ हेमंत सोरेन ने राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए वातावरण बनाने की तैयारी नए सिरे से आरंभ की है। इस सिलसिले में वे पड़ोसी राज्य बंगाल में चल रहे ग्लोबल बिजनेस समिट में भाग लेने कोलकाता पहुंचने वाले दूसरे राज्यों के अकेले मुख्यमंत्री थे। इस अवसर का प्रयोग उन्होंने राज्य में निवेश के लिए उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए किया तो इसके नतीजे भी सामने आए। देश-दुनिया के अग्रणी उद्यमियों की मौजूदगी में हेमंत सोरेन ने राज्य के मजबूत पक्ष से अवगत कराते हुए परंपरागत सेक्टर से हटकर भी उद्योग लगाने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। इसके फलस्वरूप 26 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश राज्य में करने के लिए विभिन्न औद्योगिक घराने इच्छुक हैं। इससे 15 हजार से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

इन निवेश प्रस्तावों में वैसे प्रस्ताव भी शामिल हैं, जिनसे जुड़े समझौते पूर्व में राज्य सरकार कर चुकी है। विभिन्न जटिलताओं के कारण यह धरातल पर नहीं उतर पाया। उद्यमियों के साथ आमने-सामने की बात में सबसे ज्यादा शिकायतें जमीन संबंधी परेशानी की आईं तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उसका समाधान करने का भी भरोसा दिलाया। ऐसे प्रयासों से राज्य का औद्योगिक वातावरण बेहतर होगा तो अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी। नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट राज्य के लिए उत्साहजनक है, जिसमें आर्थिक सुधारों के विभिन्न सूचकांकों में राज्य का ओवरआल प्रदर्शन देशभर में चौथे स्थान पर है। पहले इसमें झारखंड की रैंकिंग 18वें पायदान पर थी। आर्थिक रैंकिंग में अप्रत्याशित सुधार से स्थिति मजबूत होगी तो इसका लाभ पिछड़ेपन और कुपोषण का आरंभ से दंश झेल रहे राज्य को होगा। जाहिर तौर पर ऐसी उपलब्धियां राज्य की छवि को और बेहतर करने में भी मददगार होगी। आर्थिक गतिविधियां जब तेज होंगी तो इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। भविष्य में राजनीतिक पकड़ बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि भावनात्मक और लोगों का समर्थन पाने के लिए उठाए जाने वाले मुद्दों के साथ आर्थिक विकास का सिलसिला भी जारी रहे। इस क्रम में चल रही कवायद के परिणाम के लिए अभी इंतजार करना होगा। अभी तक के प्रयासों से यह ऐसा लगा रहा है कि हेमंत सोरेन सधे कदमों से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

दुमका में सांसद नलिन सोरेन का अभिवादन करते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। (दाएं)। फाइल

मंथन

हृदय का स्पंदन है भारत नाम

सशक्त और विकसित भारत का संकल्प लेकर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। ऐसे में जन जन में भारत भाव जगाने की आवश्यकता है, जिसमें एक देश, एक नाम-भारत बहुत महत्वपूर्ण होगा

डा. वेदप्रकाश
असिस्टेंट प्रोफेसर, किरोड़ीमल कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

सृष्टि के पुरातन और सनातन देश का नाम भारत है। देसी-विदेशी अनेक विद्वान प्रमाणों के आधार पर कह चुके हैं कि भारत ज्ञान-विज्ञान, आचार, व्यवहार और विश्व सभ्यता का जन्मदाता है। यह केवल एक भौगोलिक क्षेत्र का नाम नहीं है, अपितु यह सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व धार्मिक विविधताओं में एकत्व का जीवंत रूप है। यह अध्यात्म के साथ-साथ दर्शन और विविध आयामी चिंतन का उत्कृष्ट केंद्र रहा है, यह जन जन के हृदय का स्पंदन है। वेद, उपनिषद एवं अनेक ग्रंथों में भारत नाम का वर्णन मिलता है।

भारतवर्ष की समूची ज्ञान परंपरा एवं साहित्य परंपरा में भी भारत नाम प्रमुखता से उल्लेखित है। पुराणों में भारत शब्द और उसका महत्व प्रतिपादित करते हुए लिखा है- गायंति देवाः किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमिभागे...। क्या यह भारत की महत्ता व पुरातनता का द्योतक नहीं है? स्वामी विवेकानंद ने अपने देश-विदेश के विभिन्न प्रवासों एवं अपनी आत्मकथा में स्थान स्थान पर भारत, भारतवर्ष व भारतवासी शब्दों का प्रयोग किया है- मेरा उद्देश्य यही है कि भारत में और भारत के बाहर मनुष्य जाति ने जो महत् चिंताराशि उद्भावन की है, उन सबका अति हीन, अति दरिद्र लोगों तक प्रचार करना होगा। श्री अरविंद ने भी भारतीय संस्कृति के आधार नामक अपनी पुस्तक में एवं अनेक स्थानों पर भारत और भारतीय शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने लिखा है- भारतीय सभ्यता एक ऐसी संस्कृति का बाह्य रूप एवं अभिव्यक्ति रही है जो मानव जाति की किसी भी ऐतिहासिक सभ्यता के समान ही महान है...।

इसी प्रकार मेरे सपनों का भारत-नामक पुस्तक में गांधी जी ने भी अनेक बार भारत, भारतवर्ष, भारतभूमि और भारतीय आदि शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने लिखा है- भारत अपने मूल स्वरूप में कर्मभूमि है, भोग भूमि नहीं। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद एवं रामधारी सिंह दिनकर जैसे अनेक कवियों ने अपनी रचनाओं में भिन्न-भिन्न स्थानों पर भारत, भारतवर्ष, भारत भूमि और भारतीय शब्दों का प्रयोग किया है। हमारा राष्ट्रगान भी जन गण के माध्यम से भारत भाग्य विधाता कहकर भारत का जय गान करता है।

औपनिवेशिक मानसिकता : ब्रिटिश शासकों ने भारत के लिए इंडिया और भारतवासियों के लिए इंडियन शब्द का प्रयोग किया। इसके पीछे के कारण और उनकी मानसिकता भी सर्वविदित है, क्या आज भी हम उस अपमानित करने की मानसिकता के गुलाम बने रहें? भारतवर्ष के संविधान में इंडिया देट इज भारत का प्रयोग औपनिवेशिक मानसिकता का प्रतीक है। यह मानसिकता आगे संविधान के भाग 17 राजभाषा के संदर्भ में भी सामने आती है, जहां संविधान में तो लिखा है- संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, लेकिन आगे प्रविधान भी बना दिया कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। आज भारत नाम और संघ की राजभाषा हिंदी इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। क्या इंडिया शब्द भारतवर्ष अथवा भारत को अनुभूति करवा सकता है? आज यह नितांत आवश्यक है कि इस विषय पर संसद में चर्चा करते हुए संशोधन किया जाए और कंस्टीट्यूशन आफ इंडिया के स्थान पर कंस्टीट्यूशन आफ भारत लिखा जाए।

हमें यह भी समझना होगा कि भारत नाम है और नाम का अनुवाद नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश नाम के किसी व्यक्ति का नाम अन्य किसी भी भाषा में लिपि बदलने पर भी सूर्य प्रकाश ही रहेगा, यदि हम उसे अंग्रेजी में सनलाइट कर देंगे तो अनर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार न इंडिया भारत हो सकता है और न ही भारत इंडिया। भारत के संविधान की उद्देशिका में स्पष्ट लिखा है- हम भारत के लोग, भारत को...। संविधान में अनेक स्थानों पर भारतवर्ष की संस्कृति एवं अन्य कई विशेषताओं को दर्शाते चित्रों का प्रयोग हुआ है। भारत नाम हमारी विरासत है। जी-20 सम्मेलन में राष्ट्रपति द्वारा विदेशी मेहमानों को दिए भोजन निमंत्रण में भी प्रेसिडेंट आफ इंडिया के स्थान पर प्रेसिडेंट आफ भारत लिखा गया, यह सराहनीय है।

अब सकारात्मक यह भी है कि एक देश, एक नाम-भारत, यह विषय चर्चा और चिंतन के केंद्र में आ रहा है। ध्यान रहे भारत नाम का विचार स्व के जागरण का विचार है। अतीत में विश्व के कई देशों ने अपने देश का नाम बदला है और भारत के कई प्रदेशों वह स्थानों के नाम भी बदले गए हैं, इस परिवर्तन में अनुचित क्या है? आज पूरा देश स्व जागरण की ओर है, औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति हेतु जन-जन संकल्पबद्ध हो रहा है।

नई दिल्ली में आयोजित जी-20 सम्मेलन में भारत नाम का ही उल्लेख किया गया। फाइल

दैनिक जागरण

प्रयासों की कूची से ही सपनों की तस्वीर साकार होती है

अमेरिकी अहंकार

अमेरिका ने अपने यहां अवैध तरीके से आए भारतीयों को जिस अनुचित तरीके से वापस भेजा, उस पर संसद में जो आपत्ति और आक्रोश जताया गया, वह उचित ही है। निःसंदेह अमेरिका अथवा अन्य किसी देश को यह अधिकार है कि वह अपने यहां अवैध तरीके से प्रवेश करने वालों को संबंधित देशों को वापस भेज दे, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं कि वह उन्हें हथकड़ी-बेड़ी लगाकर अमानवीय तरीके से भेजे। गत दिवस अमेरिका ने अपने सैन्य विमान से जिन 104 अवैध अप्रवासियों को भारत भेजा, उन्हें हवाई यात्रा के दौरान हथकड़ी पहनाए रखा और उनके पैरों को जंजीरों से बांधे रखा। आखिर यह करने की क्या जरूरत थी? माना कि इन भारतीयों ने अमेरिका में अनुचित तरीके से प्रवेश किया, लेकिन वे वहां से बेदखल किए जाते समय सामान्य गरिमा के तो हकदार थे ही। विमान में सवार होने के बाद न तो उनके प्रतिरोध की कोई आशंका थी और न ही कहीं भाग जाने की। अमेरिका से भारत की 20 घंटे से अधिक की लंबी यात्रा के बाद भी उन्हें ऐसे सैन्य विमान में भेजा गया, जिसमें शौचालय का इस्तेमाल करना भी कठिन था। इसको भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अवैध अप्रवासियों में महिलाएं और बच्चे भी थे। उनके साथ भी संवेदनहीनता दिखाई गई।

अमेरिका पहले भी भारत के अवैध अप्रवासियों को वापस भेजता रहा है। ओबामा और बाइडन के कार्यकाल में भी तमाम अवैध अप्रवासी वापस भेजे गए, लेकिन यह पहली बार है, जब उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ। भारत को इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। इसलिए और भी, क्योंकि वह अपने अवैध अप्रवासियों को वापस लेने की हामी भर चुका है। यह शर्म की बात है कि जो अमेरिका मानवाधिकारों संग अवैध अप्रवासियों के अधिकारों का भी चैंपियन बनता है, वह हमारे लोगों के साथ ऐसे व्यवहार करता दिखा, जैसे वे खूंखार अपराधी या आतंकी हों। यह ठीक है कि ट्रंप ने अवैध अप्रवासियों को वापस भेजने को चुनावी मुद्दा बनाया था और अब वह दिखाना चाहते हैं कि वह इस पर कोई रियायत नहीं बरतने वाले, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह भारत सरीखे सहयोगी एवं मित्र देश को असहज करने का काम करें। भारत को ट्रंप प्रशासन से यह भी कहना चाहिए कि अमेरिका में अवैध प्रवेश के आरोप में पकड़े गए भारतीयों को सैन्य विमान से भेजने की कोई जरूरत नहीं थी। यदि अमेरिका अवैध अप्रवासियों को वापस भेजने के अपने तौर-तरीके बदलने के लिए तैयार नहीं होता तो भारत को अपने विकल्प सोचने होंगे। अवैध अप्रवासियों के मसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति को अहंकार का भोंडा प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। यदि ट्रंप यह चाहते हैं कि भारत उनके मूर्ख पर संवेदनशीलता दिखाए, तो ऐसा ही उन्हें भारत के संदर्भ में भी करना होगा।

विकास को गति

औद्योगिक विकास की राह पर चल रहे प्रदेश बिहार में बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है। घरेलू मांग भी बढ़ी है। ऐसे में राज्य को जितनी बिजली चाहिए, उतना उत्पादन नहीं होता। बाहर से बिजली खरीदनी पड़ती है। बिहार जैसे अपेक्षाकृत पिछड़े समझे जाने प्रदेश के लिए यह अच्छी खबर है। अच्छी बात यह है कि राज्य सरकार इस दिशा में सोचने के साथ काम भी कर रही है। इसी के चलते राज्य मंत्रिमंडल ने भागलपुर के पीरपैंती में आठ सौ मेगावाट की तीन ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। साथ ही, लखीसराय के कजरा में 116 मेगावाट की सोलर परियोजना के लिए बाजार से ऋण लेने की सहमति दी है। इन दोनों का काम पूरा होने से राज्य बिजली के क्षेत्र में निश्चित ही आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा। कटौती से मुक्ति के साथ औद्योगिक इकाइयों को निर्बाध बिजली की आपूर्ति हो सकेगी। इससे विकास को गति मिलेगी। मंजूरी के दौरान बिहार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कुछ ऐसी ही बात कही। उन्होंने इसे बिहार की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए ऐतिहासिक बताया। अक्सर देखा यह जाता है कि अच्छी परियोजना बन तो जाती है, लेकिन निविदा से लेकर निर्माण में इस तरह लेटलतीफी होती है कि उसकी लागत बढ़ती जाती है। इसकी लगातार मानीटरिंग के साथ समय-समय पर समीक्षा हो। इसके लिए नोडल एजेंसी को अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभानी होगी। ऐसा होने से राज्य में बिजली का उत्पादन बढ़ेगा, जिससे विकास को भी गति मिलेगी।

पीरपैंती में तीन ताप विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी से निश्चित ही बिजली की कमी दूर होगी और विकास को रफ्तार मिलेगी

डिजिटल तकनीक में पिछड़ने का खतरा

दिव्य कुमार सोती

यदि हमारे फोन से लेकर लैपटाप को विदेशी एप्स के एल्गोरिदम नियंत्रित करते रहते हैं तो हम एक तरह की डिजिटल गुलामी की ओर बढ़ेंगे

बीते दिनों अमेरिकी बाजार धराशयी हो गए, जिसका असर दुनिया भर के बाजारों पर देखा गया। शेयर बाजार में इस भारी गिरावट के पीछे एक चीनी स्टार्टअप द्वारा बेहद कम दाम पर विकसित हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप डीपसीक रहा। डीपसीक के आगमन से दिग्गज अमेरिकी टेक कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में एक ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर तक की गिरावट आई। यह सब तब हुआ जब अमेरिका ने चीन को अत्याधुनिक कंप्यूटर चिप और एआइ के क्षेत्र में प्रतिबंदी टेश घोषित कर उस पर अनेक प्रतिबंध लगा रखे हैं, ताकि वह इस क्षेत्र की तकनीक या तो विकसित न कर सके और यदि करे भी तो अमेरिकी कंपनियों से कहीं पीछे ही रहे। इसके बावजूद डीपसीक को कई कसौटियों पर प्रमुख अमेरिकी एआइ एप चैटजीपीटी जितना ही सक्षम पाया गया।

डीपसीक बनाने वाली कंपनी का दावा है कि उसने यह माडल अमेरिकी कंपनियों के मुकाबले 10 गुना कम लागत पर विकसित किया है। जहां अग्रणी अमेरिकी एआइ कंपनियां अपने चैटबोट को 16000 जीपीयू से युक्त सुपरकंप्यूटरों पर प्रशिक्षित करती हैं, वहीं डीपसीक ने मात्र 2000 जीपीयू क्षमता के उपयोग से ही सक्षम एआइ टूल तैयार कर दिया। चीन ने प्रतिबंधों के बावजूद अपने स्वयं के बल पर प्रथम पंक्ति की तकनीक विकसित करने की क्षमता दिखाई। डीपसीक की आलोचना इसलिए हो रही है कि वह चीन के लिए राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दों से जुड़े प्रश्नों के उत्तर नहीं देता है, परंतु उसकी तकनीकी क्षमताओं और कम लागत वाले माडल पर कोई सवाल नहीं उठा है। स्वयं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटनाक्रम को अमेरिका के लिए जगाने वाली घंटी कहा है।

अमेरिका के सरकारी एआइ प्रोजेक्ट स्टारगेट पर काम कर रही कंपनियों जैसे माइक्रोसफ्ट और ओपन एआइ के अधिकारियों ने डीपसीक की क्षमताओं को खास प्रभावी माना है। यह समझना आवश्यक है कि डीपसीक जैसे टूल राजनीतिक प्रश्नों का जवाब तलाशने के लिए नहीं, बल्कि जटिल तकनीकी कार्यों के लिए हैं, जिसमें डीपसीक माडल काफी सस्ता और प्रभावी है। ऐसे में लागत घटाने और लाभ बढ़ाने के लिए कंपनियां उसके उपयोग को तरजीह देंगी। हालांकि अमेरिकी सरकार अपनी टेक कंपनियों के दबाव में डीपसीक पर प्रतिबंध लगा रही है। अमेरिकी सरकार का कहना है कि डीपसीक अमेरिकी यूजर्स का डाटा चुरा सकता है, परंतु ऐसे प्रतिबंधों की सीमाएं हैं। कारण यह है कि तमाम अमेरिकी कंपनियां अपने माल का उत्पादन चीनी कंपनियों से चीन में कराती हैं। ये चीनी कंपनियां डीपसीक का उपयोग करने वाली हैं। ऐसे में अमेरिकी कंपनियां अपने चीनी उत्पादकों से जो भी डाटा, जिसमें डिजाइन और पेटेंट से जुड़ी जानकारियां भी होती हैं, वह साझा करेंगी। यह बहुत हद तक भारत के मामले में भी सच है, क्योंकि तमाम भारतीय कंपनियां भी चीन में उत्पादन कराती हैं।

अवधेश राजपूत

ओपन एआइ या डीपसीक जैसा कुछ बनाने से हम कोसों दूर हैं। हमारी आइटी कंपनियां अमेरिकी कंपनियों का बैकएन्ड आफिस बनकर ही खुश हैं। हमारे विश्वविद्यालय ऐसी पीएचडी बांटकर संतुष्ट हैं, जिनमें कोई उल्लेखनीय खोज नहीं होती। ब्रेन-ड्रेन रोकने के लिए हमने कोई कदम नहीं उठाए हैं। हमारे उद्योगपति भी किसी क्रांतिकारी तकनीक के आविष्कार के लिए धन उपलब्ध नहीं कराते। रही बात भारतीयों के डाटा चोरी होने की तो वह तो अमेरिका और चीन, दोनों की कंपनियां कर रही हैं। विश्वस्तरीय एआइ टूल्स बनाना तो दूर, अभी हम स्वदेशी इंमेल और इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म तक नहीं बना पाए हैं और पूरी तरह अमेरिकी कंपनियों पर निर्भर हैं। एक्स और मेटा के एल्गोरिदम हमें वही दिखाते हैं, जो वे दिखाना चाहते हैं। हमारी समस्या यह है कि हम ऐसा कुछ करने की बहुत देर से सोचते हैं। जब तक किसी उपयोगी टेक्नोलाजी का विकास करते हैं, तब तक वह पुरानी हो चुकी होती है। लचर अनुसंधान के चलते हमें स्वयं ही अपने पर विश्वास नहीं है। ऐसे में हम कोई न कोई विदेशी बैसाखी ढूंढ़ने के आदी हो चुके हैं। इसका ताजा उदाहरण भारत आए अमेरिकी कंपनी ओपन एआइ के मुखिया सैम आल्टमैन की ओर से यह कहकर भारत को रिझाने की कोशिश है कि भारत में एआइ को लेकर बहुत संभावनाएं हैं। इन्हीं आल्टमैन को कुछ समय पहले तक भारत के एआइ टेक्नोलाजी विकसित करने के प्रयासों पर संदेह था। अब उनके सुर इसलिए बदले हैं, क्योंकि डीपसीक से मिल रही कड़ी टक्कर के चलते कई देशों का बाजार उनके हाथ से निकल सकता है। हम इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते कि जब आल्टमैन भारत में थे, तभी यह खबर भी आई कि सरकार ने कहा कि सरकारी कर्मचारी चैटजीपीटी और डीपसीक जैसे टूल्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें। ऐसी चेतावनी देने के साथ हमें अपनी क्षमताओं को भी परखना होगा, क्योंकि वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। हाल में भारत में भारतीय सेना के लिए बनाए गए ड्रोन का कुछ महीने पहले चीनी और पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा हैक कर अपने नियंत्रण में लेने संबंधी खबर इसी चिंता को बयान करती है। यूं तो ये ड्रोन भारत में बनाए गए थे, लेकिन जब चीनी सेना द्वारा इसे हैक कर लिया गया तो पता चला कि इसे सिर्फ भारत में असेंबल किया गया था और तमाम कलपुर्जे चीनी थे। यदि यह सब सच है तो गंभीर चिंता की बात है।

कोई भी देश महाशक्ति तब बनता है, जब वह सही मायनों में आत्मनिर्भर होता है। वैसे तो 140 करोड़ की जनसंख्या वाले किसी देश को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, परंतु हम एक तरह की डिजिटल गुलामी के मुहाने पर खड़े हैं, क्योंकि हमारे फोन से लेकर लैपटाप को विदेशी एप्स के एल्गोरिदम नियंत्रित करते हैं। हमारा निजी डाटा विदेशी कंपनियों के पास देश से बाहर जा रहा है और हमारे हथियारों के अंदर शत्रु देशों के बनाए कलपुर्जे लगे हैं। चूंकि विश्व एआइ और डाटा से नियंत्रित होने वाला है, इसलिए हमें अपनी इन कमियों को ठीक करना ही होगा। अन्यथा परिणाम घातक हो सकते हैं।

(लेखक काउंसिल आफ स्ट्रैटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

विकसित भारत में दिखे स्वर्णिम अतीत

राघवेंद्र पी. तिवारी

अपने अतीत की पहचान एवं गौरव को बनाए रखते हुए ही हम एक आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं

देश के सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय के लिए इस साल बजटीय आवंटन में वृद्धि कर कुल आवंटन 3,360.96 करोड़ रुपये किया जाना यही बताता है कि सरकार भारत के गौरवशाली अतीत को सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतभूमि का इतिहास समृद्ध संस्कृति का साक्षी रहा है। यह भूमि प्राचीन काल से ही ज्ञान, विज्ञान, धर्म, संस्कृति, कला एवं शौर्य का केंद्र रही है। जगत कल्याण की भावना भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य रही है, परंतु कालचक्र कुछ ऐसा चला कि लगभग आठ सौ वर्षों तक इस भूमि पर विदेशी आततायी आते रहे। मुगल एवं अंग्रेज शासकों ने हमारी धन संपदा को लूटा एवं इस महान सभ्यता को उसके मूल स्वरूप से दूर करने का कुत्सित प्रयास किया। आक्रांता काफी हद तक इस षड्यंत्र में सफल भी रहे। अंग्रेजों की सत्ता से मुक्त होने के वर्षों बाद भी यदि भारत आज सांस्कृतिक स्तर पर परतंत्रता की जंजीरों में जकड़ा है, तो उसका एक बड़ा कारण अपने गौरवपूर्ण अतीत से अनभिज्ञ रहना है।

वास्तव में देवों एवं ऋषियों की यह पुण्यभूमि न केवल ज्ञान-विज्ञान, कला और साहित्य में विश्व की मार्गदर्शन देने वाली रही है, अपितु योग, दर्शन, आध्यात्मिकता, सामाजिक व्यवस्था सहित मानव जीवन के सभी पक्षों में भी अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। इसका विस्तृत विवरण वेदों, पुराणों, उपनिषदों, महाभारत, रामायण, गीता एवं अन्य ग्रंथों में मिलते हैं। इन ग्रंथों ने न केवल धार्मिक, बल्कि नैतिक और सामाजिक मूल्यों को भी स्थापित करने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया है। भारत ने विश्व को अनेक महान धर्मों का उपहार दिया, जिनमें हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म प्रमुख हैं। इन धर्मों ने मानवता को सत्य, अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। भारतीय दर्शन में वेदांत, योग और सांख्य जैसी दार्शनिक विचारधाराएं शामिल हैं, जिन्होंने आत्मा, ब्रह्मांड और मानव अस्तित्व के रहस्यों पर प्रकाश डाला। भगवान श्रीराम का चरित्र सामाजिक समरसता एवं प्रकृति से संवाद का अनुपम उदाहरण है। गीता जैसे उपदेश ने कर्म, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से जीवन को आध्यात्मिक उन्नति हेतु प्रेरित किया। प्राचीन भारत में खगोलशास्त्र, ज्योतिष, गणित और चिकित्सा विज्ञान का अद्भुत विकास हुआ। आर्यभट्ट और भास्कराचार्य जैसे गणितज्ञों ने शून्य, दशमलव प्रणाली और त्रिकोणमिति से परिचय कराया। खगोल विज्ञान में आर्यभट्ट ने ग्रहों की गति और सूर्यग्रहण का सटीक वर्णन किया है। चिकित्सा क्षेत्र में चरक और सुश्रुत जैसे विद्वानों ने आयुर्वैदिक चिकित्सा प्रणाली विकसित की। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा का विस्तृत विवरण है। वास्तुकला के क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना, जल निकासी प्रणाली और मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार दर्शाते हैं कि भारत प्राचीनकाल में ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कितना उन्नत था।

आवश्यक है संस्कृति का संरक्षण। फाइल

भारत का शिक्षा तंत्र विश्व में अद्वितीय था। विक्रमशिला, बल्लभी, तक्षशिला एवं नालंदा जैसे विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्र थे। यहां न केवल भारतीय वरन विदेशी विद्यार्थी भी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को नष्ट करने हेतु मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू की, जिसका उद्देश्य भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बनाना था। हमें हमारी देवभाषा संस्कृत और उसमें निहित ज्ञान-विज्ञान से दूर कर दिया गया एवं इतिहास को तोड़ा-मरोड़ा गया। भारतीय चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्तिकला एवं वास्तुकला अद्वितीय एवं बहुआयामी रही है। अजंता और एलोरा की गुफाएं, खजुराहो के मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, महाबलीपुरम का मंदिर एवं कोणार्क का सूर्य मंदिर आदि भारतीय वास्तुकला की श्रेष्ठता के प्रमाण हैं। संगीत और नृत्य के क्षेत्र में भारत ने भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी जैसे शास्त्रीय नृत्यों का विकास किया। भारतीय शास्त्रीय संगीत की धुपद और ख्याल परंपराएं विश्व में अपनी पहचान रखती हैं। ये कलाएं केवल मनोरंजन का माध्यम ही नहीं, अपितु आध्यात्मिक साधना का मार्ग भी प्रशस्त करती हैं।

प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था संतुलित और व्यवस्थित थी। आज जो प्रचारित किया जाता है, उसके विपरीत हमारे समाज में कोई भी कर्तव्य की दृष्टि से बड़ा-छोटा नहीं था। सबके कार्य की अपनी महत्ता स्वयंसिद्ध थी। जीवन शैली प्रकृति केंद्रित थी। भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार एवं समाज के प्रति कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व को विशेष महत्व दिया गया।

अतीत में भारत समुद्री व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहां से मसाले, वस्त्र और आभूषण विश्वभर में निर्यात किए जाते थे। हमारी इसी आर्थिक संपदा पर विदेशियों की गिद्ध दृष्टि थी एवं अवसर मिलने पर उन्होंने इसे खूब लूटा भी। अंग्रेजों ने औद्योगिक एवं कृषि व्यवस्था को ध्वस्त कर भारत को एक बाजार और कच्चे माल के स्रोत में बदल दिया। हमारे पारंपरिक उद्योगों को नष्ट कर दिया। परिणामस्वरूप, भारतीय गरीबी एवं बेरोजगारी के शिकार हुए। विदेशी शासकों ने जाति, धर्म और क्षेत्रीय विभाजन को प्रोत्साहित किया। इस विभाजन की छाया से मुक्त होने के लिए हमें न केवल अपने इतिहास पर गर्व करना चाहिए, बल्कि उसके पुनर्जीवन के प्रयास भी करने चाहिए। अपने अतीत की पहचान और गौरव को बनाए रखते हुए ही हम एक आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं।

(लेखक पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा के कुलपति हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

स्वबोध

स्वबोध का अर्थ है-स्वयं को जानना। इस छोटे से शब्द में एक नितांत गूढ़ अर्थ समाहित है। स्वबोध एक ऐसी अवधारणा है जो आत्मज्ञान, आत्मसाक्षात्कार एवं आत्मपरिष्करण से संबंधित है। वास्तव में स्वयं को जान पाना ही इस जगत का सबसे दुष्कर कार्य है। कारण यह है कि स्वयं से परिचित होने के लिए हमें अंतर्जगत की यात्रा करनी पड़ती है, जबकि हम सब प्रतिक्षण बाह्य जगत के मिथ्या पहलुओं से घिरे रहते हैं। विज्ञान के नियमों से देखें तो एक साथ दो परस्पर विपरीत दिशाओं में यात्रा कर पाना सर्वथा असंभव है।

स्वबोध के लिए हमें बाह्य विषयों की ओर से अपना ध्यान हटाकर अंतर्मन की ओर केंद्रित होना पड़ेगा। स्वबोध के माध्यम से हम आध्यात्मिक, मानसिक, बौद्धिक एवं नैतिक उन्नयन की ओर अग्रसर होते हैं एवं ऐसा होने पर हमारे भीतर अहम का वहम दूर होने लगता है। स्वबोध की दिशा में कदम बढ़ाकर ही हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में सफल हो सकते हैं। जीवन को नकारात्मकता के दायरे से बाहर निकालकर सकारात्मकता के परिवेश की ओर मोड़ने का एकमात्र साधन स्वबोध है। प्राचीन भारतीय धर्मग्रंथों एवं मनीषियों द्वारा स्वबोध की अवधारणा पर विशेष बल देते हुए इसे आत्मिक उन्नति का एकमात्र उपाय बताया गया है।

मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन स्वबोध से ही संभव हैं। स्वबोध एक गहन एवं जटिल प्रक्रिया जरूर है, किंतु जिसने एक बार इसे सिद्ध कर लिया, उसे अपने लक्ष्य को पहचान कर स्वयं को चरमोन्नति के शिखर तक पहुंचने से कोई बाधा नहीं रोक सकती। जीवन की व्यस्तताओं के बीच हमें स्वबोध जैसे कठिन, किंतु मोक्षप्रद लक्ष्य के लिए कुछ समय निकालने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। ऐसा करके ही हम अपने जीवन को सफल बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा सकते हैं।

प्रेरणा अवस्थी

प्रारंभिक ब्रह्मांड का पुनर्निर्माण

प्रदीप

अत्याधुनिक तकनीकों और नए कण त्वरकों की मदद से ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके विकास को समझने का हो रहा प्रयास

ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर मानव हमेशा से जिज्ञासु रहा है। वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार, लगभग 14 अरब वर्ष पहले बिग बैंग नामक महाविस्फोट से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। यह विस्फोट अत्यधिक गर्म और घनी अवस्था से हुआ, जिसके परिणामस्वरूप पदार्थ, ऊर्जा, अंतरिक्ष और समय अस्तित्व में आए। लेकिन इतने विशाल और प्राचीन घटनाक्रम को कैसे समझा जा सकता है? इसका जवाब विज्ञानी अपनी प्रयोगशालाओं में खोजने का प्रयास कर रहे हैं, जहां वे अत्याधुनिक कण त्वरकों की मदद से प्रारंभिक ब्रह्मांड की स्थितियों को पुनः निर्मित करने का प्रयास कर रहे हैं।

लार्ज हैड्रान कोलाइडर (एलएचसी) जैसे कण त्वरकों का उपयोग करके विज्ञानी उन चरम परिस्थितियों की नकल करने में जुटे हुए हैं, जो बिग बैंग के शुरुआती क्षणों में विद्यमान थीं। हाल ही में रिलेटिविस्टिक हैवी आयन कोलाइडर के फीनिक्स डिटेक्टर द्वारा प्राप्त आंकड़ों से यह स्पष्ट हुआ है कि प्रयोगशाला में प्रारंभिक ब्रह्मांड की स्थितियों का पुनर्निर्माण संभव है। इससे हमें यह समझने में सहायता मिलेगी कि कैसे बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड धीरे-धीरे विकसित हुआ और पदार्थ, परमाणु, तारे और आकाशगंगाएं अस्तित्व में आईं। भविष्य में और भी अधिक शक्तिशाली कण त्वरक बनाए जाने की योजना है। वर्ष 2030 के अंत तक इसके पहले चरण के पूरा होने की उम्मीद है।

जब ब्रह्मांड की आयु मात्र एक सेकंड थी, तब उसका तापमान लगभग 10 अरब डिग्री सेल्सियस था। उस समय न तो आकाशगंगाएं थीं, न तारे और न ही ग्रह। यहां तक कि परमाणु भी अस्तित्व में नहीं थे। उस समय ब्रह्मांड केवल स्वतंत्र कणों से बना था। इन कणों का एक उच्च-ऊर्जा प्लाज्मा बना हुआ था, जिसे 'क्वार्क-ग्लूआन प्लाज्मा' कहा जाता है। इसमें क्वार्क और ग्लूआन स्वतंत्र रूप से मौजूद थे। क्वार्क वे मूलभूत कण हैं, जो प्रोटान और न्यूट्रान का निर्माण करते हैं, जबकि ग्लूआन वे कण हैं, जो क्वार्क को आपस में जोड़कर रखते हैं। ब्रह्मांड के विस्तार और तापमान के गिरने के साथ, क्वार्क और ग्लूआन ने एक साथ मिलकर प्रोटान और न्यूट्रान बनाए, जो बाद में परमाणुओं के निर्माण में सहायक बने। विज्ञानी इस पूरी प्रक्रिया को प्रयोगशाला में दोहराने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि सृष्टि के उन क्षणों को समझा जा सके, जहां भौतिकी के नियम विफल हो जाते हैं।

विज्ञानी सूक्ष्म स्तर पर होने वाले प्रयोगों के निष्कर्षों को ब्रह्मांड के बड़े पैमाने पर लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि, बिग बैंग को पुनः उत्पन्न करना असंभव है, लेकिन कण त्वरकों के माध्यम से विज्ञानी इसके प्रभावों को समझने और प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं। भविष्य में नए कण त्वरकों की सहायता से हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति व उसके विकास को अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे।

(लेखक विज्ञान संचारक हैं)

शिक्षा के लिए अपनाएं सही राह

प्रो. रसाल सिंह का आलेख 'उच्च शिक्षा की गुणवत्ता से खिलवाड़ रुके' पढ़ा। इसमें ड्राफ्ट रेगुलेशन 2025 की कमियों और उसके प्रभावों की सटीक समीक्षा की गई है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और मानक मापदंडों की उपेक्षा कर मनमाने नियम लागू नहीं किए जाने चाहिए। यह किसी भी दृष्टि से शिक्षा जगत के हित में नहीं है। कुलपति की नियुक्ति में अकादमिक शिक्षकों की अनदेखी कर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अन्य क्षेत्रों के व्यक्तियों को तरजीह देना एक प्रकार से शिक्षा का बंटाधार करने वाला फैसला ही कहा जाएगा। एक संयुक्त परीक्षा के माध्यम से देश के विश्वविद्यालयों-महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का सुझाव उपयोगी है। शिक्षकों की नियुक्ति में विषम विशेषज्ञ की अनिवार्यता समाप्त करने के दूरगामी दुष्परिणाम होंगे। इसे कतई लागू न किया जाए। ड्राफ्ट-2025 लागू हो उसके पहले इसकी खामियों को स्वसंज्ञान लेकर यूजीसी और उच्च शिक्षा विभाग उन्हें दूर करें। उच्च शिक्षा में भविष्य बनाने के लिए प्रयासरत प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को इन नए नियमों के लागू होने से बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, जो अंततः शिक्षा जगत के लिए नुकसानदेह साबित होगा। उम्मीद है कि नीति-नियंता संभावित दुष्परिणामों को ध्यान में रखकर नियमों में उचित संशोधन करके ही इसे लागू करेंगे।

मोहित सोनी, कुर्सी, मध्य प्रदेश

संस्कृति की पताका

महाकुंभ का पर्व पौष पूर्णिमा के स्नान से प्रारंभ हुआ है। इसके बाद मकर संक्रांति पर भी करोड़ों श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में स्नान किया। यह स्नान का क्रम अनवरत चलायमान है। इसी बीच भीनी अभावना पर भगदड़ की दुखद घटना हुई। जिससे तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौरा चला और कुछ लोग लगातार अफवाह फैलाने में लगे रहे कि महाकुंभ में अच्छी व्यवस्था नहीं है। बयानबाजी का दौर चलता रहा। लेकिन प्रसन्नता का विषय है कि आस्था का प्रवाह रुका नहीं और तीसरे अमृत स्नान पर्व वसंत पंचमी पर दो करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में पुण्य की डुबकी लगाई। अनेक सामाजिक संगठनों की ओर से इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन, जलपान आदि की व्यवस्था है, जहां किसी भेदभाव के बिना सभी लोग भोजन कर रहे हैं। अभी माघी पूर्णिमा पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करेंगे। यह महाकुंभ कोई सामान्य आयोजन नहीं है, बल्कि यह भौतिक से आध्यात्मिकता की ओर एक यात्रा है। इस पर्व ने हमारे सनातन धर्म और संस्कृति की पताका पूरे विश्व में फहरा दिया है।

अखिलेश कुमार मिश्र, अध्यापक, वाराणसी

मेलबाक्स

सामाजिक सामंजस्य

गुरुवार को 'जाति गिनने पर जोर' शीर्षक से प्रकाशित अग्रलेख में सही उल्लेख किया गया है कि अगर सरकार सामाजिक-आर्थिक हैसियत में निचली पंक्ति में खड़े लोगों की समग्र चिंता कर योजनाएं लाती है। फिर किस जाति समूह की कितनी संख्या है? इसका कोई मतलब नहीं है। हां, यह जरूर है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लग रहा होगा कि कांग्रेस की जड़ें तभी हिलनी शुरू हुई थी, जब देश में आरक्षण आंदोलन छिड़ने की वजह से उत्तरी भारत के दो बड़े राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय क्षत्रप का उदय हुआ था। वैसे राजीव गांधी की बहुमत वाली सरकार को बोफोर्स घोटाले के आरोप में जाना पड़ा था। वैसे ही मोदी सरकार को जातीय राजनीति में उलझा कर धराशायी किए जा सकें। मगर मोदी की चार जातियां तथा महिला, युवा, किसान, गरीब में कोई विभेद नजर नहीं आता है और इसमें सभी धर्म, जाति के लोग समाहित हो जाते हैं। वैसे कांग्रेस के सभी प्रयोगों में दलित और पिछड़ों की कितनी भागीदारी है? सनातन की विशेषता है कि इसमें अनेक जातियां हैं। हालांकि अन्य धर्म में भी जातियां हैं। यह संख्या के लिहाज से लाखों में है। जिसकी गिनती में व्यावहारिक कठिनाइयां एवं उलझन है। यही कारण है कि परंपरा द्वारा कराए गए जातीय सर्वेक्षण अविश्वसनीय जान पड़ते हैं। इस आंकड़े को उत्तेजक बनाकर प्रस्तुत करने से इस बात की आशंका है कि समाज में वैमनस्य फैल सकता है।

मुकेश कुमार मनन, पटना

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

चिंतन

मानवीय गरिमा के खिलाफ अमेरिकी 'कृत्य' निंदनीय

अपनी हरकतों और अजीब फैसलों की वजह से इन दिनों अमेरिका चर्चा में है। ट्रंप और मस्क की जोड़ी अमेरिका को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह हांकना चाहती है। सत्ता संभालते ही ट्रंप संरक्षणवादी फैसले ले रहे हैं। पेरिस जलवायु करार और विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने के बाद अमेरिका ने अपनी अंतरराष्ट्रीय सहायता एजेंसी यूएसएड को 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है तो अवैध प्रवासियों को उनके मानवाधिकार की अनदेखी करते हुए बेड़ियों में जकड़कर विदेश डिपोर्ट करना शुरू किया है। हथकड़ी में विदेश भेजे गए प्रवासियों में दो सौ से अधिक भारतीय भी हैं। हथकड़ी में वापस भेजने के अमेरिकी कृत्य की भारत में काफी आलोचना हो रही है। सरकार को जवाब देना पड़ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि अवैध प्रवासियों का निर्वासन कोई नई बात नहीं है, पिछली अमेरिकी सरकारों ने भी ऐसा किया है, लेकिन नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार कतई स्वीकार्य नहीं है। देश में तीखी आलोचना के बाद यूं तो विदेश मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत कर रही है कि निर्वासित किए जा रहे भारतीयों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो। भारत को केवल बयान जारी नहीं करना चाहिए, बल्कि अमेरिकी राजदूत को तलब कर अपना तीखा विरोध जताना चाहिए कि हथकड़ी लगाकर भारतीय नागरिकों को भेजना स्वीकार्य नहीं है। अवैध प्रवासियों की समस्या से समूचा विश्व जूझ रहा है। भारत भी अपनी आजादी के बाद से ही अवैध घुसपैठियों की समस्या से रूबरू होता रहा है। इसके बावजूद भारत ने कभी मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं किया। अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है और मानवाधिकार की वैश्विक वकालत करता रहा है, कैदियों की गिरफ्तारी भी हथकड़ी में बंद है। ऐसे में अवैध प्रवासियों को हथकड़ी में उसके देश भेजना अमेरिकी मानवाधिकार कानून का ही उल्लंघन है। भारतीय प्रवासियों से अमेरिकी प्रशासन का अनुचित व्यवहार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। भारत सरकार को कड़ा स्टैंड लेना चाहिए। अमेरिका ने यूएसएड (यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट) के जरिये विदेशी मुल्कों को दी जाने वाली सहायता पर भी तीन माह के लिए रोक लगा दी है। इस फैसले से भी भारत प्रभावित होगा। अमेरिका यूएसएड के जरिये सबसे बड़ा वैश्विक मानवीय मददगार है। वह अंतरराष्ट्रीय विकास पर भी दुनिया का सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश है। दुनिया भर में अमेरिकी सरकार की ओर से मानवीय सहायता कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ़ कैनेडी ने यूएसएड की स्थापना 1961 में की थी। इसमें लगभग 10,000 लोग कार्यरत हैं। इसके 60 से अधिक देशों में आधार हैं। यूएसएड का अधिकांश बजट स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर खर्च किया जाता है। इसका सालाना बजट क़रीब 40 अरब डॉलर है, जबकि अमेरिकी सरकार का विदेशों में सहायता पर कुल बजट 68 अरब डॉलर का है। यूएसएड यूक्रेन, इथियोपिया, जॉर्डन, कांगो, सोमालिया, यमन, अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान और सीरिया को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। हर बेलफेयर स्टेट का मानवीय चेहरा होता है, अमेरिका का वैश्विक प्रभुत्व बढ़ने के पीछे भी उसकी सहायता एजेंसी का बड़ा हाथ है। यूएसएड को बंद कर देने से कई गरीब देशों के स्वास्थ्य कार्यक्रम पर असर पड़ेगा। अमेरिकी टैरिफ वार से भी गरीब आयातक देशों पर शुल्क की मार पड़ेगी।

सारा संसार

देवराज स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर के राजाओं ने कराया था। यह हिंदू भगवान भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर के अंदर अलंकृत उत्तरीय स्तंभ हैं, जो कि दीवारों में खेदय आकर्षित लगते हैं। इस भव्य मंदिर में एक विवाह कक्ष है जिसे भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के विवाह की याद में बनाया गया था। इसमें एक पानी की टंकी भी है जिसके अंदर भगवान विष्णु की एक बड़ी मूर्ति है।

बजट

तोखन साहू

विकास, नवाचार और समावेशिता की दिशा में एक मास्टरस्ट्रोक

नया बजट मोदी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो भारत को निरंतर आर्थिक विकास, नवाचार और सामाजिक समावेशिता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और आर्थिक अस्थिरता के बीच, यह बजट एक दूरदर्शी और साहसिक खाका पेश करता है, जो तात्कालिक चुनौतियों और दीर्घकालिक आकांक्षाओं दोनों को पूरा करता है। यह बजट केवल आर्थिक विकास को गति देने का साधन नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास के लाभ देश के प्रत्येक कोने तक पहुँचें। विशेष रूप से मध्यम वर्ग, किसानों, युवाओं और उद्यमियों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह सिर्फ एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक रूपरेखा को बदलने, लोगों को सशक्त बनाने और वैश्विक स्तर पर देश की स्थिति मजबूत करने का रोडमैप है।

कृषि और ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना : बजट के केंद्र में कृषि और किसानों के कल्याण के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। कृषि क्षेत्र, जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, को इस बजट में विशेष प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रीय उच्च उत्पादकता बीज मिशन और प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना जैसी पहलों के माध्यम से 100 कृषि जिलों में आधुनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे लगभग 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा, पांच वर्षीय कपास उत्पादकता मिशन और आत्मनिर्भरता के लिए दलहन मिशन (विशेष रूप से तुअर, उड़द और मसूर पर ध्यान केंद्रित करते हुए) भारतीय कृषि को आत्मनिर्भर, सतत और लाभकारी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के अल्पकालिक ऋण की सुविधा प्रदान कर 7.7 करोड़ किसानों और कृषि श्रमिकों को सशक्त किया जाएगा। पारंपरिक कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देना और कृषि के डिजिटलीकरण की दिशा में उठाए गए कदम, वैश्विक स्तर पर टिकाऊ कृषि की ओर बढ़ने की रणनीति के अनुरूप हैं।

संघ बजट 2025 केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है; यह 'नए भारत' की परिकल्पना का घोषणापत्र है। यह समावेशी, सतत और भविष्य के लिए तैयार भारत की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है।किसानों, उद्यमियों, छात्रों और शहरी नागरिकों की आवश्यकताओं को संतुलित करते हुए, यह बजट भारत के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखता है। बजट 2025 एक मजबूत, आत्मनिर्भर और वैश्विक भारत की दिशा में नए युग की शुरुआत है।

-लेखक भारत सरकार में आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री हैं।

बजट से रेल को मिलेगी नई गति

विश्लेषण
प्रदीप सरदाना

रेल मंत्रालय देश के लिए ब्रिटिश राज से ही बेहद अहम रहा है। ब्रिटिश सरकार में रेल मंत्रालय का बजट पहले आम बजट का हिस्सा था। लेकिन सन 1921 में तत्कालीन 'ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी' के अध्यक्ष विलियम एक्वर्थ ने रेलवे के विकास के लिए, अपने वित्तीय प्रबंध अलग से तैयार करने की सिफ़ारिश की। तत्पश्चात 1924 से भारत में रेल बजट अलग से प्रस्तुत करने की शुरुआत हो गयी। मोदी सरकार में पहले तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने और फिर पीयूष गोयल ने 2016 में अंतिम बार रेल बजट पेश किया। रेल बजट को 92 वर्ष तक अलग पेश करने की परंपरा तब टूटी, जब 2017 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रेल बजट का आम बजट में विलय कर दिया।

संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब 2025-26 का बजट प्रस्तुत कर रही थीं तब यह संभावना तो थी कि यह बजट कुछ अलग होगा, लेकिन यह बजट इतना शानदार और उम्मीदों से भी ऊपर होगा, ऐसी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। इस बजट ने लगभग सभी वर्ग की झोलियां भरी हैं। साथ ही अधिकतर मंत्रालयों को भी इतना कुछ दिया है कि उनकी पुरानी योजनाएं तो अविरल चलती ही रहेंगी। फिर नया कुछ भी इतना होगा जो देश को विकसित भारत बनाने के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में भी सहायक रहेगा।

इधर रेल मंत्रालय की बात करें तो यह मंत्रालय देश के लिए ब्रिटिश राज से ही बेहद अहम रहा है। ब्रिटिश सरकार में रेल मंत्रालय का बजट पहले आम बजट का हिस्सा था। लेकिन सन 1921 में तत्कालीन 'ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी' के अध्यक्ष विलियम एक्वर्थ ने रेलवे के विकास के लिए, अपने वित्तीय प्रबंध अलग से तैयार करने की सिफ़ारिश की। तत्पश्चात 1924 से भारत में रेल बजट अलग से प्रस्तुत करने की शुरुआत हो गयी। मोदी सरकार में पहले तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने और फिर पीयूष गोयल ने 2016 में अंतिम बार रेल बजट पेश किया। रेल बजट को 92 वर्ष तक अलग पेश करने की परंपरा तब टूटी, जब 2017 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रेल बजट का आम बजट में विलय कर दिया।

असल में सन 2014 में नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही भारतीय रेल का कायापलट करने के लिए जिस तरह का कृत संकल्प लिया,वह अद्भुत था। रेलवे के प्रति उस तरह का भव्य सपना उनसे पूर्व शायद किसी ने नहीं देखा होगा। क्योंकि मोदी सरकार से पहले भारतीय रेल अपनी स्थापना के 160 साल बाद भी अपने अपेक्षित गंतव्य पर नहीं पहुंच सकी। ऐसा नहीं कि पूर्व वर्षों में भारतीय रेल में कुछ विकास नहीं हुआ। कई बड़े काम, बदलाव, सुधार और विकास हुए लेकिन वैश्विक स्तर पर यूरोपीय देशों के साथ जापान और चीन ने रेल परिवहन को जो शिखर दिया,उसके सामने हम बहुत पिछड़े रहे। मिसाल के तौर पर देश में बिजली से चलने वाली पहली रेल ठीक 100 साल पहले 3 फरवरी 1925 को चल गयी थी। लेकिन भारतीय रेल में शत प्रतिशत विद्युतीकरण आज तक नहीं हो सका। मोदी सरकार ने अपने पिछले 10 साल में भारतीय रेल को 95 प्रतिशत विद्युतीकरण कर दिया है। लेकिन इसका शत प्रतिशत कार्य इस नए बजट के माध्यम से आगामी एक वर्ष में ही हो सकेगा। रेलवे का पिछड़ने का कारण इसका कम बजट भी रहा। देश स्वतंत्र होने के बाद सन् 1947-48 के लिए देश के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई ने जो पहला रेल बजट पेश किया उसमें रेलवे को 14 करोड़ 28 लाख रुपये आवंटित किए गए। उधर मोदी सरकार से पूर्व वर्षों में तो रेलवे का बजट मात्र 20 से 25 हजार करोड़ होता था। जबकि इस बरस वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के लिए रेल मंत्रालय को 2 लाख 52 हजार करोड़ रुपये की राशि आवंटित कर भारतीय रेल के भविष्य को और उज्ज्वल करने के मार्ग को 'ग्रीन सिग्नल' दे दिया है। इतने बड़े बजट से भारतीय रेल जल्द ही विश्व रेल परिवहन में अपनी बड़ी उपस्थिती दर्ज कराने के लिए अत्यंत तीव्र गति से बढ़ सकेगी। हालांकि गत वर्ष भी वित्त मंत्रालय ने रेल के लिए इतनी ही धन राशि आवंटित की थी तो इस

बरस समय के साथ यह राशि और बढ़ी क्यों नहीं? इस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि लगातार इतनी बड़ी राशि मिलना भी बड़ी बात है। रेल मंत्री वैष्णव इस बजट को लेकर यह भी कहते हैं-'यह एक ड्रीम बजट है। इसमें भविष्य की प्रगति की आधारशिला है तो आज की आवश्यकताओं के लिए राहत भी। इसे रेलवे के आधुनिकीकरण और डिजिटल व्यवस्था को बढ़ोतरी के साथ,रेलवे सुरक्षा के लिए भी काम सुगमता से हो सकेंगे। फिर नयी रेल गाड़ियां चलाने के साथ बुलेट ट्रेन को जल्द पटरी पर चलाने का काम भी।' इधर इस बरस रेल को 2 लाख 52 हजार रुपये की राशि तो बजट से आवंटित हुई है, साथ ही 10 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त संसाधनों से जुटाने का प्रावधान भी है। इससे यह बजटीय राशि बढ़कर 2 लाख 62 हजार करोड़ हो जाएगी। फिर भारतीय रेल अपने आंतरिक संसाधनों से भी 3 हजार करोड़ रुपये और भी एकत्र कर सकेगी। देश में आधुनिक वंदे भारत रेल गाड़ियां चलने से रेल परिवहन एक नए युग में पहुंच गया है। अभी 136 वंदे भारत देशभर में चल रही हैं लेकिन इस बजट के बाद देश में 200 और वंदे भारत चलाने की योजना सफल हो सकेगी। पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए संभावना है कि आगामी वर्ष में ही करीब 75 और वंदे भारत शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ रेल मंत्रालय 100 'अमृत भारत' रेल चलाने की योजना को साकार रूप देने में जुट गया है। देश में अभी दो 'अमृत भारत' चल रही हैं। 'अमृत भारत' निम्न आयवर्ग और श्रमिकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। इन गैरवातानुकूलित गाड़ियों में भी वे लगभग तमाम सुविधाएं हैं जो वंदेभारत जैसी आधुनिक रेल में हैं। इनका किराया एक हजार किमी का सिर्फ 450 रुपये है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा के लिए यह आदर्श रेल है। इधर अब 200-250 किमी की कम दूरी की यात्रा के लिए भी 50 नमो भारत रैपिड ट्रेन भी जल्द शुरू हो सकेंगी। पहली नमो भारत रेपिड रेल अहमदाबाद और भुज के बीच 17 सितंबर 2024 को आरंभ हुई थी। इस सबसे भारतीय रेल को 17 हजार 500 नए सामान्य कोच और मिल सकेंगे। इस बजट में 4 लाख 60 हजार करोड़ रुपये नयी परियोजनाओं के लिए भी हैं। इससे अब देश में जहां 1300 नए आधुनिक रेलवे स्टेशन बनकर शुरू होने लगेंगे, वहीं एक हजार नए फ्लाईओवर्स और अंडरपास भी बनेंगे। वहीं अब 7500 किमी के पुराने ट्रैक बदलने और नए ट्रैक बनने का बड़ा काम भी होने जा रहा है। इस बजट में जो एक बड़ा काम और हो सकेगा, वह है रेलवे वर्कशॉप के आधुनिकीकरण का। इसके लिए 25 हजार करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान है।

वर्कशॉप के नवीनीकरण से भी भारतीय रेल को निश्चय ही एक नयी चमक मिलेगी। उधर रेल यात्रा की सुरक्षाओं को लेकर भी इस बजट में विशेष राशि है। जिससे सुरक्षा की कवच प्रणाली पर तेजी से काम शुरू हो सकेगा। अब 10 हजार नए कवच लगाने का प्रावधान है। रेल सुरक्षा के लिए इस बजट में एक लाख 16 हजार करोड़ रुपये है। कवच जल्द लग सके, इसके लिए रेल ट्रैक के साथ बोगियों में भी बदलाव की जरूरत होती है, साथ ही प्रशिक्षित व्यक्तियों की भी। अब जहां रेल मंत्रालय ने 12 हजार व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है, वहां पहले एक कवच को स्थापित करने में 23 दिन लगते थे। अब वही कवच मात्र 26 घंटे में लगाया जा सकेगा। इन सभी योजनाओं के अतिरिक्त देश दुनिया की नजर हमारे बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर भी लगी है। मुंबई से अहमदाबाद मार्ग की देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का काम जापान के सहयोग से बहुत तेजी से चल रहा है। देश में हवा से बातें करती बुलेट ट्रेन को शुरू करना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भी पुराना स्वप्न है। ये नयी परियोजनाएं और बुलेट ट्रेन भारतीय रेल जगत को विश्व में एक नए शिखर पर ले जाएंगी।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

सत्य में ऐसी शक्ति जो आपको सौ झूठ से बचाए

संकलित
दर्शन

संसार में सत्य को सबसे सुंदर कहा गया है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि सत्य के लिए किसी से भी संघर्ष करने के लिए स्वयं को सदैव तत्पर रखना चाहिए। एक सत्य ही तो है, जो मनुष्य को सौ झूठ बोलने से बचा लेता है। सत्य की ऐसी महत्ता-महिमा होते हुए भी संप्रति संसार में असत्य का बोलबाला बढ़ा है। हालांकि, असत्य का आश्रय लेने वालों को सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि अंत में विजय सत्य के खेमे का ही वरण करती है। वास्तव में जहां सत्य है, वहीं धर्म है और जहां धर्म वहीं विजय है। यदि हमारी जीवन रूपी इमारत सत्य रूपी नींव पर खड़ी होगी तभी हम उसे निरंतर ऊंचाई प्रदान करते हुए उसकी प्रकृति को संरक्षित रख पाएंगे। सत्य के महत्व पर बुद्ध ने कहा कि सत्य को छोड़कर जो असत्य बोलता है, धर्म का उल्लंघन करता है, परलोक की जिसे चिंता नहीं है, वह व्यक्ति बड़े से बड़ा पाप कर सकता है। इसलिए असत्य का परित्याग ही श्रेयस्कर है। मनीषी कहते हैं कि 'मनसा वाचा कर्मणा' यानी मन, वचन और कर्म से सत्य बोलना चाहिए। जो विचार मन में हों वही वाणी में भी होने चाहिए और उसी के अनुरूप ही मनुष्य का व्यवहार भी होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि मन, वचन और कर्म से अलग रहने वाले पूर्णरूपेण सत्य का आचरण नहीं कर सकते।गांधी जी जैसे महामानव सत्य को निरपेक्ष सत्य के रूप में ग्रहण करते हैं। सत्य को ईश्वर का पर्यायवाची बताते हैं। उसे अपनी नीति का अहम अवयव मानते हैं। इसी सत्य के प्रति निष्ठावान हैं।

अहंकार का त्याग ही तपस्या का मूलमंत्र

संकलित
प्रेरणा

एक साधु व एक डाकू एक ही दिन मरकर यमलोक पहुंचे धर्मराज उनके कर्मों का लेखा-जोखा खोलकर बैठे थे और उसके हिसाब से उनकी गति का हिसाब करने लगे। धर्मराज ने दोनों से कहाः मैं अवसर देता हूं, कह सकते हो। डाकू अत्यंत विनम्र शब्दों में बोला महाराजः मैंने जीवन भर पापकर्म किए जिसने केवल पाप ही किया हो वह क्या आशा रखे आप जो दंड दें, मुझे स्वीकार है। डाकू के चुप होते ही साधु बोला महाराजः मैंने आजीवन तपस्या और भक्ति की है मैं कभी असत्य के मार्ग पर नहीं चला। धर्मराज ने दोनों की बात सुनी फिर डाकू से कहाः तुम्हें दंड दिया जाता है कि तुम आज से इस साधु की सेवा करो डाकू ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली। यमराज की यह आज्ञा सुनकर साधु ने आपत्ति जताते हुए कहाः महाराज! इस पापी के स्पर्श से मैं अपवित्र हो जाऊंगा मेरी तपस्या तथा भक्ति का पुण्य निरर्थक हो जाएगा मेरे पुण्य कर्मों का उचित सम्मान नहीं हो रहा है। धर्मराज को साधु की बात पर बड़ा क्षोभ हुआ वह क्षुब्ध होकर बोलेः निरपराध व्यक्तियों को लूटने और हत्या करने वाला डाकू मर कर इतना विनम्र हो गया कि तुम्हारी सेवा करने को तैयार है। तुम वर्षों के तप के बाद भी अहंकार ग्रस्त ही रहे यह नहीं जान सके कि सब में एक ही आत्मतत्व समाया हुआ है तुम्हारी तपस्या अधूरी और निष्फल रही अतः आज से तुम इस डाकू की सेवा करो, और तप को पूर्ण करो।

अंतर्मन

आज की पाती

किताबों-अखबारों को बनाइए अपना साथी

युवा लोगों में इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से किताबों में दिलचस्पी कम होती जा रही है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, वाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से युवा भारतीयों की पढ़ने की आदत में तेजी से बदलाव आ रहा है। स्मार्टफोन और लगभग मुफ्त इंटरनेट सेवाओं के प्रसार ने आदत बदलने की इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। इंस्टेंट मैगी युवा पीढ़ी का हिस्सा है। नतीजतन वे अपने जीवन को मैनेज करने के लिए गूगल का इस्तेमाल करते हैं। मेहनत, धैर्य और लगन से काम करके पुरानी पीढ़ी, जो कभी किताबें पढ़ती थी, अपने जीवन को मकसद देती थी। किताबें समस्या समाधान के लिए बहुत जरूरी थीं। बहरहाल, किताबों-अखबारों को साथी बनाने की जरूरत है, इससे नजरिया बदल जाएगा। - संतोष साहू, दुर्ग

ट्रेंड

बिपिन रावत को श्रद्धांजलि

उत्तराखण्ड के रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल ने आज देश के प्रथम सीडीएस 'पद्म विभूषण' जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा अविस्मरणीय है, उनको साहस एवं शौर्य को नमन!
-योगी आदित्यनाथ, सीएम, उप्र

अपने विमान क्यों नहीं भेजे

मोदी सरकार को विनिवेश पर एक विस्तृत बयान देना चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि हमारे अपनी धरती पर एक सैन्य विमान उतारने के बजाय भारतीयों को नहीं और सम्मान के साथ वापस लाने के लिए अपने विमान क्यों नहीं भेजे।
-मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष

शिक्षा प्रणाली में बदलाव

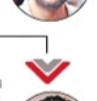

यह जरूरी है कि हमारी शिक्षा प्रणाली दुनिया में हो रहे बदलाव के अनुरूप बने और युवा भारतीयों को आगे बढ़ने और हमारे देश को आगे ले जाने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करे।
-राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद

एआई का स्वागत

एआई वास्तव में एक लोकतांत्रिक तकनीक है, जो उन लोगों को सशक्त करती है जो उस गति से परिवर्तन को संभालने के इच्छुक हैं जो अविश्वास के लिए अस्वीकार्य है। हमारे लिए रचनात्मकता अस्वीकार्य है पैदा होती है, हम इसका स्वागत करते हैं।
-रोहित कपूर, फिल्मकार

करंट अफेयर

किसी भी तरह के जातीय सफाए से बचना जरूरी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पट्टी पर 'स्वामित्व' स्थापित करने का प्रस्ताव देने के एक दिन बाद संयुक्त राष्ट्र (संरा) महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने बुधवार को कहा कि किसी भी तरह के जातीय सफाये से बचना जरूरी है। गुतारेस ने इसी के साथ इजराइल-फलस्तीन संघर्ष के दो-राष्ट्र समाधान की एक बार फिर वकालत की। जातीय सफाये का मतलब किसी शक्तिशाली पक्ष की ओर से किसी जातीय समूह को उसकी भूमि से जबरन हटाने और कभी-कभी उसकी जगह किसी अन्य जनसांख्यिकीय समूह को वहां बसाने से है। उन्होंने कहा, समाधान की तलाश में हमें समस्या को और विकराल नहीं बनाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय कानून की आधारशिला के प्रति समर्पित रहना महत्वपूर्ण है। किसी भी तरह के जातीय सफाये से बचना जरूरी है। गुतारेस ने फलस्तीनी लोगों के अपरिहार्य अधिकारों के इस्तेमाल पर समिति के समक्ष अपनी टिप्पणी में दोहराया कि संयुक्त राष्ट्र इजराइल-फलस्तीन संघर्ष के दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। उन्होंने कहा, 'किसी भी टिकाऊ शांति के लिए दो-राष्ट्र समाधान की दिशा में ठोस, अपरिवर्तनीय एवं स्थायी प्रगति के अलावा कब्जे की समाप्ति और एक ऐसे स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य की स्थापना की आवश्यकता होगी, जिसका गाजा एक अभिन्न हिस्सा हो।'

ऑफ बीट

बुध ग्रह अभी भी सिकुड़ता जा रहा

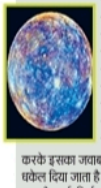

ग्रह वैज्ञानिक लंबे समय से जानते हैं कि बुध अरबों वर्षों से सिकुड़ रहा है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह होने के बावजूद, आंतरिक गर्मी निकल जाने के कारण इसका आंतरिक भाग ठंडा होता जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जिस चट्टान (और, उसके भीतर, धातु) से यह बना है, उसका आयतन थोड़ा सिकुड़ता जा रहा है। हालांकि, यह अज्ञात है कि ग्रह आज भी कितना हद तक सिकुड़ रहा है - और, यदि यह वाकई सिकुड़ रहा है, तो यह भी कोई नहीं जानता कि यह प्रक्रिया कितने समय तक जारी रहने की संभावना है। चूंकि बुध का आंतरिक भाग सिकुड़ रहा है, इसकी सतह (परत) के पास दबाने के लिए उत्तरोत्तर कम क्षेत्र रह गया है। यह 'दबाव ब्रस्ट' विकसित करके इसका जवाब देता है - ग्रहों क्षेत्र का एक भाग निकटवर्ती इलाके पर धकेल दिया जाता है। यह सेब के पुराने होने पर उस पर पड़ने वाली झुर्रियों की तरह है, फर्क सिर्फ इतना है कि एक सेब इसलिए सिकुड़ जाता है क्योंकि वह सूख रहा है जबकि बुध अपने आंतरिक भाग के तापीय संकुचन के कारण सिकुड़ रहा है। बुध के सिकुड़ने का पहला सबूत 1974 में सामने आया जब मेरिनर 10 मिशन ने सैकड़ों किलोमीटर तक अपना रास्ता बना चुकी कई किलोमीटर ऊंची स्कार्पियों (रैंप जैसी ढलानों) की तस्वीरें प्रसारित कीं।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

कल्पमेधा

आदमी कुल से महान नहीं होता, नैतिक मूल्यों से महान होता है। तुम किस कुल में जन्मे हो, इसकी अपेक्षा तुम कैसे हो, यह पहचानने की कोशिश करो।

- ललितप्रभ सागर

संवेदनहीन रवैया

अमेरिका अक्सर दुनिया भर में मानवाधिकारों, नैतिक और मानवीय मूल्यों पर आधारित नीति की वकालत करता रहा है। यह अलग बात है कि व्यवहार में कई बार वह खुद ऐसे कठघरे में खड़ा दिखता है, जो उसकी घोषित प्रतिबद्धताओं से उलट होने का संकेत देता है। अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें उनके देश भेजने के मसले पर वह अपने पक्ष को सही बता सकता है, लेकिन इस पर अमल के जैसे तौर-तरीके सामने आए हैं, उससे दुनिया भर में हैरानी और चिंता का भाव है। गौरतलब है कि अमेरिका में कथित तौर पर वैध दस्तावेजों के बिना रह रहे सौ से ज्यादा भारतीय प्रवासियों को लेकर अमेरिकी सेना का एक विमान भारत पहुंच चुका है। गैरकानूनी तरीके से अमेरिका में रहने वाले लोगों को नियमों के मुताबिक वापस भेजना अमेरिका का नीतिगत फैसला हो सकता है, लेकिन इस क्रम में ऐसे लोगों को अपराधियों के समकक्ष मान कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करने को किस तर्क पर सही कहा जा सकता है? ऐसी तस्वीरें सामने आईं, जिनमें अवैध प्रवासी भारतीय लोगों को बेड़ियों और हथकड़ी बांध कर सेना के एक विमान से भेजा गया। इस क्रम में लौटने के बाद कुछ लोगों ने अपना दुख जाहिर किया कि उन्हें कैदियों या अपराधियों की तरह लाया गया और यात्रा के दौरान जानबूझ कर तकलीफदेह हालात का सामना करने पर मजबूर किया गया।

अफसोस की बात है कि तमाम सवालों को ताक पर रख कर अमेरिकी प्रशासन ने इस मुद्दे पर जैसा रवैया अपनाया है, उससे डोनाल्ड ट्रंप के इस दूसरे कार्यकाल में नीतिगत मसलों पर अमल के भावी तौर-तरीकों के बारे में संकेत मिलता है। अगर उचित दस्तावेजों के बिना अमेरिका में रह रहे लोगों को भारत वापस भेजना अनिवार्य है, तो उनके साथ पेशेवर अपराधियों की गिरफ्तारी की तरह का बर्ताव किए जाने को कैसे उचित ठहराया जाएगा? स्वाभाविक ही इस रवैये की खुद अमेरिका में भी तीखी आलोचना हुई है। वहीं भारत में विपक्ष ने यह सवाल उठाया है कि अमेरिका से भेजे गए प्रवासियों के साथ जैसा बर्ताव किया गया है, उस पर सरकार की ओर से कोई ठोस आपत्ति क्यों नहीं दर्ज की गई या कोई व्यावहारिक हल क्यों नहीं निकाला गया? एक ओर भारतीयों को कैदियों की तरह भेजे जाने पर सरकार की चुप्पी बनी रही, दूसरी ओर ट्रंप ने जब कोलंबिया के अवैध प्रवासियों को वापस भेजने की घोषणा की, तो वहां के राष्ट्रपति ने अपने नागरिकों की 'गरिमा' को बरकरार रखने के लिए वायुसेना के दो विमान उन्हें लाने के लिए भेजे।

ऐसा नहीं है कि अमेरिका से कोई पहली बार अवैध प्रवासियों को वापस भेजा गया है। मगर डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद अवैध प्रवासियों सहित कुछ अन्य मुद्दों पर अमेरिकी प्रशासन का जैसा रवैया दिख रहा है, उसका औचित्य समझ से परे है। क्या इस बात की संभावना नहीं है कि बहुत सारे भारतीय वहां काम करने के परमिट के साथ गए होंगे, लेकिन उसकी अवधि खत्म हो जाने के बाद वे अवैध प्रवासियों की श्रेणी में आ गए? कामकाज के दौरान उन्होंने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी अपना योगदान दिया होगा। अगर वैसे लोग भी अवैध प्रवासी के रूप में चिह्नित कर लिए गए हों तो उनके साथ कैसे व्यवहार की अपेक्षा की जानी चाहिए? मानवाधिकारों के सवाल पर आए दिन दूसरे देशों को कठघरे में खड़ा करने वाले अमेरिका को क्या इस मसले पर न्यूनतम मानवीय और संवेदनशील रुख नहीं अपनाना चाहिए?

दांव पर जिंदगी

उच्च गुणवत्ता के कैमरे से लैस मोबाइल फोन अब मौत का सबब बन रहे हैं। बार-बार स्वयं की अच्छी तस्वीर लेने की लत कब बेलगाम भूख में तब्दील होती गई, इसका अहसास तब हो रहा है, जब सेल्फी लेते लोगों, खासकर युवाओं की जिंदगी दांव पर लग गई दिखती है। पिछले कुछ समय से युवा पीढ़ी में इसका नशा इस कदर हावी होता जा रहा है कि वे अपनी फिक्र करना भी जरूरी नहीं समझ रहे। नतीजतन,ऐसा करते हुए कोई झील में डूब जाता है, तो कोई पहाड़ से गिर जाता है या फिर रेलगाड़ी की चपेट में आ जाता है। सेल्फी के प्रति इतनी दीवानगी की वजह समझने की आवश्यकता है। खुद की खास तस्वीर लेने के फेर में लोग अपनी जिंदगी को खतरे में डालने से नहीं हिचकिचा रहे, तो इसका अर्थ है कि वे ऐसी मानसिक अवस्था में हैं, जो यथार्थ से दूर है। गौरतलब है कि मंगलवार को महाराष्ट्र के ठाणे में दोस्तों के साथ सेल्फी ले रहा एक युवक यह देख नहीं सका कि कोयना एक्सप्रेस तेज रफ्तार से आ रही है। रेलगाड़ी की चपेट में आकर हुई इस युवक की मौत इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है।

सोशल मीडिया के इस दौर में सेल्फी लेने का चलन बेतहाशा बढ़ा है। खासकर युवा एक दिन में कई-कई बार सेल्फी लेते हैं और उसे सोशल मीडिया के अलग-अलग मंचों पर साझा करते हैं। यह प्रवृत्ति उनकी मनःस्थिति को दर्शाती है। लंदन की नाटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी और तमिलनाडु के त्यागराज स्कूल आफ मैनेजमेंट के साझा अनुसंधान का निष्कर्ष है कि अगर किसी का दिन भर में तीन से ज्यादा सेल्फी लेने से मन नहीं भरता, तो उसे कोई विकार है। यह लत अब घातक होती जा रही है, क्योंकि एक आकलन के मुताबिक सेल्फी लेते हुए सबसे ज्यादा मौत इस समय भारत में हो रही है। इसकी वजह सिर्फ स्मृतियों को संजोने तक सीमित नहीं हो सकती। दरअसल, लोग दूसरों से अलग दिखना चाहते हैं। मगर इस क्रम में अपनी जान गंवा देने तक की लापरवाही बरतने को कैसे उचित माना जा सकता है?

मानसिक समस्याओं से जूझते बच्चे

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) की 'मेंटल हेल्थ आफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल' नामक ताजा रपट के मुताबिक दुनिया में दस से उन्नीस वर्ष का प्रायः प्रत्येक सातवां बच्चा किसी न किसी मानसिक समस्या से जूझ रहा है।

चेतनादित्य आलोक

आजकल की भागदौड़ भरी दुनिया में मानसिक समस्याएं बड़ी तेजी से लोगों को अपना शिकार बनाती जा रही हैं। इसका प्रभाव इतना तीव्र होता है कि इससे न तो कोई देश बचा है, और न ही कोई राज्य। कटु सत्य है कि इसके घातक प्रभाव से अछूता आज न तो कोई गांव है, न कोई शहर और न ही कोई गली-मोहल्ला। इसका शिकार बच्चे, किशोर, बड़े-बजुर्ग, स्त्री और पुरुष सभी हो रहे हैं, लेकिन आंकड़ों की बात करें, तो विशेष रूप से, बच्चों और किशोरों में यह समस्या अब कुछ ज्यादा ही जटिल होती जा रही है। इसके कारण बच्चों की मासूमियत खत्म होती जा रही है। उनकी फूल-सी मुस्कुराहट कहीं खो रही है। वे बेहद गुस्सैल होते जा रहे हैं। वे बात-बात पर क्रोध करने लगे हैं। यहां तक कि अपने माता-पिता और अभिभावक पर हमले करने से भी वे नहीं चूकते। ऐसे में उनके माता-पिता को यह समझ में नहीं आता कि जो बच्चे कुछ महीने, साल पहले तक मासूमियत से भरे बिल्कुल सामान्य व्यवहार वाले थे, हर पल खेलते-कूदते, हंसते-मुस्कराते, गाते-गुनगुनाते और आयु के अनुरूप शरारतें करते रहते थे, आखिर क्या कारण है कि अचानक उनका व्यवहार इस प्रकार बदल गया कि वे उन्हें बिल्कुल सुनना और मानना ही नहीं चाहते।

विडंबना है कि खेलने-कूदने और खाने-पीने की आयु में देश के बच्चों और किशोरों में बेचैनी, अवसाद तथा मानसिक तनाव जैसी समस्याएं अब गंभीर होती जा रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) की 'मेंटल हेल्थ आफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल' नामक ताजा रपट के मुताबिक दुनिया में दस से उन्नीस वर्ष का प्रायः प्रत्येक सातवां बच्चा किसी न किसी मानसिक समस्या से जूझ रहा है। इन समस्याओं में अवसाद, बेचैनी और व्यवहार से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं। एक अनुमान के मुताबिक मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी लगभग एक तिहाई समस्याएं 14 साल की उम्र से पहले शुरू हो जाती हैं, जबकि इनमें से आधी समस्याएं 18 वर्ष से पहले सामने आने लगती हैं। तात्पर्य यह कि जब हमारे मासूम बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर कदम बढ़ाना आरंभ करते हैं, सामान्यतया उसी दौरान मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी अलग-अलग समस्याएं उन्हें अपना शिकार बनाना शुरू कर देती हैं।

यूनिसेफ की एक रपट के अनुसार भारत में सात में से एक बच्चा अवसाद का शिकार है। आंकड़ों की बात करें, तो देश के 14 फीसद बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य खराब है। इसी प्रकार, 'इंडियन जर्नल आफ साइकिएट्री' में वर्ष 2019 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार भारत में पांच करोड़ से अधिक बच्चे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे। इनमें से ज्यादातर बच्चे तनाव, चिंता और अवसाद का सामना कर रहे थे।

यूनिसेफ के एक अनुमान के मुताबिक कोरोना महामारी के बाद ये आंकड़े पहले की तुलना में कई गुना तक बढ़ गए हैं। डब्लूएचओ के आंकड़े बताते हैं कि पूरी दुनिया में 30 करोड़ से भी अधिक लोग चिंता और तनाव से जूझ रहे हैं। कोई 28 करोड़ लोग अवसाद का सामना कर रहे हैं। विज्ञान पत्रिका 'द लैंसेट' में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार आस्ट्रेलिया में 75 फीसद किशोर तनाव-चिंता और बेतहाशा अवसाद से जूझ रहे हैं। वहीं, दस से 18

वर्ष की आयु के 64 फीसद वयस्कों को तीन से अधिक बार खराब मानसिक स्वास्थ्य का दंश झेलना पड़ा है। विशेषज्ञों के अनुसार किशोरावस्था के दौरान लड़के-लड़कियों में कई प्रकार के हार्मोन में और शारीरिक बदलाव होने के कारण उनकी सोच और व्यवहार में बदलाव आता है। इनके अतिरिक्त, उसी

> **अध्ययन के मुताबिक, अगर कोई सोशल मीडिया पर प्रतिदिन एक घंटे बिताता है, तो उस व्यक्ति में अवसाद के लक्षण प्रतिवर्ष 40 फीसद तक बढ़ जाते हैं। बीएमसी मेडिसिन में 2010 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जो लड़के-लड़कियां किसी तरह के खेल, शारीरिक व्यायाम में भाग नहीं लेते, उनके अवसाद का शिकार बनने की आशंका अधिक होती है। उक्त अध्ययन में यह भी पता चला था कि प्रतिदिन एक घंटे शारीरिक व्यायाम से अवसाद एवं तनाव का जोखिम 95 फीसद तक कम हो जाता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि बच्चों का खेल का समय बढ़ाने और 'स्क्रीन टाइम' घटाने का हर संभव प्रयास किया जाए, लेकिन जो बच्चे पहले ही तनाव और अवसाद का शिकार बन चुके हैं, उन्हें ठीक करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है।**

दौरान लड़के-लड़कियों को बोर्ड परीक्षाओं और करिअर को लेकर विषय चुनने जैसे दबावों और ऊहापोह वाली परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ता है। ऐसे में, अगर उन्हें घर और विद्यालय में सहयोगी परिवेश नहीं मिले तो ये दबावों और ऊहापोह वाली परिस्थितियां प्रायः तनाव-चिंता और अवसाद का रूप ले लेती हैं। इसी प्रकार, जो बच्चे नियमित पढ़ाई-लिखाई नहीं करते, वे परीक्षाएं नजदीक आने पर अक्सर दबाव में आ जाते हैं।

वहीं, मनोचिकित्सकों का मानना है कि आजकल बच्चों में विफलताओं से निपटने की क्षमता कम होती जा रही है। कभी-कभी यह आनुवंशिक भी हो सकता है। इतना ही नहीं, हमारी प्रतिदिन की आदतों में शामिल हो चुके फास्ट फूड, शीतल पेय और सोशल मीडिया जैसे तत्त्व भी अवसाद का कारण बन रहे हैं। वर्ष 2024 में नेशनल लाइब्रेरी आफ मेडिसिन (एनएलएम) में प्रकाशित एक अध्ययन में यह बात सामने आई थी कि 'अल्ट्रा प्रोसेस्ड और फास्ट फूड' खाने से व्यक्ति में तनाव और अवसाद का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है, जिसका सबसे अधिक खतरा वयस्कों को होता है, क्योंकि फास्ट और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के सबसे बड़े उपभोक्ता भी वही हैं। ऐसे ही, एनएलएम में 2022 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार चीनी से बने पदार्थ या 'ड्रिंक्स' का सेवन भी किशोरों के खराब मानसिक स्वास्थ्य की बड़ी वजह बन रहा है। जाहिर है कि 'एनर्जी ड्रिंक' या कोल्ड ड्रिंक के नाम पर मिल रहे इस प्रकार के पेय अवसाद का कारण बन सकते हैं। विज्ञान पत्रिका 'फ्रंटियर्स' में 2023 में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक जो किशोर प्रतिदिन सात घंटे से अधिक समय 'स्क्रीन' पर बिताते हैं, उन्हें अवसाद का शिकार बनने की आशंका अन्य की तुलना में दोगुने से भी अधिक होती है।

इस अध्ययन के मुताबिक, अगर कोई सोशल मीडिया पर प्रतिदिन एक घंटे बिताता है, तो उस व्यक्ति में अवसाद के लक्षण प्रतिवर्ष 40 फीसद तक बढ़ जाते हैं। बीएमसी मेडिसिन में 2010 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जो लड़के-लड़कियां किसी तरह के खेल, शारीरिक व्यायाम में भाग नहीं लेते, उनके अवसाद का शिकार बनने की आशंका अधिक होती है। उक्त अध्ययन में यह भी पता चला था कि प्रतिदिन एक घंटे शारीरिक व्यायाम से अवसाद एवं तनाव का जोखिम 95 फीसद तक कम हो जाता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि बच्चों का खेल का समय बढ़ाने और 'स्क्रीन टाइम' घटाने का हर संभव प्रयास किया जाए, लेकिन जो बच्चे पहले ही तनाव और अवसाद का शिकार बन चुके हैं, उन्हें ठीक करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है।

बच्चों को व्यावहारिक बनाने, उन्हें जीवन की वास्तविकताओं से अवगत कराने और जीवन के उतार-चढ़ाव को साझा करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि मस्तिष्क का विकास जीवन और अनुभव के साथ होता जाता है। इसके अलावा, प्रतिदिन कम से कम एक बार पूरे परिवार को एक साथ भोजन अवश्य करना चाहिए। इस दौरान मोबाइल, टीवी आदि इलेक्ट्रानिक उपकरणों से दूरी बनी रहे, क्योंकि इससे परिवार में सामंजस्य बढ़ता है। बच्चों से संबंधित शोध एवं अध्ययन करने वाला प्रसिद्ध शोध संस्थान 'मरडोक चिल्ड्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट' के तत्त्वावधान में किए गए इस अध्ययन में यह बताया गया है कि इन मामलों में चिकित्सीय देखभाल से अधिक जरूरत बच्चों को इन मानसिक बीमारियों से बचाने को लेकर रणनीति बनाने की है। वहीं, डब्लूएचओ एवं यूनिसेफ की 'मेंटल हेल्थ आफ चिल्ड्रेन एंड यंग पीपल' नामक रपट में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए समुदाय आधारित माडल तैयार करने की बात कही गई है।

साहचर्य का सौंदर्य

मोहम्मद जुबैर

वक्त के साथ दुनिया में विकास होने का दावा किया जा रहा है। इसी क्रम में उम्मीद की जाती है कि इसी अनुपात में समाज का भी विकास हुआ होगा। बहुत सारे लोगों की अपेक्षाओं और समझ के मुताबिक ऐसा हो भी रहा है। मगर शहरों-महानगरों में परिवार से लेकर नाते-रिश्ते और जान-पहचान तक में रिश्तों का जो स्वरूप पहले था या फिर जिसकी उम्मीद की जाती है, क्या वह उसी रूप में आज भी हमें दिखता है? सच यह है कि आभासी दुनिया में संबंधों के आभासी विस्तार के दौर में जमीनी स्तर पर आपसी रिश्तों की गांठ ढीली होती जा रही है। यहां तक कि सात जन्मों की शर्त वाले रिश्ते भी पल भर में दम तोड़ दे रहे हैं। दरअसल, देखते-देखते आज बहुत कुछ बदल चुका है। पहले संयुक्त परिवार होते थे। जब इसे बोझ के रूप में देखा-समझा गया तब फिर एकल परिवार का चलन बढ़ा। यहां तक गनीमत थी। लेकिन इसकी हद तब देखी जाने लगी, जब अपूर्ण परिवार की नौबत आने लगी। एक दशक पहले तक जो मामले कुछ हजार में होते थे, अब लाखों में होने लगे हैं। यह रिश्ता जो किसी किताब के एक पन्ने के दो पेज की तरह होता है, उनकी पहचान भले अलग-अलग होती है, लेकिन वजूद एक होता है। जब ये रिश्ते टूटते हैं या फिर लोग अलग-अलग होते हैं, तो उनका अस्तित्व मटियामेट हो जाता है। दोनों पहचानें वजूद को चीरते हुए अलग होती हैं। सही मायने में न तो पन्ना रह जाता है, न किताब।

रिश्तों में भावों के क्षणिक उतार-चढ़ाव का रंग गहरा होता जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे चंद सेकंड की अवधि के वीडियो देखते हुए पलक झपकने के पहले रोमांटिक दृश्य और झपकने के बाद बेरुखी का दृश्य। संबंध विच्छेद के कई कारणों में से एक कारण सोशल मीडिया भी है। इसने हमारे भावों के स्थायित्व को कमजोर किया है। हम अपने भावों को सोशल मीडिया की रगों में रंगते जा रहे हैं, जहां सब त्वरित हो रहा है। रंग चढ़ना लाजिमी भी है। लोग लगभग प्रतिदिन इन्हीं भावों के उतार-चढ़ाव के सागर में घंटों डूबकी लगा रहे हैं। यह सच है कि सोशल मीडिया ने दुनिया को एक गांव में बदल दिया है, लेकिन गलत यह भी नहीं है कि इसने गांव के भीतर भी विभाजन बढ़ा दिया है। यानी सोशल मीडिया ने दूरियां घटाईं तो जमीनी स्तर पर फासले भी बढ़ा दिए हैं। हमें इस बात को स्वीकारना होगा कि हमारा ध्यान पारिवारिक रिश्तों में कुछ कमजोर हुआ है और हम 'वर्चुअल' यानी आभासी रिश्तों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। रिश्तों में दरार की एक वजह यह भी है कि हम आभासी दुनिया को आदर्श मानने लगे हैं, जहां हम उन्हीं दृश्यों को देख पाते हैं, जो सिर्फ दिखने- दिखाने के उद्देश्य से पूरी रणनीति के साथ परोसे जा रहे हैं। हम उन्हें ही अपने जीवन में उतारने के प्रयास में लगे हैं, जो व्यावहारिक नहीं है। इस जद्दोजहद ने लोगों में असंतोष, हीनभावना, कुंठा, भौतिकता आदि को बढ़ाया है। इससे न केवल लोगों की आदतें बदली हैं, बल्कि सोच पर भी गहरा असर पड़ा है।

एक पहलू यह भी है कि आज सहनशीलता लगभग खत्म हो चुकी है, जिस वजह से हम एक-दूसरे की जरा-सी बात को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसके कारण नई पीढ़ी रिश्तों को खत्म करते हुए जरा नहीं हिचकिचाती। 'रील कल्चर' ने 'परफेक्शन' यानी संपूर्णता के आग्रह को भी बढ़ावा दिया है। हम एक ही शख्स में हर खूबी तलाश रहे हैं, जो लगभग असंभव है। रिश्तों में त्याग, सहिष्णुता और सामंजस्य में कमी आई है। भावनाएं कम, नफा-नुकसान का हिसाब ज्यादा हावी होता जा रहा है। हर जगह हर बात के औचित्य की अनिवार्यता को शर्त में खोजने के बजाय इसे सहमति आधारित बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए कभी-कभी जीवन में कुछ लापरवाहियां, गलतियां हल्के-फुल्के अंदाज में जीना और छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करना भी जरूरी होता है। कुछ लापरवाहियां अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि वे हमें खुश रहने और अपने असली स्वभाव को महसूस करने का मौका देती हैं। ये हमारे जीवन के तनाव को कम करके रिश्तों को नया नजरिया देती हैं। सुकरात कहते हैं कि एक शिक्षित मन की यह पहचान है कि वह किसी भी विचार को स्वीकार किए बिना उसके साथ सहज रहे।

दुनिया मेरे आगे

> **हम अपने भावों को सोशल मीडिया की रगों में रंगते जा रहे हैं, जहां सब त्वरित हो रहा है। लोग लगभग प्रतिदिन इन्हीं भावों के उतार-चढ़ाव के सागर में घंटों डुबकी लगा रहे हैं। यह सच है कि सोशल मीडिया ने दुनिया को एक गांव में बदल दिया है, लेकिन गलत यह भी नहीं है कि इसने गांव के भीतर भी विभाजन बढ़ा दिया है।**

पहले लोग रिश्तों को जिम्मेदारी और कर्तव्यों के रूप में देखते थे, जबकि अब लोग रिश्तों से व्यक्तिगत खुशी और संतुष्टि की उम्मीद रखते हैं। अगर इस प्रकार की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं तो विच्छेद विकल्प बन रहा है। हम यह क्यों भूल रहे हैं कि रिश्तों के कमजोर होने के कारण हमारे मूल्य और हमारी परंपराएं भी खतरे में पड़ सकती हैं और आने वाली पीढ़ी का भविष्य जोखिम में पड़ सकता है। इससे हमारी हजारों वर्षों की निर्मित संस्कृति और संस्थाओं का स्वरूप धराशायी हो सकता है। सार्त्र कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता एक दायित्व के रूप में आती है। समाज के नागरिक होने के नाते हमारे भी कुछ दायित्व हैं कि हम अपनी विरासत को और विकसित कर आगे आने वाली पीढ़ी को सौंपे। अपूर्ण परिवार जीवन को पूर्ण नहीं कर सकता है। मानव जीवन केवल संतुलन और साहचर्य में ही पूर्ण होता है। जीवन में मधुरता रिश्तों में प्रेम, सम्मान और त्याग से ही संभव है। वर्तमान में सबसे अमीर वही है, जिसने संबंधों को सहेजकर रखा है।

तकनीक के पांव

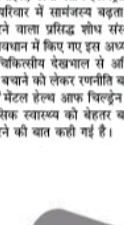

अभी हाल ही में हमने देखा कि हमारे पड़ोसी देश चीन ने 'डीपसीक' एआइ का विकास किया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस नए ऐप से भारत में सर्वाधिक डाउनलोड होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम भारतीय नई चीजों को बहुत आसानी से अपनाने लगे हैं। ऊपर से भारत आबादी के हिसाब से विश्व में सबसे अग्रणी है। युवा बहुल भारत में एआइ के प्रति जिज्ञासा भी बहुत ज्यादा है। लोग नई तकनीक को आजमाने या अपनाने में आगे रहते हैं। ऐसे में 'डीपसीक' का भारत में सबसे ज्यादा डाउनलोड होना स्वाभाविक है। इसकी जबरदस्त कामयाबी पर वैश्विक तकनीकी कंपनियों की ओर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दुनिया को मानो एक नई क्रांति का अहसास हो रहा है। इसके मुकाबले अब 'पैटजीपीटी' को बड़े पैमाने पर निवेश और नवाचार की जरूरत पड़ेगी। सचमुच 'डीपसीक' ने अचानक आकर चैट जीपीटी को नई टक्कर दे दी है। बहरहाल, एआइ की दुनिया में भारत आज कहां खड़ा है? क्या हम केवल उपभोक्ता बने रहेंगे? हम डेटा सुरक्षा की बात कर रहे हैं, पर क्या दिग्गज एआइ कंपनियों से अपना डेटा बचा पाएंगे? ऐसे तमाम सवाल आज हमारे सामने खड़े हैं।

- सुदर्शन सोलंकी, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड

कैंसर के जोखिम

निरोगी काया जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि और अमीरी भी है। यह मुखद ही है कि वर्तमान दौर में मनुष्य कई बीमारियों से ग्रस्त हो रहा है। जिनमें कैंसर के आंकड़े डराते नजर आ रहे हैं। चिंता की बात है कि यह जानलेवा बीमारी पैर पसारती जा रही है। मध्यप्रदेश में मुंह के कैंसर के 64 फीसद मरीज 35 से 54 वर्ष की उम्र के है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि युवावर्ग कितना नशा करता है। इसमें कोई दो मत नहीं कि ग्रामीण अंचलों और शहरी क्षेत्रों में छोटे-छोटे बच्चे और युवा बीड़ी-सिगरेट का धुआं उड़ाते देखे जा सकते हैं। कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक भोपाल में प्रति एक लाख पुरुष आबादी पर कैंसर मरीजों की संख्या 106.7 है। इनमें 19 फीसद को मुख कैंसर है। यानी कैंसर मरीजों में से हर छठा व्यक्ति मुंह के कैंसर से जूझ रहा है। हालांकि कैंसर विशेषज्ञों का मानना है कि खानों का प्रदूषण भी इस रोग की वजह है। इसलिए बच्चों और युवाओं को नशे सेवन से बचाना होगा।

- योगेश जोशी, बड़वाह

बुजुर्गों की देखभाल

'उपेक्षा का दंश झेलते बुजुर्ग' (आलेख, 4 फरवरी) में देशभर के बुजुर्गों की समस्या को गंभीरता से उठाया गया है। बुजुर्ग घर की रौनक होते हैं, पर दुर्भाग्य से कई भारतीय परिवारों में इनकी उपेक्षा होती है। ये बुजुर्ग ही हैं, जिनकी वजह से परिवार को न सिर्फ अनुभव मिलते हैं बल्कि घर में अनुशासन भी रहता है। बुजुर्ग हमारे समाज की अमूल्य पूंजी हैं। प्राचीन समय में भारतीय समाज में बुजुर्गों का हमेशा सम्माननीय स्थान रहा है, लेकिन एक मार्गदर्शक और पारिवार का मुखिया होने के नाते जो सम्मान बुजुर्गों को मिलना था, उसमें धीरे-धीरे कमी आ रही है। घर में ही अपने बच्चों की उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। परिवार की शान कहे जाने वाले हमारे बड़े-बुजुर्ग आज अपने ही अस्तित्व को तलाशते नजर आ रहे हैं। आज भी कई ऐसे परिवार हैं, जहां बुजुर्ग ही सर्वेसर्वा हैं। जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है, वह सुंदर हो जाता है। बुजुर्गों की देखभाल परिवार को करनी चाहिए।

- साजिद अली, चंदन नगर, इंदौर

सेवानिवृत्ति के बाद

हर अधिकारी व कर्मचारी को समय रहते अपनी सेवानिवृत्ति के बारे में सोचना चाहिए। सेवानिवृत्ति के बाद आपको एक साधारण व्यक्ति ही कहा जाएगा। इसलिए, अपनी पिछली नौकरी या व्यवसाय की मानसिकता और श्रेष्ठता की भावना से चिपके न रहें। अगर पहले से अपनी कोई दिनचर्या निर्धारित नहीं की गई, तो सेवानिवृत्ति के बाद अत्यधिक खालीपन महसूस होगा। इसलिए एक नियमित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी है। हमउम्र लोगों के साथ बातचीत करते रहें। समय पर खेएं और पौष्टिक भोजन करें। हर दिन कोई न कोई अच्छा कार्य करें। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। याद रखिए कि शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य से ही हम गुणवत्तापूर्ण जीवन जी सकते हैं। साथ ही सामाजिक मेलजोल बढ़ाए। लोगों के सुख-दुख में भागीदार बनें। इससे सेवानिवृत्ति के बाद अलग-थलग महसूस नहीं करेंगे।

- राजेंद्र कुमावत, जयपुर

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

अवैध आप्रवासी

अमेरिका से निष्कासन

अवैध आप्रवासियों का अमेरिका से बड़े पैमाने पर निष्कासन गहरी सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों से निपटने तथा मानव-व्यापार पर लगाम लगाने की आवश्यकता स्पष्ट करता है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 205 अवैध भारतीय आप्रवासियों का निष्कासन भारत के लिए परेशान करने वाली घटना है। अमेरिका सरकार ने लंबे समय से आप्रवास नीतियों पर कठोर दृष्टिकोण अपना रखा है और खासकर ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आर्थिक स्थायित्व पर जोर दिया है। अवैध आप्रवासियों में वीसा की अवधि से अधिक समय तक रुकने या अवैध तरीकों से प्रवेश करने वालों को अक्सर निष्कासन का खतरा उठाना पड़ता है। इनमें से अनेक लोगों ने अमेरिका में अवैध तरीकों का प्रयोग कर प्रवेश किया था जिसे आमतौर से 'डंकी रूट' कहा जाता है। उन्होंने इस घुसपैठ के लिए लाखों रुपये खर्च किए थे। अवैध आप्रवासियों पर कार्रवाई अमेरिका के व्यापक आप्रवास नियम लागू करने के प्रयासों का अंग है। मैक्सिको व कोलम्बिया समेत कई देशों के नागरिकों को बड़े पैमाने पर निष्कासित किया गया है। सीमा सुरक्षा तथा आवास के विधिक तरीकों पर ज्यादा जोर देने के कारण बिना समुचित दस्तावेजों वाले लोगों को उनके मूल देशों को प्रत्यर्पित किया जा रहा है। भारत के लिए यह व्यापक निष्कासन अनेक स्तरों पर परेशानी का कारण है। पहला, इससे भारत की प्रवासन व्यवस्था में कमियों का पता चलता है और इसमें अनेक ऐसे लोगों का निष्कासन

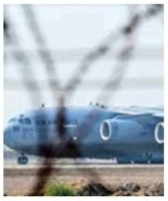

शामिल है जो विदेशों में बेहतर जीवनशैली की इच्छा से आप्रवास के अवैध तरीके अपनाते हैं।

पंजाब तथा अनेक अन्य राज्यों में अमेरिका या यूरोप अवैध तरीके से जाने की प्रक्रिया में तेजी आई है जिससे सामाजिक-आर्थिक तनाव, अवसरों की कमी तथा पश्चिम में संभावित बेहतर जीवन का लालच शामिल है। इसके साथ ही इस घटना ने भारत का वैश्विक सम्मान घटाया है और इसे ऐसे देश के रूप में पेश किया है जहां नागरिकों को आजीविका पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसके साथ ही इससे राज्य सरकारों व खासकर पंजाब का सम्मान गिरता है जहां अवैध एजेंट और मानव-व्यापारी विदेशों में बेहतर भविष्य की तलाश करने वाले संकटग्रस्त लोगों से लाभ उठाते हैं। भविष्य में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए भारत सरकार को कुशल और अकुशल कामगारों के प्रवासन के ज्यादा विधिक तरीके खोजने पर काम करना चाहिए। अमेरिका, कनाडा और आस्ट्रेलिया जैसे देशों में सुनियोजित काम के लिए समझौतों के आधार पर वीसा देने से अवैध तरीकों से लोगों के प्रवासन पर रोक लगेगी। लोगों को अवैध आप्रवास के खतरों से जागरूक करने के अभियानों की जरूरत है। पंजाब के एनआरआई मामलों के मंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे प्रवासन के पहले आवश्यक कौशल और शिक्षा प्राप्त करें। लेकिन इसके साथ ही धोखाधड़ी करने वालों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है जो अमेरिका और यूरोप में बसाने के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाते हैं। इस विभीषिका को जड़ से समाप्त करने के लिए ऐसे लोगों और उनके नेटवर्कों के खिलाफ भारी जुर्माने समेत कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। अवैध आप्रवास का प्रमुख कारण भारत में समुचित रोजगार अवसरों की कमी है। ऐसे में एक जीवन्त आर्थिक रणनीति का लक्ष्य, खासकर ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में समुचित रोजगार सृजन होना चाहिए जिससे लोग जोखिम वाले प्रवासन विकल्पों से बचेंगे। इसके साथ ही भारत सरकार को अमेरिका जैसे देशों के साथ सक्रिय राजनय में शामिल हो कर विदेशों में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों के लिए राहत देने या वैकल्पिक मार्ग तलाशने के प्रयास करने चाहिए। इनमें खासकर ऐसे अवैध आप्रवासी शामिल हैं जिन्होंने अमेरिका या अन्य देशों की अर्थव्यवस्था में काफी योगदान किया है।

शिक्षा में गांधीवादी मूल्यों का महत्व

गांधीवादी मूल्यों- प्रतिबद्धता, त्याग व सेवा के क्षरण से शिक्षा का उसके नैतिक व सामाजिक दायित्वों से संबंध विच्छेद हो गया है।

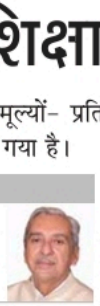

जे एस राजपूत
(लेखक, सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं)

भारत में स्वतंत्रता के बाद शिक्षा प्रयास जल्दबाजी में शुरू किए गए जिनका उद्देश्य बहुत कम समय में बहुत अधिक प्राप्त करना था और ऐसे प्रयास भी मानवीय व भौतिक संसाधनों की भारी कमी के समय में किए गए। राष्ट्र पर इसके दीर्घकालीन प्रभाव बहुत हानिकारक पड़े हैं क्योंकि अब उसे निष्प्रभावी स्कूलों, गायब शिक्षकों तथा फर्जी शिक्षकों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे विश्लेषण के अनुसार हमारे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की या तो अनदेखी हुई है, उनको भुला दिया गया है अथवा वे उन मूल्यों का महत्व नहीं समझ रहे हैं जिन्होंने पूरे राष्ट्र को एक साथ जोड़ा है। महात्मा गांधी के नेतृत्व ने प्रतिबद्धता, त्याग, दूसरों की देखभाल तथा राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान करने जैसे मूल्यों को पैदा किया था। आमतौर से इनको सामान्य बोलचाल की भाषा में गांधीवादी मूल्य कहा जाता है। दुर्भाग्य से देश का प्रबंधन करने वाली पीढ़ियों के परिवर्तन के साथ ही व्यावहारिक रूप से हर क्षेत्र में गांधीवादी मूल्यों की अनदेखी हुई है। शिक्षकों और शिक्षा से हमेशा बहुत उम्मीदें रही हैं। उम्मीद की जाती है कि वे मानक, समुचित व्यवहार, आदर्श, नैतिकता तथा मूल्यों की स्थापना करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से मूल्यों के गायब होने की यह अवधारणा शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों को प्रभावित कर रही है। प्रख्यात शिक्षाशास्त्री डी.डी. कोठारी ने कहा है, 'शिक्षा का आधारभूत लक्ष्य, शिक्षा से सभी स्तरों पर मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाना, विशेष कौशल प्राप्त करना तथा ज्ञान को आगे बढ़ाना है।

लेकिन इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण युवा पीढ़ी में सोद्देश्यता तथा मिशन, प्रतिबद्धता तथा अपने और देश के भविष्य के प्रति विश्वास पैदा करना है। नैतिक शिक्षा का महत्व रेखांकित करना तथा किसी भी सेक्युलर या अन्य समाज में नैतिक मूल्यों तथा सामाजिक जिम्मेदारी की भावनाओं का प्रोत्साहन देना सबसे जरूरी है।' इन वाक्यों को बार-बार पढ़े जाने की आवश्यकता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण इसके प्रति 'मनन' और परस्पर विचार-विमर्श वाली प्रक्रिया से 'चिंतन' की आवश्यकता है। इस पर गंभीर पुनर्विचार की आवश्यकता है जिसकी शुरुआत स्कूलों से होनी चाहिए और इसे उच्च शिक्षण संस्थानों तक ले जाना चाहिए। 21वीं शताब्दी के वर्तमान संदर्भ में इस बिंदु पर विचार कर मैं एक प्रमुख बिंदु पर जोर देना चाहूंगा। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा को समग्र रूप से देखने तथा इसके अतीत व वर्तमान को समझने के साथ ही भविष्य के लिए इसकी कल्पना करने वाले डा. डी.एस. कोठारी एक महान भौतिकवादी शोधकर्ता तथा महान शिक्षाशास्त्री थे। आध्यात्मिकता तथा ज्ञान के सृजन, हस्तांतरण व प्रयोग की भारतीय परंपरा पर उनकी गहन अंतर्दृष्टि तथा इसका प्रयोग जन कल्याण के लिए करने के अंतर्निहित लक्ष्य से प्रेरित होकर उन्होंने 1964-66 तक शिक्षा पर राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की भूमिका निभाई।

उनकी व्यावहारिकता, समझदारी और दृष्टिकोण से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा जा सकता है। भारत के लिए भविष्य की उनकी कल्पना में कुछ महत्वपूर्ण, पर सरल और सार्थक अवधारणा- 'एसटीपीजी' सामने आती है। भारत और भारतीय शिक्षा को 'विज्ञान, तकनीक, उत्पादन और गांधी' पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। निश्चित रूप से पांच दशक पहले इस दृष्टिकोण ने मेरी विचार प्रक्रिया

> **महात्मा गांधी के नेतृत्व ने प्रतिबद्धता, त्याग, दूसरों की देखभाल तथा राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान करने जैसे मूल्यों को पैदा किया था। आमतौर से इनको सामान्य बोलचाल की भाषा में गांधीवादी मूल्य कहा जाता है। दुर्भाग्य से देश का प्रबंधन करने वाली पीढ़ियों के परिवर्तन के साथ ही व्यावहारिक रूप से हर क्षेत्र में गांधीवादी मूल्यों की अनदेखी हुई है।**

को झकझोर दिया था और मेरे भीतर आधुनिक समय को समझने की प्रेरणा पैदा की थी जहां पश्चिमी शिक्षा, विचार और संस्कृति का प्रभुत्व था। कोठारी के सुझाव का अर्थ भारतीय परंपरा, संस्कृति, अतीत की समस्याओं तथा पश्चिमी ज्ञान प्रणाली की गहरी विश्लेषणात्मक समझ है जिसमें कोई पूर्वाग्रह या 'केवल पहले से बनाई प्रेरणा' न शामिल हो।

भले ही यह व्यक्तिगत लगता हो, पर प्रोफेसर कोठारी को सुन कर मेरे पढ़ने की दिलचस्पी बदल गई और शिक्षा में परिवर्तन के प्रति मेरा पूरा दृष्टिकोण भी बदल गया। लेकिन दुर्भाग्य से डा. कोठारी द्वारा प्रस्तावित चतुरंग-एसटीपीजी में गांधीजी पर कभी आवश्यकतानुसार ध्यान नहीं दिया गया। गांधीवादी मूल्यों की यह अनदेखी स्कूलों से विश्वविद्यालयों तक दिखाई देती है, हालांकि इसके कुछ अपवाद हैं। यदि कोई अपने दृष्टिकोण का विस्तार करे तो निश्चित रूप से इसके प्रभाव व्यापक व दूरगामी होंगे। सरल शब्दों में यह पूछा जा सकता है कि क्या भारत ने शिक्षा के मूल उद्देश्य की अनदेखी की है? शिक्षा व्यवस्था के प्रभावों पर गंभीरता से विचार करने पर स्पष्ट होता है कि शिक्षकों को हमेशा इसके केन्द्र में रखा जाना चाहिए।

हम सबका और हमारे धर्मों का अंतिम लक्ष्य एक ही है। यह बार-बार दुहराया जाना चाहिए कि हमारे देश के सभी सरकारी स्कूलों में व्यावहारिक रूप से हर भारतीय शिक्षक बहु-धार्मिक कक्षाओं में पढ़ाता है, यानी उनमें कई प्रकार के धार्मिक व्यवहार करने वाले परिवारों के छात्र शामिल होते हैं। इसलिए उसे विभिन्न प्रकार की विविधताओं के सौंदर्य तथा आयामों से सर्वोत्तम तरीके से परिचित और सहमत होना चाहिए जो प्रकृति ने भारतीयों को वरदान में दी हैं। इन सुंदर विविधताओं में धार्मिक विविधतायें भी शामिल हैं।

एक एकीकृत, सुगठित तथा समन्वित भारत के भविष्य को बनाने वाले की जिम्मेदारी स्वीकार करने वाले शिक्षकों को सभी महान भारतीय ग्रंथों के खजाने की जानकारी होनी चाहिए। इनमें से सबका धार्मिक होना जरूरी नहीं है, पर वे 'संतुष्ट, सहयोगी एवं रचनात्मक' जीवन के निर्देशक के रूप में काम करते हैं। शिक्षक को पूर्व पूर्वाग्रहों और दुराग्रहों से मुक्त होना चाहिए। इस संबंध में दिलचस्पी रखने वालों को महात्मा गांधी के उस संबोधन से प्रेरणा लेनी चाहिए जो उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के समक्ष दिया था। गांधीजी ने कहा था, 'अपने बचपन में मैं ऐसे धर्मग्रंथ की आवश्यकता अनुभव करता था जो जीवन की सभी परीक्षाओं और लालसाओं में मेरे लिए असंदिग्ध निर्देशक का काम करे। आज गीता न केवल मेरी बाइबिल या मेरी कुरान, बल्कि उससे भी अधिक है।

वह मेरी मां है। बड़ी संख्या में संस्थान भारतीय ज्ञान परंपरा-आईकेएस के गंभीर अध्ययन व शोध में लगे हुए हैं। इन अध्ययनों में सेक्युलरिज्म की गलत व्याख्याओं के बावजूद उम्मीद की जाती है ये प्राचीन धर्मग्रंथों तथा उनकी समकालीन प्रासंगिकता की अनदेखी नहीं करेंगे।

दोषारोपण के खेल से मुक्ति

> **जब हम अपने कार्यों की कम से कम आंतरिक रूप से जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तो हम खुद को क्या नुकसान पहुंचाते हैं? हम अपनी कमियों को सुधारने के लिए कुछ नहीं करेंगे। वे हमें परेशान करती रहेंगी।**

अजीत बिश्नोई
(लेखक, आध्यात्मिक उपदेशक हैं)

हम सभी अपने दुखों के लिए दूसरों को दोषी ठहराने के आदी हैं। कुछ अपवाद हैं, ज्यादातर भगवान के भक्त। हम लगभग सहज रूप से ऐसा क्यों करते हैं? इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो यह कि ऐसा करना आसान है। इस तरह हमें अपने दुखों की जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती, हालांकि यह कर्मफल सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है, जिसका अर्थ है, हम जो बोते हैं, वही काटते हैं। हम अपने मन, वाणी और शरीर से हमेशा कर्म करते रहते हैं।

हम ऐसा नहीं सोचते, लेकिन यह सच है। जब हमारे मन में डरावने विचार आते हैं, तो शरीर में पसीना आना, दिल की धड़कनें बढ़ जाना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। जहां तक वाणी का सवाल है, हम जानते हैं कि जब हम अच्छा बोलते हैं, तो हमें इनाम मिलता है। दूसरी ओर, गुस्सा करना या किसी को गाली देना भी इसी तरह की प्रतिक्रियाएं पैदा करता है।

शारीरिक कार्य जैसे कि किसी दफ्तर में काम करने से हमें वेतन मिलता है। हालांकि, कुछ कार्य तुरंत परिणाम या फल नहीं देते हैं, वे भविष्य में, यहां तक कि अगले जन्मों में भी ऐसा करते हैं। हमारे सभी कार्य ईश्वरीय सत्ता द्वारा विधिवत दर्ज किए जाते हैं; वे ठीक से जानते हैं कि हम क्या करते हैं। उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। यह भगवान की व्यवस्था है जिसके अधीन वे काम करते हैं। (भगवद गीता 9.10) दूसरा कारण यह स्वीकार करना है कि हम वास्तव में बहुत छोटे और बहुत अज्ञानी हैं। हमने अतीत में गलतियां की हैं। इससे हमारे अहंकार को ठेस पहुंचती है। हमसे इतर सभी गलतियाँ कर सकते हैं और करते भी हैं। श्रेष्ठता की भावना, जिसे हम पोषित करने के लिए खुद को बहलाते हैं,

वह कम हो जाती है। जब हम अपने कार्यों की कम से कम आंतरिक रूप से जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तो हम खुद को क्या नुकसान पहुंचाते हैं? हम अपनी कमियों को सुधारने के लिए कुछ नहीं करेंगे। वे हमें परेशान करती रहेंगी। क्योंकि हम ही अपनी कमियों को सुधार सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। हमें यह तय करने की स्वतंत्र इच्छा है कि हम क्या करें। और दूसरों में कमियाँ ढूँढ़ने से कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि वे सिर्फ़ इसलिए खुद को नहीं सुधारेंगे क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं। इसलिए, जो भी हमारी परेशानियों का कारण है, वह बना रहता है। कोई यह बता सकता है कि कई बार अजनबी लोग हमें शराबी ड्राइवर की तरह परेशान करते हैं। हाँ, यह सच है, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने हमें परेशान करने के लिए केवल एक माध्यम के रूप में कार्य किया, क्योंकि यह कर्मफल सिद्धांत के अनुसार नियत था। यह वास्तविकता है। प्राकृतिक शक्तियों द्वारा हमें दिए गए कष्टों के बारे में भी यही सच है। भगवान ने हमें चेतावनी दी है कि इस दुख के स्थान पर ऐसा होगा। (8.15) फिर, हम लोगों को दुश्मन बना लेते हैं, जिन पर हम दोष लगाते हैं। ये अधिकतर निकट और प्रिय लोग होते हैं, जिनके साथ हम जुड़ते हैं।

आपको क्या लगता है कि पारिवारिक झगड़ों का मुख्य कारण क्या है? जब कुछ गलत होता है तो यह दोषारोपण का खेल होता है। ये वे लोग हैं, जो हमारे मन की शांति के लिए महत्वपूर्ण हैं। हम भगवान को भी खुश नहीं करते, क्योंकि हमने जो गलत किया है उसके लिए दूसरों को दोष देना धर्म के विरुद्ध है। इस तरह हम खुद को उस एकमात्र इकाई से दूर कर लेते हैं, जो हमारी खामियों को ठीक करने में हमारी मदद कर सकती है, खासकर हमारे स्वभाव में। भगवान ने हमें सभी परेशानियों से बाहर निकालने का वादा किया है यदि हम ईश्वरीय चेतना विकसित करें। (18.58) लेकिन क्या हम सुनेंगे? समाधान क्या है? इस अहसास से शुरू करें कि हम गलत हैं; हम अतीत की तरह गलतियां करेंगे। हमें ऐसा करना ही होगा, अन्यथा हम जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं बंधे रहेंगे। इस संबंध में विनम्रता का गुण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सभी पारस्परिक संबंधों में है। आध्यात्मिक अभ्यास करना शुरू करना, जो हमारे स्वभाव के अनुकूल हो, निश्चित रूप से बहुत मदद करेगा। क्यों? भगवान तस्वीर में आते हैं। वह हममें रुचि लेना शुरू करते हैं। मैंने यही किया है, और मेरा विश्वास करो परिणाम अविश्वसनीय हैं। मेरे भगवान मेरे जीवन का सूक्ष्म प्रबंधन कर रहे हैं। छोटे-छोटे चमत्कार हर समय होते रहते हैं जो मुझे चकित कर देते हैं।

आप की बात

अवैध घुसपैठिये

घुसपैठिए विश्व के किसी भी कोने में हो, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना अपेक्षित है। अपने राष्ट्र की सुदृढ़ता के लिए देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अपने देश के नागरिकों का ही होना चाहिए। अन्य देश के नागरिकों का नहीं। विडम्बना है कि भारत में कोटों की राजनीति के चलते अवैध घुसपैठियों को कुछ राजनीतिक दलों का खुला संरक्षण प्राप्त है, जिस कारण बरसों से भारत में वे फल फूल रहे हैं। हाल ही में अमेरिका ने विदेशी घुसपैठियों पर कठोर कार्रवाई करते हुए अमानवीय तरीक़े से उनके देशों में वापस भेजा है। कुछ भारतीयों के साथ भी अमेरिका ने ऐसा ही अमानवीय व्यवहार किया है, जिसे देखकर प्रत्येक भारतीय को क्रोध आना स्वाभाविक है। सरकार को हर घटना पर निशाने पर लेने वाला देश का विपक्ष इस वापसी को सत्ता पक्ष की कमजोरी सिद्ध करने पर तुला है, जैसे देश की सत्ता ने उन्हें जबरन अमेरिका में बसने के लिए विवश किया हो। वहरहाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घुसपैठियों के सम्बंध में मानक तय होने ही चाहिएं, कि किन घुसपैठियों को किस देश में रहने का अधिकार मिले, किस देश में नहीं। भारत में सभी दलों को मिलकर यह अभियान चलाना चाहिए कि भारत भूमि पर बोझ बने रोहिंग्या और बंगला देशी घुसपैठियों को भी उसी प्रकार उनके देशों में वापस भेजा जाए, जिस प्रकार अमेरिका ने भारतीय घुसपैठियों को भारत में भेजा है।

– **सुधाकर आशावादी**, मेरठ

जाति की गणना पर जोर

पटना पहुंच कर राहुल गांधी ने जाति गणना पर जोर देते हुए कहा कि बिना इसके दलितों ,आदिवासियों और पिछड़ों का विकास नहीं होगा लेकिन नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते जाति गणना क्यों नहीं हुई ,इसके बावजूद भी इनका विकास हुआ । हां ये जरूर है कि जाति गणना से सरकार को यह जानने में मदद मिलती है कि किन जातियों को विशेष सहायता और संसाधनों की आवश्यकता है। यह समाज के वंचित वर्गों के उत्थान में सहायक हो सकता है। जाति आधारित आर्थिक असमानताओं को समझने और उन्हें दूर करने के लिए जाति गणना आवश्यक है। इससे सरकार को योजनाएं बनाने में मदद मिलती है। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रणाली के सफल कार्यान्वयन के लिए जाति गणना महत्वपूर्ण है। इससे समाज के सभी वर्गों को शैक्षिक अवसरों का लाभ मिल सकता है लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि जाति गणना से समाज में जातिगत भेदभाव और बंटवारे को बढ़ावा मिल सकता है। इससे सामाजिक सामंजस्य में बाधा आ सकती है। लोगों की जातिगत जानकारी एकत्र करना उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। यह मुद्दा संवेदनशील है जाति गणना के आंकड़ों का राजनीतिक दुरुपयोग भी संभव है। चुनावी राजनीति में जाति की भूमिका और महत्व को देखते हुए, इस जानकारी का गलत इस्तेमाल हो सकता है।

– **भगवानदास छारिया**, इंदौर

संवाद की जरूरत

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिया गया बयान, अगर ईरान मेरी हत्या करता है, तो उसे तबाह कर दिया जाए ,अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर चुका है। यह बयान न केवल अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का प्रतीक है, बल्कि वैश्विक शांति के लिए एक गहरी चुनौती भी है। ऐसे वक्त में, जब विश्व को सहयोग और संवाद की आवश्यकता है, इस तरह के तीखे शब्द तनाव को और बढ़ा सकते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से विवाद जारी है। इस तरह के बयान केवल आग में घी डालने का काम करते हैं। राजनैतिक और कूटनीतिक दृष्टि से ऐसे कदम अंतरराष्ट्रीय स्थिरता को कमजोर कर सकते हैं। वैश्विक मंच पर जिम्मेदार नेतृत्व की अपेक्षा होती है कि वह हिंसा के बजाय संवाद और समाधान को प्राथमिकता दे। इतिहास गवाह है कि युद्ध और टकराव केवल विनाश और दर्द लाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, राजनयिक उपायों को प्राथमिकता देते हुए वार्ता और शांति के रास्ते तलाशना ही सबसे उचित समाधान है। शक्ति प्रदर्शन और धमकी से कोई भी पक्ष विजेता नहीं बनता। आज समय की मांग है कि विश्व नेता शांति और स्थिरता के लिए मिलकर काम करें। सहयोग, सहिष्णुता और संवाद से ही एक मजबूत और सुरक्षित विश्व की नींव रखी जा सकती है।

– **आर के जैन**, बड़वानी, मप्र

ट्रंप के फैसले

डोनाल्ड ट्रंप कड़े फैसले ले रहे है जो वैश्विक चिंता का विषय है। कठोर नीतियों की नींव में अमेरिका को महान बनाने के अपने वादे उन्हें भले ही आलोचना का पात्र बनाएं पर उनका ऐसा करना भी जरूरी है क्योंकि उन्होंने चुनाव के पूर्व वादे किए थे। जन्मजात नागरिकता कानून और एच-1बी वीजा खत्म करने की घोषणा से अप्रवासी असमंजस में है। अवैध प्रवासन पर रोक के लिए मैक्सिको और कनाडा से आयातित वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की चेतावनी और साथ ही चीन और यूरोपीय संघ पर भी कर बढ़ाने के संकेत की नीतियों से अमेरिका के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर असर पड़ सकता है। टैरिफ बढ़ाने से फरेलू रोजगार और कर राजस्व में वृद्धि की सोच कितनी कारगर साबित होगी लेकिन अमेरिका के मित्र राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होना तय है। हालांकि अमेरिकी कानून-व्यवस्था में राष्ट्रपति के अधिकार सीमित हैं और इसी वजह से ट्रंप के कई फैसले बहस और विरोध का विषय बने हुए हैं। अब बड़ा सवाल यही कि ट्रंप की नीतियां अमेरिकी अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार संतुलन को किस दिशा में ले जाएगी यह देखना दिलचस्प होगा।

– **अमृतलाल मारू**, इंदौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

सम्पादकीय

अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को बेड़ियों में जकड़ कर भेजा गया भारत, तालमेल बिठा कर निकाला जा सकता है गरिमापूर्ण रास्ता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण से पहले ही स्पष्ट कर चुके थे कि वे अवैध प्रवासियों के साथ कड़ाई से निपटेंगे। यहां तक कि उन्होंने एच-वनबी वीजा समाप्त करने की भी घोषणा कर दी थी, मगर कड़े विरोध के कारण उन्होंने अपना कदम रोक लिया था। अब अमेरिका प्रशासन ने एक सौ चार अवैध प्रवासी भारतीयों का पहला जत्था वापस भेज दिया है। बताया जा रहा है कि ऐसे करीब अठारह हजार भारतीय मूल के लोग अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं और उन सभी को वापस भेजा जाएगा। निश्चय ही इस तरह अमेरिका ने भारत सहित दुनिया के तमाम देशों को सख्त संदेश दिया है कि वह अपने आव्रजन कानूनों को सख्ती से लागू कर रहा है। इससे बिना जरूरी कागजात के, अवैध तरीके से, अमेरिका में प्रवेश की कोशिश करने वालों पर लगाम लगेगी। गौरतलब है कि अमेरिका में अवैध घुसपैठ करने वालों में सबसे अधिक लोग भारत के होते हैं। ट्रंप ने कहा था कि ऐसे लोगों की वजह से अमेरिका पर नाहक भारी वित्तीय बोझ पड़ता और सुरक्षा को खतरा पैदा होता है। इसलिए उन सीमाओं पर भारी संख्या में सुरक्षाबल तैनात कर दिए गए हैं, जहां से अवैध प्रवासी प्रवेश करते हैं। कोई भी देश अपने यहां लोगों को अवैध रूप से प्रवेश की इजाजत नहीं देता। युद्ध, अकाल आदि स्थितियों में कुछ लोग पलायन कर दूसरे देशों में शरण लेने का प्रयास करते हैं, उन्हें कुछ समय के लिए नजरअंदाज कर दिया जाता है। मगर रोजी-रोजगार की तलाश में गलत तरीके से प्रवेश करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। इसलिए जब ट्रंप ने अवैध प्रवासियों का मुद्दा उठाया, तो भारत ने कहा कि वह अपने नागरिकों को वापस लेने को तैयार है। मगर अमेरिका चूंकि उन्हें अपराधी मानता है, इसलिए वह उनके साथ उसी तरह निपटना चाहता है। पहली खेप में वापस भेजे गए लोगों को जिस तरह बेड़ियों में जकड़ कर सेना के विमान पर बिठाया गया, वह विचलित करने वाला दृश्य था। जबकि यह हकीकत किसी से छिपी नहीं है कि अवैध रूप से अमेरिका गए लोगों का इरादा किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधियां चलाने का नहीं था। वे बेरोजगारी के मारे हुए लोग हैं और वहां जाकर कुछ बेहतर जीवन जीना चाहते हैं। इसलिए उन्हें वापस भेजते वक्त अपराधियों की तरह परेड कराने के बजाय मानवीय तरीका अपनाने की अपेक्षा गलत नहीं है। भारत के साथ तालमेल करके कोई गरिमापूर्ण रास्ता निकाला जा सकता है। ट्रंप प्रशासन अमेरिकी हितों को सर्वोपरि रखते हुए कठोर पर कठोर फैसले कर रहा है। उसमें आव्रजन नीतियों को कड़ा बनाने पर विशेष बल है। इससे वहां रह रहे भारतीय मूल के लोगों में स्वाभाविक ही भय है। मगर हकीकत यह भी है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भारतीय मूल के लोगों का योगदान महत्त्वपूर्ण है। उन्हें अगर ट्रंप प्रशासन बिना तार्किक आधार के निकालने या रोकने का प्रयास करेगा, तो उसकी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव जल्दी ही दिखना शुरू हो जाएगा। यही वजह है कि ट्रंप के जन्मजात नागरिकता संबंधी संवैधानिक प्रावधान के विरुद्ध फैसले को लेकर विरोध तत्ख हो गया है। उसे वहां की अदालत में चुनौती दी गई है। देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा की चिंता ट्रंप को होनी ही चाहिए, मगर मनमाने तरीके से कानून बदलने और फैसले थोपने को वहां कोई स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए उन्हें विरोधों का सामना करना पड़ रहा है।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आज कई विशेष तारों की युति बनेगी। तब आप यह जानना चाहते हैं कि आपके जीवन के तीसरे भाव में, तब आपके विदेशी कुटुंब लोगों और दूसरी तरफ, आपकी शिक्षा बाधों में लाभकारक रहना संभव। तब एक विदेश यात्रा योग में और संतति सुख को सुखमुक्त करता लाभकारक। उन्हें भी मालूम होगी, वैसे पराक्रमशील लोगों में भी, जब एक लाभकारक रही संतान और कानूनी में लाभ प्रदान करेगा

मेष
पिता तथा अभिभावकों का सहयोग प्राप्त होगा। मन आनंदित रहेगा। फिर भी स्वभाव में उग्रता का असर आपकी वाणी पर न पड़े, इसका ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी मामूली शिकायत रहेगी।

वृष
संतान के अध्ययन या अन्य मामलों के पीछे धन खर्च या पूंजी निवेश होगी। कलाकारों तथा खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने का उत्तम समय है। नौकरी- धंधे में उच्च अधिकारी या भागीदार के क्रोध का शिकार बनना पड़ेगा।

मिथुन
गृहस्थ जीवन में सुख- शांति का अनुभव होगा। मित्रों से मुलाकात होगी। आय में वृद्धि होगी। उत्तम वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी। अविवाहितों का रिश्ता पक्का होने की संभावना बनी रहेगी। आज आपके हरेक कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे।

कर्क
आज यात्रा को टालना हित में होगा। पाचन तंत्र संबंधी कोई तकलीफ हो सकती है। आपके व्यवहार से किसी को हानि न पहुंचे, इसका ध्यान रखें। आज आप सभी काम दृढ़ आत्मविश्वास और मनोबल से पूरा करेंगे। सरकार से लाभ होने की संभावना है।

सिंह
व्यवसाय करने वालों को सरकार की तरफ से लाभ मिलने और नौकरीपेशा को उच्च अधिकारियों की कृपादृष्टि मिलेगी। भाई-बंधुओं और पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।

कन्या
आप पूरे दिन शारीरिक और मानसिक थकान महसूस करेंगे। परिश्रम की अपेक्षा कम सफलता मिलने से निराशा रह सकती है। नौकरी और व्यापार के संबंध में थोड़ा चिंतित रहेंगे। काम की भागदौड़ में परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे।

तुला
लंबे प्रवास का आयोजन संभव होगा। विरोधियों से विजय प्राप्त करेंगे। दिन के दौरान आकस्मिक घटनाओं में व्यस्त रहेंगे। आज आप शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता अनुभव करेंगे। परिणामस्वरूप मन में नकारात्मक विचार पैदा होंगे।

वृश्चिक
शारीरिक अस्वस्थता के साथ-साथ मानसिक चिंता में वृद्धि होगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव होगा। उग्र वाणी और आंख के टकराव से किसी के साथ झगड़े या विवाद की स्थिति बन सकती है।

धनु
किसी के साथ गलतफहमी होने के कारण मनमुटाव हो सकता है। पारिवारिक खातावरण खराब हो सकता है। अत्यधिक धन खर्च होगा। भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ निर्णय के कारण आज आप कोई भी काम त्वरित निर्णय लेकर पूरा करेंगे।

मकर
शारीरिक स्वास्थ्य बना रहेगा। मित्रों, स्नेहीजनों से लाभ होगा। शरीर में थकान और बेचैनी रहेगी। स्वास्थ्य नरम-गरम रहेगा। मन चिंता से व्याकुल रहेगा। आज यात्रा स्थगित रखने की सलाह दी जाती है। संतान के विषय में चिंता रहेगी।

कुंभ
गृहस्थ जीवन में आनंद छाया रहेगा। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नौकरी-व्यवसाय में प्रगति होगी। अधिकारी और घर में बड़ों से लाभ मिलेगा। धन लाभ होगा। व्यापारियों को उधार दिया पैसा मिलेगा। संतान की प्रगति से मन खुश रहेगा।

मीन
कोर्ट-कचहरी का कामों को आज टाल देना हितकर है। आज विविध क्षेत्र में लाभ मिलने से आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और प्रफुल्लित रहेंगे। मित्रों के साथ मुलाकात, रमणीय स्थानों पर प्रवास पर्यटन का आयोजन होगा। भाग्य साथ न देता हुआ प्रतीत होगा।

आज का इतिहास

बढ़ता राजस्थान

7 फरवरी की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- पुशिया एवं आस्ट्रेलिया ने 1792 में फ्रांस के खिलाफ़ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- यूरोपीय देश बेल्जियम ने 1831 में संविधान स्वीकार किया।
- अमेरिका के बाल्टिमोर में 1904 में जबरदस्त आग लगने से पन्द्रह सौ इमारतें जल कर खाक।
- चलती ट्रेन से 1915 में पहली बार भेजा गया वायरलेस संदेश रेलवे स्टेशन को प्राप्त हुआ।
- ब्रिटेन में रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1940 में हुआ।
- यूनाइटेड किंगडम ने थाईलैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा 1942 में की।
- अमेरिका, ब्रिटेन, और रूस ने 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण पर चर्चा की।
- अरब और यहूदियों ने 1947 में फिलीस्तीन को विभाजित करने के ब्रिटेन के प्रस्ताव को खारिज किया।
- क्यूबा से सभी तरह के आयात पर अमेरिका ने 1962 में रोक लगाई।
- जर्मनी की एक कोयला खदान में 1962 में हुए विस्फोट से लगभग 300 मजदूरों की जान गयी।
- अमेरिका ने 1965 में उत्तरी वियतनाम में लगातार हवाई हमले शुरु किये।
- 1983 में कोलकाता में ईस्टर्न न्यूज एजेंसी की स्थापना।
- जापान द्वारा 1987 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस (ए.एन.सी) को मान्यता।
- 1999 में जार्डन के शाह हुसैन की मौत, अब्दुला नये शाह बने।
- वाशिंगटन में भारत और अमेरिका के बीच गठित संयुक्त विरोधी दल की पहली बैठक 7 फरवरी, 2000 को शुरु हुई।
- एरियल शेरोन 7 फरवरी, 2001 में इजरायल के प्रधानमंत्री के रुप में चने गये।
- फ्रांस के प्रधानमंत्री ज्यां पियरे रैफरिन 7 फरवरी, 2003 में भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे।
- नेपाल में स्थानीय निकायों के लिए 7 फरवरी , 2006 में वोटिंग हुई।
- इक्वाडोर का तुंगुराही ज्वालामुखी 7 फरवरी, 2008 को फटा।
- महाराष्ट्र के राज्यपाल एससी जमीर ने 2009 में स्वतंत्र भारत की 12वीं तथा पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को डी लिट् की उपाधि से नवाजा।
- दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 19वां अंतराष्ट्रीय पुस्तक मेला 7 फरवरी, 2010 को खत्म हुआ। आपको बता दें कि यह मेला 9 दिनों तक चला जिसमें करीब 2 हजार प्रकाशकों ने हिस्सा लिया।

7 फरवरी को जन्मे व्यक्ति

- डॉ. भीमराव आम्बेडकर की पत्नी रमाबाई आम्बेडकर का जन्म सन 1898 में हुआ।
- प्रमुख क्रान्तिकारी तथा लेखक मन्मथनाथ गुप्त का जन्म सन 1908 में हुआ।

विशेष आलेख

वेलेंटाइन वीक : जान लो, पहचान लो, जनक और जननी से बड़ा कोई वेलेंटाइन नहीं

सुशील कुमार 'नवीन'

शुक्रवार से वेलेंटाइन वीक की शुरुआत हो रही है। आज के व्यवसायिक दौर की माने तो ये सात दिन प्रेम की अभिव्यक्ति की पराकाष्ठा होते हैं। व्यवहारिक दृष्टि इसके विपरीत है। देखा जाए तो प्रेम किसी पहचान का मोहताज नहीं होता है। प्रेम तो वास्तव में अंतर्मन की वो अभिव्यक्ति और अनुभूति है। न सुनाई पड़ती है और न दिखाई देती है। वह तो सिर्फ महसूस की जा शक्ति है। प्रेम कोई बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध वस्तु नहीं है तो फिर इसका व्यवसायीकरण क्यों? क्या प्रेम के लिए एक प्रेमिका का होना आवश्यक है? जिसने हमें जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया। लड़खड़ाते कदमों को संभाल हमें आगे बढ़ाया। क्या वो प्रेम का अधिकारी नहीं है?

हिंदी के विख्यात साहित्यकार जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध उक्ति है कि यह संसार भी बड़ा प्रपंचमय यंत्र है। वह अपनी मनोहरता पर आप ही मुग्ध रहता है। सीधा सा भाव है कि सरलता सदैव धोखा खाती है। यही वजह है कि जो तुमसे ज्यादा प्रेम करता है, उसकी तुम्हें पहचान ही नहीं हो पाती। चार दिन किसी के साथ तफरी क्या कर ली, वहीं जाने जहां हो जाते हैं। इसके लिए माता-पिता , घर-परिवार की इज्जत भी उछालनी पड़ जाए तो भी परवाह नहीं। माई लाइफ माई राइट कहकर झट से पल्ला झाड़ लेते हो। जब इस माई लाइफ का भूत सर से उतर जाता है तो वापसी के लिए इसके सिवाय कोई और जगह नहीं होती। मैं ये नहीं कहता कि संसार में प्रेम की उपयोगिता या महत्ता नहीं है। पर वेलेंटाइन के नाम पर जो भ्रमजाल लगातार पैर पसार रहा है। उस पर चिंतन बहुत जरूरी है। सबसे पहले जानो कि प्रेम का कोई एक दिन तय नहीं किया जा सकता। जीवन का हर एक क्षण हमें प्रेम और प्रेमालाप करने का अवसर प्रदान करता है। यह कोई उपहारस्वरूपी वस्तु के बदले का मोहताज नहीं होता। यह कभी किसी लालसा को जन्म नहीं देता। यह तो हमें एक ऐसी साधना की राह की ओर अग्रसर करता है जो अथाह है अनन्त है। सुनते रहो! प्रेम कोई समय में बंधने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह तो युग युगांतर तक अमरता को प्राप्त होने वाली ऐसी दिव्य और अलौकिक ज्योति है जिसका प्रकाश कभी मंद हो ही नहीं सकता। प्रेम कभी नहीं कहता कि उसे गुलाब चाहिए, उपहार चाहिए। वह तो सिर्फ आत्मीयता चाहता है। जो सिर्फ पवित्र हृदय से मिलती है। आज के समय में आत्मीयता का प्रेम के रूप में कोई महत्व दिखता ही नहीं है। सुनो! जिसे तुम अट्रैक्शन कहते हो वो कोई अट्रैक्शन नहीं है। वह तो एक अबूझ लालसा है।

जो एक के मिलने के बाद भी पूरी नहीं होती। मन भरा तो मन चरा। यहां ये भी जानना जरूरी है कि प्रेम कोई आकर्षण रूपी क्षणिक भावना नहीं है। प्रेम तो हर जन का अस्तित्व है। उनका अनुपम अलौकिक व्यक्तित्व है। प्रेम को कोई बांध नहीं सकता। क्योंकि प्रेम की कोई सीमा नहीं है। प्रेम तो सीमा का निर्माण करता है। व्यक्ति बदल सकता है पर प्रेम रूपी व्यक्तित्व लाख चाहने पर भी नहीं बदलता। यह तो जानते ही होगे कि ईमान का शरीर, मन और व्यवहार बदलते देर नहीं लगाता। पर प्रेम हर व्यक्तित्व से परे अपरिवर्तनशील है। प्रेम कोई उत्तेजना नहीं है यह तो निष्काम मन का समर्पण है। प्रेम कोई विचार नहीं यह तो अभिव्यक्ति है। प्रेम कोई दृश्य नहीं यह तो अदृश्यम् है। जो प्रेम आकर्षण से पैदा होता है। या जो सुख की कामना लिए होता है। वह प्रेम नहीं है। ऐसे प्रेम की कोई लंबी उम्र नहीं होती है। अज्ञानता या सम्मोहन के फलस्वरूप जन्म लेने वाला इस तरह का प्रेम पानी के बुलबुले के समान क्षणिकमात्र होता है। इस प्रकार के प्रेम से मोह भी जल्द भंग हो जाता है। यह दीपक की लौ की तरह झर झर करने लगता है। और अंत में बुझ जाता है। मन में अनावश्यक भय, अनिश्चिता का माहौल, असुरक्षा और उदासी को बढ़ाने का कार्य करता है। जिस प्रेम की प्राप्ति सुख- सुविधा, धन दौलत, इच्छापूर्ति भाव के कारण होती है। वह आनंददायी नहीं निरुत्साही होता है। बात संभवत: तुम्हे बुरी लगे। पर जिस प्रेम की पराकाष्ठा की उम्मीद इस साप्ताहिक प्रेमोत्सव के दौरान में जाती है। वह प्रेम नहीं वासना का जाल है। प्रेम और वासना का अंतर जानना है तो यह भी सुनो! प्रेम और वासना में वही अंतर है जो कंचन और कांच में है। प्रेम अभिराम (सुंदर) तो हो सकता है पर अविराम(लगातार) नहीं। प्रेम अवलंब (सहारा) तो हो सकता है पर अविलंब (झट से) नहीं। प्रेम का परिणाम(फल)तो हो सकता है पर परिमाण नहीं। इसलिए किसी के बाहरी स्वरूप को देखकर उसके बारे में जल्दबाजी में सोचना या उसके व्यक्तित्व का आकलन करना उपयुक्त नहीं है। क्योंकि कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है। अते, हे जानकी! रोज(गुलाब) देना है तो अपने जनक(पिता)को दो। जिसकी बदौलत तुम्हारा संसार में आगमन हुआ। हे मनोहर! तुम्हे चॉकलेट ही देनी है तो अपनी मनोहरा जननी को दो। जिसने तुम्हें नौ माह पेट में रखा। लाख कष्ट सहे पर उफ तक नहीं की। यहां तक कि तुम्हें जन्म देते समय दूसरा जन्म भी उसे लेना पड़ा। प्रपोज करने का अवसर तो किसी और को देने की सोचना भी नहीं। प्रपोज के बहाने भेड़िए खाल नोचने को तैयार बैठे है। ऐसे में खुद से खुद को कामयाब होने का प्रपोज करो। टेडी देना है तो स्वयं से अनुपम कोई नहीं हो सकता। क्योंकि नटखट तो तुम ही हो। कब रूठ जाओ, कब मन जाओ पता ही नहीं चलता।

प्रोमिस अपनी बहन से उसकी सदा संभाल का करो। ताकि कोई आवारा वेलेंटाइन के बहाने उसकी अस्मिता से खिलवाड़ न कर सके। हग उस भाई को करो जो ढाल की तरह हर समय मौजूद हो। किस करने का वास्तविक हक तो माता-पिता को है। दिखावे की राह छोड़ कामयाबी की राह पकड़ो ताकि अपने आप को गौरवान्वित मान तुम्हारा ललाट चूम सके।

अवैध प्रवासियों की बेहूदा तरीके से वापसी जुड़े सवाल

ललित गर्ग

डंकी रूट यानी गैरकानूनी तरीके से अमेरिका गये करीब 200 भारतीयों को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस अशुभता एवं अमानवीयता तरीके से अपने सैनिक विमान से बलपूर्वक भारत भेजा है, उससे अनेक प्रश्न खड़े हुए हैं। बेहतर भविष्य की तलाश में आए अवैध प्रवासियों को बेहूदा तरीके से खदेड़ना जाना विडम्बनापूर्ण एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे विश्व को लोकतांत्रिक मूल्यों एवं मानव अधिकारों की शक्षीख देने वाले अमेरिका ने जिस तरीके से विभिन्न देशों के कथित अवैध प्रवासियों को उनके देश भेजने की कार्रवाई की है, उस पर अनेक देशों ने आपत्ति जताई है। भले ही भारत ने इसे सुदृढ़ बनाने से पहलेघ कारते हुए राजनीतिक कूटनीति की दृष्टि से ठीक किया हो, लेकिन भारत लौटे अप्रवासियों की चिन्ता एवं दर्द को समझना भारत-सरकार की प्राथमिकता बननी चाहिए।

सुनहरे सपनों की आस में जीवनभर की पूंजी दांव पर लगाकर व एजेंटों को लाखों रुपये लुटाकर अमेरिका पहुंचे युवाओं ने सपने में नहीं सोचा होगा कि उन्हें अपराधियों की तरह वापस उनके देश भेजा जाएगा। ये हमारे नीति-नियंताओं की विफलता एवं विदेश नीति की नाकामी तो है ही, दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश भारत के साथ ऐसा व्यवहार अमेरिका के अहंकारी एवं संकीर्णतावादी सोच को भी दर्शा रहा है। अवैध प्रवासियों को उचित तरीकों से पहचान कर उन्हें उनके देशों को वापस भेजा जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भारत का इस मामले में शुरू से सहयोगात्मक रुख रहा है। लेकिन एक जायज सवाल वापसी के तौर-तरीके को लेकर उठना असंगत नहीं कहा जा सकता है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पूर्व जबरन की गई अवैध प्रवासी भारतीयों की निर्वासन उड़ान विसंगतियों व विडंबनाओं की ही द्योतक है। हालांकि, भारत ने कूटनीतिक प्रयासों से अवैध अप्रवासन पर समयानुकूल निर्णय लेकर दोनों देशों में संबंध सामान्य बनाने के प्रयास को गलत नहीं कहा जा सकता। गलत तरीकों से अमेरिका में आये लोगों को उनके देश का रास्ता दिखाना भी गलत नहीं कहा जासकता, लेकिन जिस तौर-तरीके से यह कार्रवाई की गयी है, उस पर प्रश्न टंकने स्वाभाविक है। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब अवैध प्रवासी भारतीय वापस भेजे गए हों। लेकिन इस बार कई ऐसी बातें हैं, जो इसे अतीत की ऐसी घटनाओं से अलग एवं चर्चा का विषय बनाती हैं। दरअसल, अमेरिका की हालिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमीनी स्तर पर बेहतर कूटनीतिक प्रयास करते हुए ट्रंप प्रशासन को इस बात को लेकर आश्वस्त किया कि भारत अपने भटके हुए नागरिकों की वैध वापसी के लिये तैयार है। निस्संदेह, भारत ने समझदारी से टकराव टालने का सार्थक प्रयास किया ताकि मोदी-ट्रंप की मुलाकात से पहले दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट न घुले। निश्चय ही हठी, अहंकारी एवं तुनक मिजाज ट्रंप व उनके प्रशासन से इस मुद्दे पर अड़ने से दोनों देशों के संबंधों के आहत होने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। हमारे देश के युवा अमीर देशों में पलायन करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाते रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या गरीबी से छुटकारा पाने वालों एवं आकांक्षाओं से भी जुड़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही विदेश में निम्न-स्तरीय नौकरियां मिले लेकिन बेहतर वेतन के लोभ में युवा ऐसी नौकरियां करते हैं। भारत में बेरोजगारी का आलम यह है कि कुछ हजार कर्मियों की भर्ती के लिये लाखों से भी अधिक युवा-प्रार्थी आवेदन करते हैं। थक-हारकर ऐसी एवं अन्य नौकरियों के लिये कोशिशों में नाकाम रहने वाले युवा विदेशों की ओर पलायन करते हैं। कई लोगों की राय में अमेरिका में होने वाली अच्छी कमाई डंकी रूट की जोखिमों, परेशानियों, अपमान एवं कानूनी भय की भरपाई कर देती है। कई परिवारों ने कहा कि उनके बेटे और भतीजे हर महीने कम से कम दो लाख रुपये घर भेजते हैं।

शख्सियत

बढ़ता राजस्थान

निष्ठा नारंग
(सामाजिक कार्यकर्ता)

नमस्कार साथियों हमारी आज की शख्सियत कॉलम की स्टार हैं निष्ठा नारंग जो न केवल एक उत्कृष्ट प्रोजेक्ट मैनेजर हैं बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता और मॉडल के रूप में भी जानी जाती हैं। एक मिडिल क्लास परिवार से आने वाली और अपनी मां के अटूट समर्थन के साथ, निष्ठा ने अपनी यात्रा की शुरुआत 18 साल की उम्र में जोधपुर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में बतौर सबसे युवा जर्मन टीजीटी ट्रेड ग्रेजुएट टीचर के रूप में की। अपनी पढ़ाई और काम के साथ, निष्ठा ने मॉडलिंग में अपने सपने को पूरा किया और अब नए टैलेंट को इस क्षेत्र में गाइड करती हैं। 8 वर्षों तक जर्मन मल्टीनेशनल कंपनियों में प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम करने के बादए निष्ठा ने अपने करियर को एक नई दिशा दी और पिछले 5 सालों से सामाजिक सेवा में जुट गईं। सरकारी स्कूलों में जर्मन भाषा सिखाने और छात्रों को करियर गाइडेंस देने के उनके प्रयासों ने न केवल कई युवाओं को नौकरी के अवसर दिलाए बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाया। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम करते हुए विभिन्न एनजीओ के साथ जुड़कर अपने अनुभव साझा किए।

15 अगस्त 2024 को, निष्ठा राजस्थान से माय भारत पहल के तहत चुनी गईं और दिल्ली के लाल किले पर पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। यह उपलब्धि उनकी मेहनत और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आज निष्ठा एक फ्रैलांस प्रोजेक्ट मैनेजर रूप में जमीनी स्तर पर बदलाव लाने में जुटी हुई हैं। उनके काम को न केवल अलवर के कलेक्टर द्वारा प्रशस्ति पत्र के रूप में सराहा गया, बल्कि उन्हें रोटरी क्लब और अन्य प्रतिष्ठित मंचों पर सम्मानित भी किया गया। निष्ठा की कहानी इस बात का प्रमाण है कि अगर सपने बड़े हों और समर्पण सच्चा हो, तो कोई भी बाधा सफलता की राह में आड़े नहीं आ सकती। उनकी यात्रा लाखों युवाओं और महिलाओं के लिए प्रेरणा बन रही है।

2025_037

बढ़ता राजस्थान

Sudoku

	6	4	2			3	7	
			1		4	9		
9		2			5	8	4	
4	5	1					3	
	9	6	5				8	4
7		8			6		2	
8			4	5	1		6	
6	2		3		9	4	1	7
	4		6	2		5		

Ans_2025_036

6	1	8	7	5	9	2	3	4
4	5	3	1	2	8	6	7	9
2	9	7	4	3	6	8	5	1
3	7	2	9	6	1	4	8	5
1	8	5	2	7	4	9	6	3
9	4	6	3	8	5	1	2	7
5	2	9	6	1	3	7	4	8
7	3	4	8	9	2	5	1	6
8	6	1	5	4	7	3	9	2

कैसे खेलें

वर्ग को 1 से 9 तक अंकों से ऐसे भरे कि आड़ी व खड़ी पंक्ति के साथ ही 3 गुणा 3 के बॉक्स में 1 से 9 तक अंक आएं। कोई अंक दुबारा नहीं आए।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,हवामहल रोड खातूवाला,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतिक्षा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-मनुजा पठान*। प्रधान संपादक-राम विलास विजयवर्गीय मो.न. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक मो.नं.9414823448 अलवर कार्यालय-मेहताब सिंह का नोहरा,अलवर मो.नं. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.नं.7023350734। ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। शुक्रवार, 7 फरवरी 2025

तालमेल से बनेगी बात

UGC कानूनों के मसौदे के विरोध में पांच राज्य सरकारों का एक साथ सामने आना कई सवाल खड़े करता है। हालांकि इन पांचों राज्यों में विपक्षी दलों का शासन है। ऐसे संकेत भी हैं कि भले इनके साथ एक मंच पर न आए हों, लेकिन कई अन्य राज्य भी इस मसौदे से असहमति रखते हैं।

राजनीतिक विभाजन | अगर यह मान लिया जाए कि इस मामले में राजनीति की प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका होगी तो भी यूनिवर्सिटियों के संचालन, वाइस चांसलरों (VC) की चयन प्रक्रिया और असिस्टेंट प्रफेसरों की नियुक्ति के लिए पात्रता जैसे मसलों पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजनीतिक विभाजन गंभीर मसला है। केंद्र और राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकारों के बावजूद अगर पहले इस तरह का विभाजन नहीं दिखता था और अब दिख रहा है तो साफ है कि किसी न किसी स्तर पर ऐसी गड़बड़ी आई है या आ रही है जो पहले नहीं थी।

ड्राफ्ट रूल्स का विरोध

राज्यों की भूमिका | इन राज्यों की शिकायतों का जहां तक सवाल है तो ऐसे मामलों पर चलताऊ ढंग से कोई निष्कर्ष निकाल लेना सही नहीं होगा। लेकिन अगर राज्य सरकारों को VC के चयन में अपनी भूमिका खत्म किए जाने पर एतराज है तो उनकी आपत्ति को एकबारगी खारिज नहीं किया जा सकता। शिक्षा आज भी समवर्ती सूची में है। ऐसे में इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि राज्यों की भूमिका के लिए पर्याप्त गुंजाइश बनी रहे।

राज्यपालों की अति-सक्रियता | केंद्र और राज्य सरकारों के रिश्तों में अगर हाल के वर्षों में तनाव बढ़ा है तो उसकी एक वजह खासकर विपक्ष शासित राज्यों में राज्यपालों की अति-सक्रियता भी है। इससे इन राज्य सरकारों के बीच ऐसा संदेह बना है कि केंद्र राज्यपालों के जरिए उनके अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी करना चाहता है। बहुत संभव है कि UGC नियमों के मसौदे पर मतभेदों के ऐसा रूप लेने के पीछे भी इन संदेहों का हाथ हो।

सामंजस्य जरूरी है | कारण चाहे जो भी हो, केंद्र और राज्यों के बीच इस तरह के संदेहों का कोई औचित्य नहीं बनता। इससे संविधान के संघीय ढांचे को भी देर-सबेर नुकसान पहुंचने का अंदेशा रहता है। बेहतर होगा इन मतभेदों को उपयुक्त मंचों पर और सामंजस्यपूर्ण तरीके से सुलझा लिया जाए।

रोज़-ब-रोज़

प्रकृति के अधिकार

शैलेंद्र पांडेय

न्यूजीलैंड का माउंट Taranaki अब आजाद है, बिल्कुल किसी इंसान की तरह। इंसानों जैसे उसके भी अधिकार, शक्तियां, कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं। Taranaki पहाड़ को पूर्वज मानने वाली न्यूजीलैंड की मूल जनजातियों ने इस दिन के लिए लंबा संघर्ष किया था। वे चाहती थीं कि उनके पहाड़ को बस पत्थरों का ढेर न समझा जाए। अब उन्हें अपना पूर्वज वापस मिल चुका है। बाहरी हस्तक्षेप कम होगा, तो उम्मीद है कि प्रकृति के लिए बेहतर नतीजे आएंगे। भारत में भी 2017 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा, यमुना नदियों और गंगोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर को जीवित प्राणी मानते हुए सारे कानूनी अधिकार देने का फैसला किया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। राज्य सरकार का कहना था कि इसमें व्यावहारिक दिक्कतें हैं।

प्रकृति केवल संसाधन नहीं, जिससे बस लिया जाता रहे, उसका भी अपना अस्तित्व सम्मान और अधिकार है। नदियां, पहाड़ और जंगल कभी बोलते नहीं, मगर इसका यह मतलब नहीं कि उनकी कोई भाषा नहीं होती। लंबे अरसे से वे हमें सचेत कर रहे हैं कि पर्यावरण को लेकर हम गलत दिशा में जा रहे। यह कितनी अजीब बात है कि जिस प्रकृति से ले-लेकर हम यहां तक पहुंचे, तरक्की के इस सफर में हर कदम हम उसी के अधिकारों को कुचलते रहे। और यह आज भी जारी है। सोचिए, अगर पेड़ों के पास भी जीने का अधिकार हो, अगर सारी नदियों को हक मिल जाए सम्मानपूर्वक बहने का और तालाबों को अधिकार मिल जाए अपना अस्तित्व बचाए रखने का? जब कंपनियों को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया जा सकता है, तो प्रकृति को क्यों नहीं? वैसे भी हमारी प्राचीन परंपरा और संस्कृति में इनको जीवंत माना गया है।

कुछ लोगों को लगता है कि यह सब केवल भावनात्मक विचार है और इस पर अमल करना संभव नहीं। अगर नदियों, पहाड़ों और जंगलों को कानूनी अधिकार मिलेंगे, तो उनके साथ होने वाले अपराधों की जवाबदेही कौन लेगा? यह सवाल अपनी जिम्मेदारियों से बचने का तरीका भर है। अगर हम प्रकृति के लिए अपनी जवाबदेही नहीं तय कर सकते, तो उसकी तरफ से खुद निर्णय लेना भी बंद कर दें। न्यूजीलैंड जैसे छोटे-से देश ने ऐसा कर दिखाया है, तो हम क्यों नहीं?

एकदा

घूस नहीं लूंगी

19वीं सदी में बंगाल में पहली महिला थियेटरकर्मी के तौर पर एक नाम मशहूर हुआ था- नटी बिनोदिनी उर्फ बिनोदिनी दासी। उनका जन्म एक गरीब बंगाली परिवार में हुआ था। वह वेश्या समाज से आती थीं। लेकिन उन्हें बचपन से संगीत पसंद था। उन्हीं दिनों बांग्ला थियेटर की दुनिया में बहुत बड़ा नाम था गिरीश चंद्र घोष। उन्होंने बिनोदिनी की प्रतिभा को पहचाना और उसे संवारने का काम किया। जल्दी ही बिनोदिनी बांग्ला थियेटर का अनमोल सितारा बन गईं। गिरीश चंद्र उन्हें बेटी कहकर बुलाते थे। बिनोदिनी के रूप और गुण की चर्चा पूरे कलकत्ते में होने लगी। थियेटर के शौकीन उनके दीवाने थे। एक दिन, स्टेज पर उनके शानदार प्रदर्शन के बाद नैशनल थियेटर के मालिक प्रताप जौहरी ने बेशकीमती हार भेंट की। बिनोदिनी ने उस हार को ठंडी नजरों से देखा और कोई प्रतिक्रिया नहीं दीं। 'क्या यह हार आपको पसंद नहीं?' जौहरी के इस सवाल पर बिनोदिनी का उत्तर था, 'मैं इसे नहीं ले सकती। महीने के तनख्वाह के बाद ऊपर से कोई कुछ लेता है तो वह घूस लेना है।' जौहरी ने मनाने की कोशिश नहीं छोड़ी तो उन्हें दरवाजे का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि 23 साल की उम्र में बिनोदिनी ने थियेटर छोड़ दिया। यह उनकी बदनाम गलियों में आने से पहले की घटना है। अपनी आत्मकथा 'आमार कथा' में उन्होंने लिखा है कि साजिश करके उन्हें थियेटर निकाला गया था जिसके बाद मजबूरी में वेश्या का जीवन जीना पड़ा।

Subrata Char

संकलन : **दिलीप लाल**

सितंबर 2024 तक के सालभर में अवैध रूप से US जाने की कोशिश में 90,415 भारतीय पकड़े गए

अमीर राज्यों के लोग क्यों छोड़ रहे देश

आई पी सिंह

डॉनल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद सौ से अधिक अवैध भारतीयों के पहले बैच को अमेरिका से वापस भारत भेजा गया है। इन लोगों को कमर्शल या चार्टर्ड फ्लाइट के बजाय मिलिट्री फ्लाइट से वापस भेजकर ट्रंप सरकार ने सख्त संदेश दिया है।

समृद्ध राज्यों से पलायन | जो 104 अवैध प्रवासी वापस भेजे गए, उनमें पांच राज्यों के लोग शामिल हैं। इनमें 33 गुजरात, 33 हरियाणा, 30 पंजाब और बाकी यूपी, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों से हैं। यानी जिन राज्यों के लोगों की संख्या अधिक है, वे भारत के समृद्ध राज्यों में शामिल हैं।

वजह आर्थिक नहीं | ये लोग जान जोखिम में डालने के साथ ढेरों पैसा खर्च करके डंकी रूट से वहां गए थे। भारत सरकार को इसी सवाल का जवाब तलाशना है कि आखिर वजहें क्या हैं। मसलन, पंजाब की बात करें तो वहां से ऐसा रास्ता चुनने वाले लोगों की वजह सिर्फ आर्थिक नहीं होती।

सीएम का वादा | पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया था कि उनकी सरकार वापस लौटने वाले प्रवासियों को रोजगार मुहैया कराएगी। इस तरह से वह 'रिवर्स माइग्रेशन' कराएंगे। यह वादा तीन साल पुराना है। अभी तो ट्रंप की नीतियों की वजह से 'रिवर्स माइग्रेशन' हो रहा है।

देश का नुकसान | पिछले एक दशक में बिजनेस परिवारों में युवा पीढ़ी के लोग अच्छी-खासी संख्या में जायज तरीके से विदेश गए हैं। इसके लिए सबसे लोकप्रिय रास्ता है स्टूडेंट वीजा, जिससे 'ब्रेन ड्रेन' होता है। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। इससे देश को 'उद्यमशीलता के जज्बे' के रूप में भी नुकसान हो रहा है।

- पंजाब में शुरू से ही जारी है इमिग्रेशन
- उग्रवाद के दौर में विदेश जाने वाले बढ़े
- इमिग्रेशन से डेमोग्राफी में भी बदलाव

पंजाब-गुजरात आगे | कनाडा पंजाबियों का पसंदीदा ठिकाना रहा है। वर्षों से इसके लिए स्टूडेंट वीजा का इस्तेमाल भी होता आया है। इसी तरह से गुजरातियों के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन अमेरिका रहा है। अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच मेक्सिको और कनाडा के रास्ते अवैध रूप से अमेरिका जाने की कोशिश में 90,415 भारतीय गिरफ्तार हुए थे, जिनमें आधे गुजरात से थे।

कनाडा से झटका | कनाडा जाने की ख्वाहिश रखने वाले पंजाबियों को पिछले साल एक झटका लगा, जब वहां की सरकार ने विदेशी छात्रों की सीमा तय कर दी। खैर, अमृतसर में बुधवार को जो 30 पंजाबी लौटे, उनमें से 14 दोआबा क्षेत्र के हैं, जहां से सबसे अधिक लोग विदेश गए हैं। देश के बंटवारे के बाद छोटी जोत और आर्थिक मुश्किलों की वजह से दोआबा क्षेत्र से माइग्रेशन शुरू हुआ। तब खास्तौर पर जालंधर, होशियारपुर और कपूरथला से लोग विदेश गए।

ग्रामीण क्षेत्र से माइग्रेशन | 1980-90 के अलगाववादी आंदोलन के वक्त बड़ी संख्या में राज्य से सिखों का पलायन हुआ। इन लोगों ने पुलिसिया जुल्म का हवाला देकर विदेश में शरण मांगी। 1990 के दशक की शुरुआत में उग्रवाद खत्म हो गया, लेकिन दूसरे देशों में शरणार्थी का दर्जा पाने के लिए यही बहाना चलता रहा। हालांकि, तब तक विदेश जाने की वजह पूरी तरह से आर्थिक हो चुकी थी। असल में, वक्त के साथ परिवारों के पास जमीन घटती गई। खेती में उत्पादकता भी नहीं बढ़ रही थी। इससे किसानों की परेशानी बढ़ी, इसी वजह से तब पंजाब के ग्रामीण इलाकों से माइग्रेशन बढ़ा।

बेहतर भविष्य की चाहत | पिछले एक दशक में पंजाब के शहरों से इमिग्रेशन के रूप में यह ट्रेंड बदला। इसमें हिंदुओं की संख्या अधिक थी। इस दौरान बिजनेस कम्युनिटी और वाइट कॉलर प्रफेशनल्स देश से बाहर गए। आर्थिक रूप से मजबूत दलित समुदाय के लोग और बरसों पहले दूसरे राज्यों से पंजाब आकर बसे लोग भी इसमें शामिल हो गए। दरअसल, पश्चिमी देशों में लाइफस्टाइल बेहतर है। गवर्नेंस और सोशल सिक्योरिटी भी वहां जाने वालों के लिए आकर्षण का विषय है। इसलिए पंजाब और गुजरात जैसे समृद्ध राज्य भी इस तरह के माइग्रेशन में आगे हैं।

डेमोग्राफी बदली | पंजाबियों के राज्य छोड़ने से जो जगह बनी, उसे हिमाचल, यूपी और बिहार से आने वालों ने भरा। यानी पंजाब की डेमोग्राफी में जो बदलाव आया है, उसमें भी इमिग्रेशन की बड़ी भूमिका है। साल 2011 से 2020 के बीच राज्य की सालाना आबादी की ग्रोथ 50% से अधिक कम हो गई। 2011 में जहां यह 3.2 लाख थी, वह 2020 में घटकर 1.5 लाख रह गई। पंजाब में जो भी सरकारें आईं, उन्होंने इमिग्रेशन की समस्या को खत्म करने के वादे ही किए, लेकिन बुधवार को अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंचे अमेरिकी मिलिट्री प्लेन से राज्य और केंद्र सरकारों की नींद खुल जानी चाहिए।

कुछ घंटों के निकाह को कैसे कहें जायज़

नाइश हसन

कुछ अरसा पहले हैदराबाद में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके शौहर ने कुछ दलालों की मदद से उसकी नाबालिग बेटी का ओमान निवासी 70 वर्षीय अहमद अब्दुल्लाह के साथ मुताह करा दिया। वह लड़की ओमान में फंस गई थी, जहां उसके साथ बदसलूकी हो रही थी। मुताह का यह कोई पहला या नया मामला नहीं है। 2005, 2013, 2014, 2016 के भी कई मामले अखबारों की सुर्खियां बने।

अरब के शेख | ऐसा ही एक केस है 45 वर्षीय अरब शेख रहमान इस्माइल मिर्जा अब्दुल जब्बार का। इसने हैदराबाद में एक दलाल के जरिए 13 और 14 वर्ष की दो नाबालिग लड़कियों का 25 हजार रुपये में सौदा किया और महज एक रात के लिए मुताह निकाह किया। ऐसे ही एसए हुसैन बनाम राजस्था हैदराबाद का मशहूर केस रहा है। इसमें मुताह की अवधि में ही राजस्था के पति हबीबुल्लाह की मृत्यु हो गई, तो हबीबुल्लाह के भाई ने राजस्था को पति की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाए जाने से इनकार कर दिया था। इसमें कोर्ट ने राजस्था को संपत्ति का उत्तराधिकारी घोषित किया, क्योंकि प्रतिवादी मुताह की अवधि साबित करने में नाकाम रहे।

किराए की महिला | मुताह ऐसी शादी है जिसका अंत निश्चित होता है। यह एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित रकम के बदले स्त्री व पुरुष का शारीरिक संबंध है। मुताह का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। अरबी शब्दकोश भी इसे लुत्फ, मजा या आनंद के रूप में ही परिभाषित करते हैं। मुताह में शरीक होने वाली औरत को मुस्ताजरा या किराए की महिला भी कहा जाता है।

आज भी मान्यता | मुताह अगर सिर्फ अतीत का हिस्सा होता तो आज उस पर सवाल उठाने की जरूरत न होती, क्योंकि इतिहास में महिला विरोधी तमाम घटनाएं सभी धर्मों में मौजूद रही हैं। समस्या यह है कि यह आज भी हमारे देश में विधिमान्य है। यह आज भी शिया पारिवारिक विधि का हिस्सा है। मुताह विवाह प्रस्ताव व स्वीकृति से होता है।

AI Image

#CancelPatriarchy

इसमें गवाह भी नहीं चाहिए। मुताह होते वक्त निर्धारित कालावधि तय की जाती है। इस विवाह का अंत तलाक देकर नहीं होता। निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने पर यह स्वतः समाप्त माना जाता है।

अधिकार का सवाल | मुताह पत्नी को पति की संपत्ति से कोई अधिकार नहीं मिलता। जीवन भर का मुताह भी मुताह विवाह ही माना जा सकता है, यदि इसमें सहवास की अवधि जीवन पर्यंत तक की निश्चित कर दी गई हो। इस विवाह में भी पति-पत्नी एक दूसरे के उत्तराधिकारी नहीं माने जाते। हैदराबाद, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात में आज भी काफी संख्या में अरबी, सूडानी, यमनी, ओमानी और भारत के विभिन्न हिस्सों के लोग आते हैं। वह कुछ समय के लिए तो कभी-कभी कुछ घंटों के लिए निकाह करते हैं। उसके बाद औरत को छोड़ कर चले जाते हैं। पॉक्सो कानून आने के बाद नाबालिग लड़कियों के मामले में कुछ हद तक रोक तो लगी है, लेकिन यह बंद नहीं हुआ है।

तुरंत लगे रोक | आज के दौर में स्त्री गरिमा के सवाल को धर्म की अपनी-अपनी व्याख्या और समझ के दायरे से बाहर निकाल कर देखने की जरूरत है। बात यह भी है कि धर्म का स्त्री के जीवन पर क्या प्रभाव है? इस बहस में स्त्री अस्मिता के सवाल कहां पीछे रह जाते हैं, उसे भी देखना जरूरी है। स्त्री महज आंकड़ा नहीं है, जिसे कम या ज्यादा बताकर उसकी पीड़ा को कम ज्यादा आंका जाए। संपूर्ण भारत में न सही, आज भी भारत के कई हिस्सों में ऐसी परंपराएं चलन में हैं, जिन पर सवाल उठना लाजमी है।

BJP के नए प्रेज़िडेंट में चाहिए ये ख़ूबी

पूनम पाण्डे

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग बुधवार को हो गई, लेकिन छोटे-बड़े चुनाव आगे भी जारी रहेंगे। BJP सहित दूसरे राजनीतिक दल अब बिहार विधानसभा चुनाव पर फोकस करेंगे। इससे पहले छत्तीसगढ़ और हरियाणा निकाय चुनाव के लिए भी वोटिंग होनी है। ध्यान रहे, BJP को जनवरी तक ही अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लेना था, लेकिन कहीं विधानसभा चुनाव और कहीं निकाय चुनाव की वजह से मंडल और प्रदेश स्तर के चुनाव में देरी हुई। BJP के संविधान के मुताबिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए कम से कम 50% राज्य इकाइयों में संगठन के चुनाव पूरे होने जरूरी हैं। अभी कई राज्यों में BJP के संगठन की चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। जब यह कम से कम 50% पूरी होगी, तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा।

विशुद्ध राजनीति
कसौटी

चुनाव-दर-चुनाव

छत्तीसगढ़ में 11 फरवरी को निकाय चुनाव की वोटिंग होनी है। BJP का स्थानीय संगठन उसी में व्यस्त है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में संगठन का चुनाव होगा। हरियाणा में भी अभी BJP संगठन के चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। वहां तो पार्टी का सदस्यता अभियान ही देर से शुरू हुआ और देर तक चला। विधानसभा चुनाव की वजह से सदस्यता अभियान में देरी हुई। अब वहां 2 मार्च को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी। उसके बाद ही हरियाणा में पार्टी संगठन के चुनाव पर काम होगा। मध्य प्रदेश में BJP ने संगठन चुनाव के तहत सभी जिला अध्यक्षों की घोषणा तो कर दी है, लेकिन अभी वहां भी प्रदेश अध्यक्ष तय होना बाकी है। उत्तर प्रदेश में भी अभी संगठन चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है।

वैसे तो BJP में जब भी पुराने अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म होता है तो नए अध्यक्ष को लेकर कयासबाजी तेज हो जाती है। लेकिन इस बार यह चुनाव कुछ अलग है क्योंकि यह दो बार लोकसभा में पार्टी को मिले लगातार बहुमत के बाद NDA सरकार के साए में हो रहा है। लोकसभा चुनाव के वक्त कहा गया कि BJP और उसके वैचारिक संगठन RSS के बीच सबकुछ ठीक नहीं है और संघ के स्वयंसेवकों ने पहले की तरह ग्राउंड पर काम नहीं किया। चुनाव के बाद भी जब केंद्र में NDA सरकार बन गई, तब संघ प्रमुख मोहन भागवत के कुछ बयानों को BJP और संघ के रिश्तों से जोड़कर देखा गया। हालांकि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में RSS काफी सक्रिय रहा। इसी तरह दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी संघ पूरी तरह सक्रिय रहा। इस बार कहा जा रहा है कि BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में संघ की अहम भूमिका होगी और संघ बैकग्राउंड वाले किसी नेता के अध्यक्ष बनने के चांस ज्यादा हैं। संघ से जुड़े एक नेता ने अनौपचारिक बातचीत में बताया कि लोकसभा चुनाव के बाद पाया गया कि कई राज्यों में जहां पहले संगठन मजबूत हुआ करता था, वहां यह काफी कमजोर हुआ है। इसलिए अब संघ संगठन यानी BJP में अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने देगा।

दिल्ली और बिहार चुनाव के बीच में निकाय चुनाव और संगठन चुनाव में भी BJP बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर फैसला ले सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल में जिस तरह BJP को बढ़त दिख रही है उसके बाद तो सीएम कौन होगा, इसे लेकर पार्टी में चर्चाएं चलने लगी हैं। BJP के एक नेता ने अनौपचारिक बातचीत में कहा, लिस्ट देख लो कि कौन-कौन पूर्वांचली नेता हैं। BJP अगर दिल्ली में सरकार बनाती है तो बिहार चुनाव से पहले वह दिल्ली में पूर्वांचली नेता को कोई बड़ा पद देकर बिहार तक संदेश भेजने की कोशिश कर सकती है।

विन-विन सिचुएशन!

नीतीश अब पीएम पद की दौड़ से बाहर हैं और बिहार में ही उन्हें राजनीति करनी है। नीतीश के करीबी कहते हैं कि उनको सरकार चलाने में सहयोगियों की टोकाटाकी नहीं चाहिए थी और BJP ने उन्हें फ्री हैंड दिया हुआ है। उसे मालूम है कि बिहार में उसके पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो सभी कम्युनिटी में स्वीकार्य हो। नीतीश खुद तो OBC से हैं, लेकिन कानून-व्यवस्था के नाम पर सवर्णों में भी स्वीकार्य हैं। साथ ही, महिला वोटर्स में नीतीश की पकड़ मजबूत है। BJP के नेता अनौपचारिक बातचीत में कहते हैं कि नीतीश से BJP को कोई खतरा नहीं है। दोनों का साथ रहना दोनों के लिए ही विन-विन सिचुएशन है।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ विदेश का आकर्षण

6 फरवरी का संपादकीय 'बड़ी चुनौती' पढ़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के आदेश पर 104 अवैध प्रवासियों को सैनिक विमान से भारत वापस भेज दिया गया। ट्रंप प्रशासन सभी अवैध प्रवासियों को निष्कासित करने की नीति पर अडिग है, चाहे वे किसी भी देश से हों। जो लोग तय समय सीमा के बाद अवैध रूप से वहां रह रहे हैं, उन्हें वापस भेजना गलत नहीं है। भारतीय युवा अपने टैलंट के दम पर अमेरिका में नौकरी करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने देश में भी अच्छे अवसर पा सकते हैं। बावजूद इसके, विदेश जाकर काम करने में रुचि तेजी से बढ़ रही है। इस चक्कर में वहां सामने आने वाली चुनौतियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जबकि अपने देश में भी कई विकल्प मौजूद हैं। जाने से पहले वहां के कानूनी और व्यावहारिक पहलुओं को गंभीरता से समझना जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

इन्द्र सिंह धिगान, किंग्जवे कैंप

■ मौसम की परवाह

सर्दी के जाने और वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दिन में गर्मी और सुबह-शाम हल्की ठंडक के कारण खांसी, जुकाम और बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं। मौसम परिवर्तन के कारण इम्युन सिस्टम कमजोर पड़ रहा है, जिससे गले में खराश, बुखार और एलर्जी जैसी समस्याएं हो रही हैं। ऐसे में सेहत को बनाए रखने के लिए सावधानी जरूरी है। ठंडी और गर्म चीजों के इस्तेमाल से बचें। पर्याप्त पानी पिएं। रात में ठंडी हवा चलती है और दिन थोड़ा गर्म होता है। इसलिए लापरवाही बरतने से बचें। सही देखभाल और सतर्कता बरतना ही उपाय है।

डॉ. मनीष जैन, ईमेल से

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

वोटिंग में दिल्ली फर्स्ट क्लास से पास – एक खबर
– क्या नई बनने वाली सरकार भी इतने नंबर बटोर पाएगी!

राजीव सिंघल

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
hindi.speakingtree.in

सीमित साधनों में अधिक ख़ुशियां तलाशना जानें

निर्मल जैन

सभी खुश रहना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं। लेकिन इच्छाओं के दुखों की लदी गठरी हमें ऐसा करने की अनुमति ही नहीं देती। भारी-भरकम कामनाओं के नीचे इतने दबे होते हैं कि मुस्कुराने की बात तो दूर जीने के लिए सांसें भी रुक जाती हैं। जिस दिन वह गठरी उतार देंगे, खुशियां हमारे आसपास होंगी और हम संसार के सबसे धनवान व्यक्ति होंगे। हमारे पास जो है उसमें हमें कोई खुशी नहीं, लेकिन जो नहीं है उसका दुख चौबीस घंटे सालता रहता है। यही सोच हमें कमजोर कर देती है। नहीं तो प्रकृति तो इतनी कृपालु है कि कोई भी इंसान इतना वंचित नहीं होता कि उसके पास खुश रहने की कोई वजह न हो।

मुश्किल तो यह है कि हमने अपने सारे सुखों का ताना-बाना सुख-सुविधाओं वाली चीजों को बना लिया है। भोगों को इतना भोगा की खुद को भोग बना डाला। दिल और दिमाग को भी डस्टबिन का रूप दे डाला। जो कुछ कूड़ा-कचरा सुनाई दे रहा है, दिख रहा है सबको अंदर भर लो। हमारी मनोवृति कुछ ऐसी बन गई है कि हमें सब कुछ चाहिए तभी हम खुशी का अनुभव करेंगे। अगर इसका केवल हम क्रम बदल दें, यानी जितना भी मिले हम तो खुश रहेंगे ही, तो खुशी अपने आप बरसनी शुरू हो जाएगी।

हम निर्धन तब नहीं होते, जब हमारे पास कुछ नहीं रहता। बल्कि तब भी हो जाते हैं जब लोग हमसे मांगना बंद कर देते हैं। चाहे वह प्रेम हो, समय हो या सहायता हो। यदि सामर्थ्य हो और किसी जरूरतमंद को हम न दे पाएं, तो भले ही भंडार भरा हो, लेकिन मन का कोई न कोई कोना खाली है। देने की क्षमता सामर्थ्य से नहीं, बल्कि अपनी उदारता से आती है।

विवेकवान होकर भी हम इन कामनाओं के बोझ से लगे फंदे क्या कर रहे हैं? इतना तो हमें जीना भी नहीं है जितना हर रोज मर रहे हैं। जहां कहीं थोड़ी सी कामयाबी मिली, संतोष मिला उनका आनंद न लेकर हम और पाने की तलाश में हांफते-दौड़ते चले जाते हैं। वास्तविक सुख का दूसरा नाम है, अनंत चाहत और सीमित संसाधनों में तालमेल बना कर रखना। लेकिन स्वामित्व की आकांक्षा इतनी गहरी पैठ गई है कि हम वस्तुओं के मालिक बनने में इतना अधिक रस लेने लगते हैं जितना कभी हमने अपने स्वयं के मालिक बनने में नहीं लिया।

जैसे-जैसे धन बढ़ता है गिनती में शून्य बढ़ने के साथ मन के अंदर भी शून्यता बढ़ती जाती है। इसी से उपजा अविवेक सफलता को असफलता में बदल देता है। तब हम अपने पुरुषार्थ या भाग्य को कोसने लगते हैं। लेकिन यह नहीं सोचते की क्या कभी कोई पूरी तरह से तृप्त हुआ भी है? अंदर की खुशी बड़ी महंगी होती है लेकिन आश्चर्यजनक यह भी है कि इसे वही खरीद पाते हैं जिनके पास खरीदने के लिए कुछ नहीं होता।

हक़ इस अंक : ऐ. ए.डब्ल्यू.ए.आर्मीज़ क्वार्टर्स / लिबिया-अमुक्ति के बिना संयुक्त राष्ट्रमिशन पुनर्स्थापना सुरक्षा; सांस्कृतिक / सामाजिकताएँ बैंक; ओलंपिक एनर्ज़ ब्लम्पी विमोचन के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा; 2 महाकुम्भ स्नान कर्म, नई दिल्ली-110002 में प्रकाशित तथा **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, भारत** से, **जीवनीय क्षेत्र परिक्षण** और ग्रामीण मेला 2-8, सेक्टर 36-ए, हरियाणा से, ईलेक्ट्रिक मीडिया सोसायटी, नवीकरण, सोनीपत से मुद्रित। फोन : 2340202040 फैक्स: 2340202041, मैनेजिंग एडीटर : गुरुग्राम/नोएडा रोड, पुष्पेंद्र-2.02.2011 जिला केंद्र मुख्य : 1 ब. प्रति कॉपी: नेपाल में कुल मूल्य : कोलकाता में रुपीज़ : रिपोर्ट 5 ब., दिल्ली : रिपोर्ट 6 ब.
कोलकाता (रिपोर्ट संख्या 2) : आर्थिक संपदा (इस अंक में प्रकाशित समाज सरकारों के कारण पूर्ण संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)